



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 29, 2018/कार्तिक 7, 1940

No. 348]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 29, 2018/KARTIKA 7, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2018

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय : सऊदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नॉर्मल-बुटानॉल अथवा "एन-बुटाइल एल्कोहॉल" के आयात के संबंध में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय में 2018 की रिट याचिका सं. 7671 (आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लि. बनाम भारत संघ), पाटनरोधी जांच में जारी 28 नवंबर, 2017 के अंतिम जांच परिणाम में 31 जुलाई, 2018 का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश - पुनर्निर्धारण।

फा. सं. 14/20/2016-डीजीएडी.—उपर्युक्त विषय और समय-समय पर यथासीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली (जिसे आगे यहां नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,

क. पृष्ठभूमि

(क) उपर्युक्त नियमावली के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे यहां "प्राधिकारी" कहा गया है) को संबद्ध सामानों के घरेलू उद्योग के रूप में आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लि. ("एपीएल") (जिसे यहां आगे "याचिकाकर्ता" कहा गया है) से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें सऊदी अरब (जिसे यहां आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "नॉर्मल बुटानॉल" अथवा "एन-बुटाइल एल्कोहॉल" (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" अथवा "एनबीए" कहा गया है) का आरोप लगाया गया है और जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है तथा जिसमें संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) प्राधिकारी ने उपर्युक्त आवेदन के आधार पर 02.09.2016 को संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के विरुद्ध जांच शुरू की।

- (ग) विस्तृत जांच के बाद प्राधिकारी ने 28 नवंबर, 2017 की अपनी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/20/2016-डीजीएडी द्वारा जांच को रद्द करने की सिफारिश की।
- (घ) उपर्युक्त अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी की सिफारिशों से दुखी होकर इस जांच में घरेलू उद्योग मैसर्स आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लि. ने तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद के उच्च न्यायालय में रिट याचिका (2018 की रिट याचिका सं. 7671) दायर की।
- (ङ) माननीय उच्च न्यायालय ने स्कीम और 28 नवंबर, 2017 के अंतिम जांच परिणाम के 1995 के नियमों की संरचना को ध्यान में रखते हुए तथा यह कार्य शीघ्रता से पूरा करने के लिए और 31 जुलाई, 2018 के अंतिम आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो माह में नए सिरे से विचार करने के लिए मामला निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापस भेजते हुए 31 जुलाई, 2018 को आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लि. बनाम भारत संघ (2018 की रिट याचिका सं. 7671) में अंतिम आदेश पारित किए। प्राधिकारी को 31 अगस्त, 2018 को अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई, यद्यपि, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर पहले भी उपलब्ध था।
- (च) प्राधिकारी ने इन मुद्दों पर 26 सितंबर, 2018 को एक प्रकटन विवरण जारी किया जिनमें माननीय उच्च न्यायालय ने 28 नवंबर, 2017 के अंतिम जांच परिणाम पर पुनः विचार करने का निर्देश दिया था।
- (छ) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित 31 जुलाई, 2018 के आदेश के संगत उद्धरण निम्नलिखित हैं:

- (i) "उसका नियम 4, जैसा कि पहले ही कहा गया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी के दायित्वों को निर्धारित करता है और अनंतिम अथवा अन्यथा अपने जांच परिणाम केवल क्षति के बारे में ही नहीं बल्कि भारत में स्थापित किसी उद्योग को क्षति के खतरे के संबंध में भी अथवा भारत में उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी के संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्तुत करने की अपेक्षा रखता है जो कि विनिर्दिष्ट देशों से समान वस्तु के आयातों के परिणामस्वरूप हुए हों, अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी यह मानने में पूर्णतः औचित्यपूर्ण नहीं थे कि सऊदी अरब से उत्पाद के आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को संभावित क्षति के खतरे अथवा वास्तविक मंदी की जांच करना उसका लिए अधिदेश नहीं था। 1995 की नियमावली के नियम 5(2) में केवल जहां लागू हो, वहां क्षति निर्धारित करने के लिए आवेदन की अपेक्षा है, परंतु वह नियम 4(1)(ग) के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी के दायित्व को सीमित नहीं करेगा। नियम 11 भी इसे स्पष्ट करता है क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी को उसके तहत जांच परिणाम रिकार्ड करना अपेक्षित होता है कि भारत में समान वस्तु के आयातकों से भारत में स्थापित किसी उद्योग को क्षति होती है अथवा वास्तविक क्षति का खतरा होता है अथवा भारत में किसी उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी होती है। यह नियम "क्षति निर्धारण" में है और इसीलिए यह स्पष्ट करता है कि नियम 5(2) के तहत घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आवेदन की विषय वस्तु तक जांच का क्षेत्र नहीं बताया जाता अथवा प्रतिबंधित नहीं होता, (उल्लिखित आदेश की प्रमाणित प्रति का पृष्ठ 20 एवं 21 देखें)।
- (ii) अतः भारत में किसी उद्योग की स्थापना को कई संभावित क्षति का खतरा अथवा वास्तविक मंदी की जांच करने के लिए इस मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी का इंकार करना सांविधिक अधिदेश की कमी में आता है। इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी का विशिष्ट निष्कर्ष यह था कि जांच को 1995 की नियमावली के नियम 14(ख) के अनुसार रद्द किया जाना था। उपर्युक्त प्रावधान से यह सिद्ध है कि यह केवल तभी है जब प्राधिकारी को पाटन का पर्याप्त साक्ष्य न मिले अथवा जांच को जारी रखने के लिए औचित्य बनाने हेतु क्षति न हो जिससे यह रद्द किया जा सके। इस मामले में, जैसे कि पहले ही ऊपर नोट किया गया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड किए गए जांच परिणामों में सऊदी अरब से निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा तीन माह के समय के भीतर पाटन के पर्याप्त साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं और उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति भी दर्शाई गई, अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच रद्द करने के लिए औचित्य बनाने हेतु इस कारण को नहीं ले पाए। वस्तुतः नियम 14 में किसी भी खंड, जो जांच को रद्द करने के संबंध में हो, में आवेदन नहीं था जिससे प्राधिकारी इस प्रकार का कदम उठा सकते थे। (उल्लिखित आदेश की प्रमाणित प्रति का पृष्ठ 21 और 22 देखें)।
- (iii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह पाया कि इसी प्रकार का उत्पाद भारत को निर्यात करने वाले कई अन्य देशों को पाटनरोधी उपायों के अधीन रखा गया था, सऊदी अरब से निर्यातकों/उत्पादकों को इन्हीं पाटनरोधी उपायों के अधीन रखे बिना अनुमति देना, यहां तक कि यद्यपि तीन माह के समय के भीतर उनके क्रियाकलाप घरेलू बाजार को आक्रामक रूप से लेना स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, स्पष्ट रूप से आवश्यक नहीं था। यद्यपि, निर्दिष्ट प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणाम न देने और केवल इस आधार पर सिफारिश करने के लिए एक प्रति हलफनामा रखा गया था कि पाटन जांच की अवधि के दौरान तीन माह के लिए हुआ,

उपयुक्त निर्धारित अंतिम जांच परिणाम स्पष्ट रूप से विरोधाभास दर्शाते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि 1995 की नियमावली उसके बावजूद जांच की अवधि बढ़ाने का विशेष रूप से प्रावधान करती है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह विस्तार मांगना उपयुक्त नहीं समझा (उल्लिखित आदेश की प्रमाणित प्रति का पृष्ठ 22 और 23)।

- (iv) यद्यपि, उत्तरदाताओं के लिए पेश होने वाले भारत के सहायक विद्वान सॉलिसिटर जनरल यह तर्क देंगे कि 1995 की नियमावली का अनुबंध-1 यह दर्शाएगा कि कम से कम 6 माह की बिक्री ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है, हमारा यह मत है कि इस तर्क को गलत समझा गया है। अनुबंध-1 सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण से संबंधित है और इन तीनों पहलुओं के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी को सऊदी अरब के निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य, निर्यात विवरण और पाटन मार्जिन निर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं थी। इसके अतिरिक्त, अनुबंध-1 में खंड (2) उन निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए तीसरे देश को अथवा उनके घरेलू बाजार में समान उत्पाद की, की गई बिक्री के संबंध में 6 माह की अवधि बताता है और इससे अधिक नहीं। अतः यह खंड जांच की अवधि के दौरान तीन माह से अधिक में होने वाले पाटन की कोई आवश्यकता नहीं दर्शाता, जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने अंतिम निष्कर्ष में गलत माना गया है। विदेशों से निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा समान उत्पादों के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति निर्धारित करने अथवा उसका मूल्यांकन करने के लिए 1995 की नियमावली के संदर्भ में अपेक्षित किसी लंबी अवधि का उल्लेख नहीं है, परंतु निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपनी जांच को समाप्त करने के लिए औचित्य बनाने हेतु जनवरी से मार्च, 2016 की तीन माह की अवधि को जोड़ा जो कि पूर्णतः असंधारणीय है। (उल्लिखित आदेश की प्रमाणित प्रति का पृष्ठ 23 देखें)।

(ज) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का प्रचालनात्मक भाग निम्नलिखित है:

"उपयुक्त विश्लेषण पर यह न्यायालय यह पाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी सऊदी अरब से निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा समान उत्पादों के पाटन से घरेलू उद्योग को हुई क्षति के समर्थन में जांच परिणाम रिकार्ड करने पर उस नोट को लेने में विफल रहे और जब वे अंतिम सिफारिश के स्तर पर आए तो आश्चर्यजनक रूप से पक्ष परिवर्तन किया। यह उनके गलत माने गए विचार के आधार पर था कि पाटन का तीन माह का समय जांच परिणाम रिकार्ड करने के लिए अपर्याप्त था। जैसा कि हमने पहले ही नोट किया है, 1995 की नियमावली में ऐसा कोई अधिदेश नहीं है, 28.11.2017 के अंतिम जांच परिणाम अलग किए जाते हैं और यह मामला स्कीम तथा 1995 की नियमावली के ढांचे को और ऊपर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से विचार करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजा जाता है। यह कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाएगा और किसी भी दशा में इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दो माह से अधिक में नहीं किया जाएगा।" (उल्लिखित आदेश की प्रमाणित प्रति का पृष्ठ 24 देखें)।

अतः प्राधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार इस जांच में उठाए गए विभिन्न मुद्दों को हल किया है।

ख. प्रक्रिया

1. नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- (क) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, प्राधिकारी ने 13 अगस्त, 2018 को हुई मौखिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रदान करना का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया।
- (ख) मौखिक सुनवाई के समय मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे उनके द्वारा मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित अनुरोधों के रूप में दायर करें और उन्हें विरोधी पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के प्रत्युत्तर दायर करने की अनुमति दी गई थी। मौखिक सुनवाई के बाद निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध दायर किए:
- मैसर्स आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लि. (घरेलू उद्योग) का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स टीपीएम।
 - सऊदी अरब साम्राज्य दूतावास
 - सऊदी बुटानॉल कंपनी (सबुको), सऊदी एक्रिलिक एसिड कंपनी (साक), सदारा केमिकल कंपनी (सदारा), पेट्रोकेम मिडिल ईस्ट एफजेडई (पेट्रोकेम), नेशनल इंडस्ट्रीलाइजेशन पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग कं. (तंसी मार्केटिंग) और टोयोटा शुशो कारपोरेशन (टोयोटा) का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स एलकेएस।
- (ग) जांच के पूर्व दौर के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी संगत अनुरोधों (जिनके परिणामस्वरूप 28 नवंबर, 2017 के अंतिम जांच परिणाम हुए) और 31 जुलाई, 2018 के आदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिमांड की

कार्रवाईयों के बाद, अनुरोधों उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों और प्रकटन विवरण पर अनुरोधों को इस जांच परिणाम में ध्यान में रखा गया है।

- (घ) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों/साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सार्वजनिक फाइल का हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण किया गया था तथा जिन्होंने सार्वजनिक फाइल के रूप में दस्तावेजों की प्रतियों के लिए अनुरोध किया था, इन्हें वे दी गई।
- (ङ) गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई। प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध कराएं जो सार्वजनिक फाइल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी।
- (च) क्षति रहित कीमत (जिसे यहां आगे एनआईपी कहा गया है) घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे निर्मित करने तथा उसकी बिक्री करने की लागत को ध्यान में रखते हुए निकाली गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। यह इस पुनर्निर्धारण से असंबद्ध है।
- (छ) मूल जांच में जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 (12 माह) (जिसे यहां आगे "जांच की अवधि" अथवा "पीओआई" कहा गया है) मानी गई थी। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 2012-13, 2013-14, 2014-15 और जांच की अवधि शामिल थी। प्राधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे का मूल्यांकन करने के लिए डीजीसीआईएस से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2016-17, 2017-18 और अप्रैल 2018 से अगस्त, 2018 के लिए जांच की अवधि के बाद की अवधि के आयात आंकड़ों पर विचार किया है।
- (ज) परिवर्तन के लिए विनिमय दर जांच की अवधि के लिए सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी डॉलर के लिए 65.91 रुपए मानी गई है।
- (झ) इस अंतिम जांच परिणाम में *** गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना तथा नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाती है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

2. माननीय उच्च न्यायालय ने अपने 31 जुलाई, 2018 के आदेश में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में कोई विशिष्ट टिप्पणियां नहीं की हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान रिमांड की कार्रवाईयों में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई मुद्दे नहीं उठाए हैं। अतः प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में दोबारा जांच नहीं की है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

3. माननीय उच्च न्यायालय ने अपने 31 जुलाई, 2018 के आदेश में घरेलू उद्योग के क्षेत्र के संबंध में कोई विशिष्ट टिप्पणियां नहीं की हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान रिमांड की कार्रवाईयों में घरेलू उद्योग के संबंध में कोई मुद्दे नहीं उठाए हैं। अतः प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणाम में घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में दोबारा जांच नहीं की है।

ङ. विविध मुद्दे

क. घरेलू उद्योग के विचार

4. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- (क) वर्तमान रिमांड की कार्रवाईयों में मौखिक सुनवाई प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में मौखिक सुनवाई करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्देश नहीं दिया है। यदि उच्च न्यायालय यह चाहता कि निर्दिष्ट प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों को सुनें तो वह उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में विशेष रूप से उल्लिखित किया गया होता। रबर केमिकल्स के मामले में सेसटेट ने, जिसमें सेसटेट ने मामला वापस निर्दिष्ट

प्राधिकारी को भेजा है और जिसमें सेसटेट ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों को सुनने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिया था।

(ख) मामला वापस भेजने की कार्यवाही में निर्दिष्ट प्राधिकारी को नए सिरे से पुनर्निर्धारण करना अपेक्षित नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करना और उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करना ही अपेक्षित है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को उच्च न्यायालय द्वारा वापस रिमांड की गई सीमा तक ही मामले पर विचार करना अपेक्षित है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को मामले के अन्य किसी भी पहलू की जांच करने अपेक्षित नहीं है। याचिकाकर्ता निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे आदेश पर विचार करें और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करें। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी को सऊदी अरब से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की कारणात्मकता पर पुनः विचार करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे को ही हल करना तथा उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में अंतिम जांच परिणाम में संशोधन करना अपेक्षित है। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए उच्च न्यायालय के आदेश के अन्यथा अथवा उपयुक्तता के संबंध में किसी तर्क पर ध्यान न दें।

(ग) मौखिक सुनवाई के समय हितबद्ध पक्षकारों के तर्क उच्च न्यायालय के निर्णय के सही-सही होने अथवा अन्यथा को चुनौती देने के बराबर है। प्रथमतः, पक्षकार ने उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत रिट याचिका में भाग नहीं लिया। दूसरे, वर्तमान कार्यवाहियों का क्षेत्र उच्च न्यायालय के आदेश के सही-सही होने अथवा अन्यथा की समीक्षा करना नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को उच्च न्यायालय के आदेश के सही-सही होने अथवा अन्यथा पर विचार करना अपेक्षित नहीं है। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए उच्च न्यायालय के आदेश की उपयुक्तता अथवा अन्यथा के संबंध में किसी तर्क पर ध्यान न दें।

ख. निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

6. सऊदी अरब से उत्पादकों/निर्यातकों, यथा - सऊदी बूटानॉल कंपनी, सऊदी एक्रिलिक एसिड कंपनी, सदारा केमिकल कंपनी, नेशनल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीलाइजेशन मार्केटिंग कं., टोयोटा शुशो कारपोरेशन, पेट्रोकेम मिडिल ईस्ट एफजेडई का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स लक्ष्मी कुमार एंड श्रीधरन अटॉर्नीज ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

(क) घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि वर्तमान मामले में किसी मौखिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मौखिक सुनवाई करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया था। प्रथमतः, घरेलू उद्योग का अनुरोध उचित है क्योंकि मौखिक सुनवाई पहले ही हो गई है और घरेलू उद्योग ने उसमें भाग भी ले लिया है। दूसरे, यह कहना ठीक नहीं है कि मौखिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में कोई विशेष निर्देश नहीं दिया है। मौखिक सुनवाई करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से विशेष निर्देश की आवश्यकता नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे स्कीम और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के ढांचे के आधार पर नए सिरे से पुनर्निर्धारण करें जिसमें मौखिक सुनवाई करने की आवश्यकता शामिल है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक सुनवाई के अवसर का प्रावधान है।

(ख) इसके अतिरिक्त, ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा अन्य [(2011) 2एससीसी258] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से यह टिप्पणी की है कि मौखिक सुनवाई अनिवार्य है क्योंकि पाटनरोधी जांच के मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अपनाया जाना अपेक्षित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की:

“इस प्रकार, यह सुनिर्धारित है कि जब तक कोई सांविधिक प्रावधान या तो विशेष रूप से अथवा आवश्यक प्रभाव से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने को अलग नहीं करता क्योंकि उस स्थिति में न्यायालय विधायी अधिदेश की उपेक्षा नहीं करेगा, कोई आदेश जारी करने से पूर्व सुनवाई किए जाने का उपयुक्त अवसर देने की आवश्यकता किसी संविधि के प्रावधानों में सामान्य रूप से पढ़ी जाती है, विशेष रूप से जब आदेश के प्रतिकूल नागरिक परिणाम हों, जिनमें स्पष्ट रूप से प्रभावित पक्षकार के लिए संपत्ति, व्यक्तिगत अधिकारों और वास्तविक प्रवचनाओं के प्रभाव शामिल हों। उपर्युक्त कानूनी स्थिति के आलोक में और 1995 की नियमावली के नियम 6 में निर्धारित विस्तृत परिपाटी के आलोक में, जिसका निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांच करते समय अनुपालन करना अनिवार्य है, हम समझते हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अपनाने का दायित्व उपर्युक्त नियमावली के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में स्पष्ट है। यहां तक कि लिखित तर्क मौखिक सुनवाई का स्थान नहीं लेते। व्यक्तिगत सुनवाई से संबंधित प्राधिकारी साक्ष्य आदि के आचरण को देख सकते हैं तथा तर्कों के दौरान उसके संदेहों को भी स्पष्ट कर सकते हैं (जोर शामिल किया गया)।”

इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन किया जाना अपेक्षित है और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा रिमांड की कार्यवाहियों के मामले में भी अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पूर्व सुनवाई की जानी है।

(ग) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा समीक्षा के लिए खुला नहीं है। इस पर सहमति है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की हितबद्ध पक्षकारों द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती अथवा उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तथापि, माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखने के बाद हमें कानूनी तर्क उठाने से रोका नहीं जा सकता। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, माननीय उच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे पाटनरोधी नियमावली के ढांचे और स्कीम के आधार पर तथा उसके निर्णय में की गई टिप्पणियों पर विचार करने के बाद नए सिरे से निर्धारण करें। तदनुसार, हमने पाटनरोधी नियमावली की स्कीम और ढांचे के आधार पर तथा माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के आधार पर विस्तृत अनुरोध किए हैं।

(घ) घरेलू उद्योग का दावा है कि रिमांड की कार्यवाहियों में निर्दिष्ट प्राधिकारी को नए सिरे से निर्धारण करना अपेक्षित नहीं है और मामले के अन्य पहलुओं की जांच करना अपेक्षित नहीं है। घरेलू उद्योग का दावा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का सीधा-सीधा विरोधाभास है। माननीय उच्च न्यायालय निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि वे पाटनरोधी नियमावली के ढांचे और स्कीम के आधार पर "नए सिरे से" निर्धारण करें। माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि:

"जैसा कि हमने पहले ही नोट किया है कि 1995 की नियमावली में ऐसा कोई अधिदेश नहीं है, 28.11.2017 के अंतिम जांच परिणामों को अलग रखा जाता है और यह मामला निर्दिष्ट प्राधिकारी को 1995 की नियमावली के ढांचे और स्कीम को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से विचार के लिए और ऊपर की गई टिप्पणियों पर विचार करने के लिए भेजा जाता है।"(जोर शामिल किया गया)।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी कानूनी मुद्दों पर विचार करने से नहीं रोका है और वस्तुतः विशेष रूप से निर्देश दिया है कि वे "नए सिरे से" निर्धारण जारी करें। माननीय उच्च न्यायालय ने नए निर्धारण जारी करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को विशेष रूप से दो माह का समय दिया है।

(ङ) घरेलू उद्योग ने दावा किया कि उत्तरदाताओं ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में भाग नहीं लिया और निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष उत्तरदाताओं का तर्क माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की सत्यता अथवा अन्यथा को चुनौती देने के बराबर है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। घरेलू उद्योग ने न्यायालय की कार्यवाहियों में सऊदी अरब के उत्पादकों/निर्यातकों को उत्तरदाता नहीं बनाया। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग द्वारा दायर रिट याचिका के संबंध में उत्तरदाताओं को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं के भाग न लेने का अभिप्राय उत्तरदाताओं से किसी प्रकार के सहयोग का अभाव नहीं है और इसे उनके विरुद्ध नहीं माना जा सकता। उत्तरदाताओं को मूल जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सहयोगी पक्षकारों के रूप में निर्धारित किया गया है और उन्होंने रिमांड की कार्यवाहियों के अनुसरण में निर्धारित सुनवाई में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष विधिवत भाग लिया है।

(च) यह कहना ठीक नहीं है कि उत्तरदाताओं का तर्क माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की सत्यता अथवा अन्यथा को चुनौती देने के बराबर है। घरेलू उद्योग उत्तरदाता के एक भी अनुरोध अथवा तर्क की पहचान करने में विफल रहे हैं जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की सत्यता पर प्रश्न उठाता हो। वस्तुतः उत्तरदाताओं ने माननीय उच्च न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के अनुपालन में और माननीय उच्च न्यायालय की सभी टिप्पणियों को ध्यान में रखने के बाद अनुरोध किए हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी को उत्तरदाताओं द्वारा उठाए गए कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखने से कोई नहीं रोकता।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

7. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक अर्ध न्यायिक निकाय होने के नाते, उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अपनाना अपेक्षित है और हितबद्ध पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान किया गया है। प्राधिकारी ने मौखिक सुनवाई करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अधिदेश को अपनाया और प्राधिकारी के समक्ष अनुरोध करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किया।

8. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा अन्य में यह माना है कि प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पूर्व मौखिक सुनवाई करना अपेक्षित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने प्राधिकारी को मौखिक सुनवाई करने से नहीं रोका है। पाटनरोधी नियमावली और अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध आमंत्रित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को किसी भी तरह से कम नहीं करता।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

9. माननीय उच्च न्यायालय ने अपने 31 जुलाई, 2018 के आदेश में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में कोई विशेष टिप्पणियां नहीं की हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाहियों में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में कोई मुद्दे नहीं उठाए हैं। अतः प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणाम में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अपनी जांच दोबारा नहीं की है और वे 28.11.2017 के मूल जांच परिणाम में मूल्यांकित के समान ही हैं।

छ. क्षति

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के मुद्दे के संबंध में कुछ टिप्पणियां की थीं। इसके अतिरिक्त, रिमांड की कार्यवाहियों के दौरान हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में विस्तृत अनुरोध किए हैं। अतः प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणाम में क्षति और कारणात्मक संपर्क के पहलू की दोबारा जांच की है।

क. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

11. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि:

- (क) संबद्ध देश से आयात जनवरी, 2016 में शुरू हुआ और तीन माह में ही इन पाटित आयातों की मात्रा घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुँचाने के लिए काफी थी।
- (ख) याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि में पूरी क्षति संबंधी सूचना को दो भागों में अलग-अलग किया है:
 - (i) अप्रैल – दिसंबर, 2015, जब संबद्ध देश से कोई आयात नहीं था।
 - (ii) जनवरी – मार्च, 2016, जब संबद्ध देश से आयात शुरू हुआ।
- (ग) जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति की जांच करते समय भी प्राधिकारी संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की सीमा और मात्रा की जांच करने के लिए जनवरी - मार्च, 2016 की अवधि पर अतिरिक्त रूप से विचार करें।
- (घ) जांच की अवधि के बाद की अवधि में आयात यह दर्शाते हैं कि जांच की अवधि के दौरान आयात एक नए संयंत्र से भारत को निर्यात का कारण नहीं थे बल्कि उत्पाद को पाटित करने के लिए संबद्ध निर्यातकों द्वारा देखा गया एक बाजार अवसर था।
- (ङ) सबुको में क्षमताओं, तीन संवर्धक कंपनियों द्वारा हिस्सेदारी में उत्पादन और उत्पादन के उपयोग के लिए उनके पास विकल्प भी यह दर्शाते हैं कि जांच की अवधि में आयात कारणात्मक नहीं थे बल्कि भारतीय बाजार को हड़पने के लिए इन कंपनियों के सजग निर्णय थे।
- (च) घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादकों द्वारा पेश की गई कीमतों के बीच काफी अंतर है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग देश में उत्पाद के पाटन के परिणामस्वरूप उन कीमतों से अधिक कीमतें बढ़ाने में असमर्थ हैं।
- (छ) यहां तक कि जब घरेलू उद्योग इष्टतम से कम कीमत पेश कर रहा है, उसकी बिक्री कम हो रही है। इस प्रकार, बिक्री मात्रा में गिरावट संबद्ध देश से पाटित आयातों का सीधा परिणाम है।
- (ज) घरेलू उद्योग द्वारा पेश की गई इष्टतम से कम कीमतों के बावजूद आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत कटौती हो रही थी और घरेलू उद्योग पर इसका कीमत दबाव बन रहा था।
- (झ) आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास हो रहा है और कीमतें बढ़ने से रुक रही हैं जो कि पाटन के अभाव में हुई होतीं।
- (ञ) बिक्री, उत्पादन और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है क्योंकि अन्य स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए जांच, जांच की अवधि के पहले नौ महीनों अर्थात् अप्रैल - दिसंबर, 2015 में चल रही थी। तथापि, उपर्युक्त मानदंडों के संबंध में निष्पादन में जांच की अवधि अर्थात् जनवरी – मार्च, 2016 के पिछले अंतिम तीन महीनों में काफी गिरावट आई है क्योंकि संबद्ध देश से नया पाटन शुरू हो गया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने 19 फरवरी, 2016 को इन स्रोतों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हुए सकारात्मक जांच परिणाम अधिसूचित किए थे।

- (ट) घरेलू उद्योग का निष्पादन पूरी क्षति अवधि में लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ के संदर्भ में प्रतिकूल था। संबद्ध देश से जांच की अवधि के जनवरी – मार्च, 2016 की अवधि में पाटित आयात शुरू होने से स्थिति और खराब हो गई है।
- (ठ) पाटन मार्जिन काफी है।
- (ड) घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक संबद्ध देश से आयात कीमत है। इस प्रकार, कीमत ह्रास बाजार में उत्पाद के पाटन के कारण है।
- (ढ) घरेलू उद्योग की वृद्धि मात्रा और कीमत मानदंडों, दोनों के संबंध में प्रतिकूल है।
- (ण) घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटन के परिणामस्वरूप वास्तविक क्षति हुई है।
- (त) क्षति मार्जिन काफी है।
- (थ) पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के अनुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है।
- (द) उपाय का स्वरूप अमेरिकी डॉलर में निर्धारित मात्रा में रखे जाने की आवश्यकता है।
- (ध) जांच की अवधि में दो भागों में अलग करने का प्रयोजन घरेलू उद्योग के निष्पादन पर संबद्ध सामानों के पाटन का प्रभाव और क्षति से उसके कारणात्मक संपर्क को दर्शाना है।
- (न) तीन माह में ही संबद्ध सामानों के पाटन का प्रभाव इतना काफी पाया गया कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- (प) दिसंबर, 2015 तक आयात विचाराधीन उत्पाद का पाटन करने वाले अन्य स्रोतों से थे और वहां से थे जहां पाटनरोधी शुल्क मार्च, 2016 के बाद लगाया गया था। सऊदी से आयात जांच की अवधि के अंतिम सप्ताह में शुरू हुए और किसी भी समय काफी थे। पाटन एक स्रोत से दूसरे स्रोत में बदलने का अभिप्राय यह नहीं है कि कारणात्मक संपर्क टूट गया है।
- (फ) पूर्व की अवधि में याचिकाकर्ता के प्रोपेलीन के आपूर्तिकर्ता के संयंत्र में आग लग जाने के कारण संयंत्र बंद होने से संबंधित मुद्दे की निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले ही जांच कर ली है।
- (ब) वर्तमान जांच की अवधि में संयंत्र को बंद करने का कारण संबद्ध देश से कम कीमतों पर पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण बाजार में अलाभप्रद कीमतों के मद्देनजर उत्पादन को रोकना था।
- (भ) घरेलू उद्योग को कानून के तहत संरक्षण की मांग करने से पूर्व मांग के 100 प्रतिशत की पूर्ति करना अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, उचित कीमतों पर देश में उत्पाद के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- (म) माननीय उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश के आदेश और पूर्व में दी गई सूचना के आलोक में याचिकाकर्ता प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया –
- किए गए निर्धारण पर विचार करें जिसमें प्राधिकारी ने पहले ही निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं:
 - जांच की अवधि के अंतिम तीन महीनों में भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में और पूर्ण दृष्टि से काफी मात्रा में सऊदी अरब से आयात भारत में आए हैं।
 - इन तीन महीनों के दौरान सऊदी अरब के निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक की काफी कीमत कटौती थी।
 - कम कीमत पर बिक्री 55 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक थी।
 - बिक्री, उत्पादन और क्षमता उपयोग के मानदंडों के संबंध में निष्पादन में जांच की अवधि की अंतिम तिमाही अर्थात् जनवरी से मार्च, 2016 में गिरावट आई क्योंकि सऊदी अरब से नए पाटित आयात शुरू हो गए।
 - सऊदी अरब से निर्यातकों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन भी अधिक थे जो 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच थे।
 - जहां तक प्राधिकारी की निम्नलिखित टिप्पणियों का संबंध है, अंतिम जांच परिणाम में संशोधन किया जाए:
 - सऊदी अरब से संबंधित सामानों के निर्यातों की जांच की अवधि के अंतिम तीन माह की अवधि घरेलू उद्योग को क्षति का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि वास्तविक क्षति निर्धारण के लिए आयातों से संबंधित आंकड़ों और लंबी अवधि के लिए घरेलू उद्योग के बिक्री के आंकड़ों की आवश्यकता होगी।

- सऊदी अरब से आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क निर्यात अवधि के तीन महीनों के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप सिद्ध नहीं है।
- उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी सऊदी अरब से संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करना उपयुक्त नहीं समझते और पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(ख) के अनुसार एतद्वारा जांच को रद्द करते हैं।

(य) इस तर्क की निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच की अवधि के अंतिम तीन माह के दौरान की गई वर्तमान पाटनरोधी जांच में जांच की अवधि की अनुपयुक्तता के संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला था, के संबंध में यह कहना है कि अंतिम जांच परिणाम अपूर्ण और कमियों वाला है तथा यह कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम जांच की अवधि की अनुपयुक्तता सिद्ध किए बिना जारी किए, सही नहीं है क्योंकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम के पैरा 94(vii) में अपने जांच परिणामों का निष्कर्ष निकाला। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से माना कि जांच की अवधि में तीन महीनों के आयात घरेलू उद्योग को पाटन एवं परिणामस्वरूप क्षति निर्धारित करने के लिए पर्याप्त हैं। तथापि, इस स्तर पर ऐसा कोई तर्क मान्य नहीं है। यह मुद्दा इस स्तर पर विचार के लिए खुला नहीं है और वह पहले ही अंतिम चरण में पहुँच गया है।

प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में सकारात्मक तथा वस्तुतः काफी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में यह भी टिप्पणी की है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड किए गए जांच परिणाम स्पष्ट रूप से पाटन के पर्याप्त साक्ष्य दर्शाते हैं और घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। कानून के तहत ऐसी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि जांच की पूरी अवधि में पाटन आयात मौजूद होने चाहिए।

(कक) जहाँ तक इन अनुरोधों का संबंध है कि याचिका विशेष रूप से इस तथ्य को प्रकट नहीं करती कि सऊदी अरब से आयात जांच की अवधि के अंतिम तीन महीनों में ही हुए, हितबद्ध पक्षकारों का निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अब इस पहलू पर अंतिम जांच परिणाम को चुनौती देने का कोई कानूनी आधार नहीं है। हितबद्ध पक्षकार अत्यधिक भ्रामक और वास्तविक रूप से गलत विवरण देकर प्राधिकारी को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने याचिका में पूरी क्षति अवधि के लिए आयातों की पूरी सूची दी है। दी गई सूचना से यह सिद्ध है कि जांच की अवधि में ही आयात हुए हैं।

निर्यातक के तर्क का दूसरा अर्थ यह है कि प्राधिकारी ने लापरवाही से जांच शुरू की है।

पूरी क्षति अवधि अथवा पूरी जांच की अवधि में आयात जारी रहने की पाटनरोधी कानून में कोई अपेक्षा नहीं है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की अपेक्षा यह है कि संबद्ध देश से आयात 3 प्रतिशत से अधिक होने चाहिए और कीमतें पाटन कीमतें हों।

(खख) जांच की अवधि का मुद्दा कम से कम 6 माह होना इस स्तर पर विचार के लिए खुला नहीं है और वह पहले ही अंतिम स्तर तक पहुँच गया है। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी उच्च न्यायालय के आदेश की उपयुक्तता अथवा अन्यथा के संबंध में किसी तर्क पर विचार न करें।

इस तर्क का दूसरा निर्वचन यह है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के एक देश अथवा एक से अधिक देश के मामले के लिए भिन्न मानदंड होने चाहिए। यदि पाटन केवल एक देश से हो रहा है तो वह पाटन पूरी जांच की अवधि पर समान रूप से होना चाहिए, परंतु यदि पाटन एक से अधिक देश से हो रहा है तो वह ठीक है, यदि पाटन जांच की अवधि के भीतर विभिन्न देशों से छिट-पुट है। निर्यातक के तर्क का यह अभिप्राय है कि कुछ देशों के संयोजन में निर्दिष्ट प्राधिकारी याचिका को स्वीकार करेंगे। कुछ संयोजन में निर्दिष्ट प्राधिकारी याचिका को रद्द करेंगे।

वर्तमान मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

"अनुबंध-1 में खंड (2) उन निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए तीसरे देश को अथवा उनके घरेलू बाजार में समान उत्पाद की, की गई बिक्री के संबंध में 6 माह की अवधि बताता है और इससे अधिक नहीं। अतः यह खंड जांच की अवधि के दौरान तीन माह से अधिक में होने वाले पाटन की कोई आवश्यकता नहीं दर्शाता, जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने अंतिम निष्कर्ष में गलत माना गया है। विदेशों से निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा समान उत्पादों के पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति निर्धारित करने अथवा उसका मूल्यांकन करने के लिए 1995 की नियमावली के संदर्भ में अपेक्षित किसी लंबी अवधि का उल्लेख नहीं है, परंतु निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपनी जांच को समाप्त करने के लिए औचित्य बनाने हेतु जनवरी से मार्च, 2016 की तीन माह की अवधि को जोड़ा जो कि पूर्णतः असंधारणीय है।"

(गग) माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से माना कि जांच की अवधि में तीन माह के आयात पाटन आयातों और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, इस स्तर पर इस प्रकार का कोई तर्क मान्य नहीं है और वह अंतिम स्तर तक पहुँच गया है। अब ऐसे तर्क को प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के लिए यह खुला नहीं है।

(घघ) अंतिम जांच परिणाम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार सऊदी अरब से पाटित आयातों के कारण पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क का विश्लेषण गलत किया गया है। चूंकि, माननीय उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर पहले ही निर्णय ले लिया है कि पाटन के कारण क्षति हुई है या नहीं, अतः इस मुद्दे पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा तर्क नहीं दिया जा सकता। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी उच्च न्यायालय के आदेश की उपयुक्तता अथवा अन्यथा के संबंध में किसी तर्क पर विचार न करें।

"यह केवल तभी है जब प्राधिकारी को पाटन का पर्याप्त साक्ष्य न मिले अथवा जांच को जारी रखने के लिए औचित्य बनाने हेतु क्षति न हो जिससे यह रद्द किया जा सके। इस मामले में, जैसा कि पहले ही ऊपर नोट किया गया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड किए गए जांच परिणामों में सऊदी अरब से निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा तीन माह के समय के भीतर पाटन के पर्याप्त साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं और उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति भी दर्शाई गई, अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच रद्द करने के लिए औचित्य बनाने हेतु इस कारण को नहीं ले पाए। वस्तुतः नियम 14 में किसी भी खंड, जो जांच को रद्द करने के संबंध में हो, में आवेदन नहीं था जिससे प्राधिकारी इस प्रकार का कदम उठा सकते थे।"

(ङङ) जहां तक घरेलू उद्योग के कोई तथ्य प्रस्तुत न करने का संबंध है, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कारणात्मक संपर्क के अभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध सूचना अथवा तर्क उच्च न्यायालय के निर्णय की सत्यता अथवा अन्यथा को चुनौती देने के बराबर है। यह तर्क यह उल्लेख करने के बराबर भी है कि उच्च न्यायालय ने दिमाग लगाए बिना आदेश पारित किया है। प्रथमतः, पक्षकार ने उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की गई रिट याचिका में भाग नहीं लिया। दूसरे, वर्तमान कार्यवाहियों का क्षेत्र उच्च न्यायालय के आदेश की सत्यता अथवा अन्यथा की समीक्षा करना नहीं है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को उच्च न्यायालय के आदेश की सत्यता अथवा अन्यथा पर विचार करना अपेक्षित नहीं है। अतः, निर्दिष्ट प्राधिकारी उच्च न्यायालय के आदेश की उपयुक्तता अथवा अन्यथा के संबंध में किसी तर्क पर विचार न करें।

माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी पर आधारित है। अतः, निर्दिष्ट प्राधिकारी उच्च न्यायालय के आदेश की उपयुक्तता अथवा अन्यथा के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों दिए गए किसी तर्क पर विचार न करें।

(चच) यह तर्क कि अंतिम जांच परिणाम के पैरा 74 में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने गलती से सार निकाला है कि संबद्ध देश अथवा अन्य गैर-संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को केवल यह निष्कर्ष निकालने के लिए अंतिम जांच परिणाम के पैरा 74 को ही समाप्त करने की अपेक्षा है कि संबद्ध देश से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, निर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेश की ही समीक्षा करने के बराबर है बल्कि उच्च न्यायालय के आदेशों की भी समीक्षा करने के बराबर है। याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि हितबद्ध पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा उच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा करने के हकदार नहीं हैं। वस्तुतः पैरा 74 में प्राधिकारी की टिप्पणी सही है।

(छछ) घरेलू उद्योग ने वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में 27 अक्तूबर, 2017 के लिखित अनुरोध में संगत सूचना प्रदान की थी। तथापि, प्राधिकारी ने इस सूचना पर विचार नहीं किया, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की गई है:

".... निर्दिष्ट प्राधिकारी यह मानने में पूर्णतः अनौचित्यपूर्ण थे कि सऊदी अरब से उत्पाद के आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति के संभावित खतरे अथवा वास्तविक मंदी की जांच करने का उससे अधिदेश नहीं है। अतः भारत में किसी भी उद्योग की स्थापना को क्षति के किसी संभावित खतरे अथवा वास्तविक मंदी की जांच करने के लिए इस मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इंकार करना सांविधिक अधिदेश की कमी में आता है।"

ख. निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

12. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- (क) यह आवेदन जांच शुरू करने के लिए न तो पूर्व शर्तों को पूरा करता है और न ही नियम 5 के तहत पर्याप्तता और शुद्धता के परीक्षण को पूरा करता है क्योंकि पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने वाले पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए गए हैं।
- (ख) गोपनीयता – याचिका के अगोपनीय रूपांतर में दी गई कुछ सूचना सार्थक टिप्पणी करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने हेतु या तो भ्रामक है अथवा अपर्याप्त है। घरेलू उद्योग को निदेश दिया जाना चाहिए कि वे कम से कम रेंजों में आंकड़े प्रकट करें ताकि उस तालिका की सार्थक समझ बन सके।
- (ग) याचिका में आरोपित कीमत कटौती मार्जिन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। निर्यात सऊदी अरब के उत्पादकों द्वारा भारतीय व्यापारियों को किए जाते हैं जो भंडारण और वेयरहाउसिंग के खर्च करते हैं। इन लागतों से पहुँच मूल्य

25-30 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। कीमत कटौती भारत में व्यापारियों की पुनः बिक्री कीमत के साथ घरेलू बिक्री कीमत की तुलना के आधार पर होनी चाहिए।

- (घ) सऊदी अरब से आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क का अभाव है। सऊदी अरब से आयात 2014-15 में शून्य से बढ़कर जांच की अवधि में 8,791 मी. टन हो गए हैं। घरेलू उद्योग की बिक्री भी उसी अवधि में 7,117 मी. टन तक बढ़ गई।
- (ङ) अन्य देशों से आयात भारत में जांच की अवधि में पाटित कीमतों पर और पाटनरोधी शुल्क से मुक्त आ रहे थे जो कि जांच की अवधि पूरा होने के बाद लगाए गए थे। सऊदी अरब से आयात भारतीय बाजार में जांच की अवधि के अंतिम तीन माह (अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016) के लिए और पूरी क्षति अवधि के लिए ही आए हैं।
- (च) यह हुई क्षति घरेलू उद्योग द्वारा स्व-प्रभावित है। याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि उनके पास कच्ची सामग्री की आपूर्ति का केवल एक स्रोत है और आपूर्तिकर्ता के संयंत्र में आग लग जाने के कारण संयंत्र बंद करना पड़ा था।
- (छ) सऊदी अरब से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित के विरुद्ध होगा। मांग एवं आपूर्ति का अंतराल है। घरेलू उद्योग पूर्ण क्षमता पर उत्पादन करने के बाद भी भारत में केवल 32 प्रतिशत मांग की आपूर्ति करने में ही सक्षम होगा।
- (ज) लागत संबंधी आंकड़ों के अगोपनीय रूपांतर का अभाव है।
- (झ) याचिका में आरोपित कीमत कटौती मार्जिन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। निर्यात सऊदी अरब के उत्पादकों द्वारा भारतीय व्यापारियों को किए जाते हैं जो भंडारण और वेयरहाउसिंग के खर्चे करते हैं। इन लागतों से पहुँच मूल्य 25-30 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। कीमत कटौती भारत में व्यापारियों की पुनः बिक्री कीमत के साथ घरेलू बिक्री कीमत की तुलना के आधार पर होनी चाहिए।
- (ञ) अन्य देशों से आयात भारत में जांच की अवधि में पाटित कीमतों पर और पाटनरोधी शुल्क से मुक्त आ रहे थे जो कि जांच की अवधि पूरा होने के बाद लगाए गए थे। सऊदी अरब से आयात भारतीय बाजार में जांच की अवधि के अंतिम तीन माह (अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016) के लिए और पूरी क्षति अवधि के लिए ही आए हैं।
- (ट) यह हुई क्षति घरेलू उद्योग द्वारा स्व-प्रभावित है। याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट यह दर्शाती है कि उनके पास कच्ची सामग्री की आपूर्ति का केवल एक स्रोत है और आपूर्तिकर्ता के संयंत्र में आग लग जाने के कारण संयंत्र बंद करना पड़ा था।
- (ठ) सऊदी अरब से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित के विरुद्ध होगा। मांग एवं आपूर्ति का अंतराल है। घरेलू उद्योग पूर्ण क्षमता पर उत्पादन करने के बाद भी भारत में केवल 32 प्रतिशत मांग की आपूर्ति करने में ही सक्षम होगा।
- (ड) घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि को दो अवधियों में अलग-अलग किया है – (i) अप्रैल से दिसंबर, 2015 और (ii) जनवरी से मार्च, 2016। घरेलू उद्योग इस पर विवाद नहीं करता कि पहली अवधि अर्थात् जांच की अवधि के पहले 9 माह में संबद्ध देश से आयात नहीं थे। घरेलू उद्योग यह भी स्वीकार करता है कि वर्तमान जांच में आंकड़ा संग्रहण की अवधि प्रभावी रूप से तीन माह है न कि एक वर्ष। जैसा कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अभिज्ञात किया गया है। घरेलू उद्योग इस बात से इंकार नहीं करता कि पाटन संबंधी जांच के लिए डाटा संग्रहण की अवधि सामान्यतः 12 माह होनी चाहिए और किसी भी हालत में छः माह से कम नहीं होनी चाहिए। तथापि, घरेलू उद्योग पाटनरोधी परिपाटियों संबंधी समिति द्वारा की गई टिप्पणी पर विश्वास करता है कि जांचकर्ता प्राधिकारी पाटन और क्षति दोनों के लिए डाटा संग्रहण की अवधियाँ निर्धारित करने में दी गई जांच की विशेष परिस्थितियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक मामले में वे उपयुक्त हैं, ध्यान में रख सकते हैं। घरेलू उद्योग का दावा है कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क तीन माह के आयात आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाना है।
- (ढ) घरेलू उद्योग का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता; प्रथमतः, घरेलू उद्योग उस "विशेष परिस्थिति" को बताने में विफल रहा जिससे जांच की अवधि कम करना आवश्यक हो; दूसरे, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एक परिपाटी के रूप में विगत में सभी जांचों में पाटनरोधी परिपाटी संबंधी समिति की सिफारिश को अपनाया है। घरेलू उद्योग भारत में अथवा किसी अन्य क्षेत्राधिकार में एक भी उदाहरण देने में विफल रहा है, जिसमें पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क का मूल्यांकन केवल तीन माह की अवधि के आंकड़ों पर आधारित हो; तीसरे, यदि वर्तमान मामले में "विशेष परिस्थिति" में आंकड़ा संग्रहण के लिए जांच की कम अवधि की आवश्यकता होती तो निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की सूचना में जांच की अवधि के रूप में एक वर्ष औपचारिक रूप से नहीं चुना होता। दूसरे शब्दों में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पहले ही यह निर्णय ले लिया है कि ऐसी कोई "विशेष परिस्थिति" नहीं है जिससे जांच की अवधि कम

करने की आवश्यकता हो; चौथे, ग्वाटेमाला – सीमेंट ॥ में पैनल द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किया गया विश्वास गलत है। पैनल की टिप्पणी क्षति जांच की अवधि के संबंध में है न कि जांच की अवधि के संबंध में। वस्तुतः ग्वाटेमाला – सीमेंट ॥ में पैनल ने विशेष परिस्थिति की मौजूदगी के कारण क्षति के निर्धारण के लिए एक वर्ष की छोटी अवधि की अनुमति दी थी न कि तीन माह की।

- (ण) पाटनरोधी करार, चूंकि, स्पष्ट रूप से जांच की अवधि के लिए विशिष्ट अवधि अधिदेशित नहीं करती, इसका अर्थ यह नहीं है कि एक माह, दो माह अथवा तीन माह की कम समयावधि के चयन की जांच की अवधि के रूप में अनुमति दी गई है। इसी ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग में अपीलिय निकाय ने स्पष्ट रूप से नोट किया कि जांच की अवधि एक संधारित समयावधि में एक अतिरिक्त किए गए आंकड़े देती है जो अवधि जांचकर्ता प्राधिकारी को पाटन निर्धारण करने के लिए अनुमति देती है जो कि समुचित मूल्यांकन को कम करने वाले बाजार उतार-चढ़ाव अथवा अन्य स्थितियों के अध्यधीन होने के लिए संभावित रूप से कम है।
- (त) यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी तीन माह की समयावधि के आधार पर पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अपने निर्धारण का आधार बनाएंगे तो इससे एक गलत पूर्वोदाहरण बनेगा। कोई न्यूनतम अवधि नहीं होगा जिसके लिए आयात आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना है और निर्धारण उन मामलों पर भी आधारित होगा जहां आयात एक माह अथवा दो माह के लिए किए जाने रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यह विवाद हो सकता है कि सऊदी अरब ने उत्पादकों तथा निर्यातकों के निर्यात व्यवहार को तीन माह के आंकड़े उपयुक्त रूप से नहीं दर्शा सकते। पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश प्रकृति में भविष्य प्रभावी है जो अगले पांच वर्षों के लिए लागू है। यह अपेक्षित है कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क का मूल्यांकन आयात आंकड़ों पर आधारित हो जो निर्यातक कंपनी में उत्पादक/निर्यातक के निर्यात व्यवहार को दर्शाए। इस प्रकार, यह तर्क देना गलत है कि तीन माह की कम अवधि डब्ल्यूटीओ, पाटनरोधी करार और पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप है। परिणामस्वरूप, पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क का पूरा दावा, जो तीन माह के आंकड़ों पर आधारित है, गलत और अविश्वसनीय है।
- (थ) यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस तथ्य के बावजूद जांच जारी रखने का निर्णय लेते हैं कि केवल तीन माह के आयात आंकड़े हैं तो यह अनुरोध है कि क्षति और कारणात्मक संपर्क का मूल्यांकन करने के लिए जांच की अवधि को 9 माह और तीन माह में विभाजित नहीं किया जा सकता। घरेलू उद्योग जांच की अवधि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक बार निर्धारित किए जाने पर उसका उप विभाजन जारी नहीं रख सकते। समग्र रूप से जांच की अवधि पर विचार करते हुए सऊदी अरब के मूल के आयातों और तथाकथित क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क का पूरा अभाव है। घरेलू उद्योग का उत्पादन और घरेलू बिक्री उसी अवधि में बढ़ी है जब सऊदी अरब से भारत में आयात हुए। सऊदी अरब से आयातों का घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं था। इसी प्रकार, उत्पादन क्षमता स्थिर रही तथा उत्पादन, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में वृद्धि हुई। निम्नलिखित तालिका में विवरण है:

घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता और भारत में कुल मांग मी. टन में

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	जांच की अवधि
सऊदी अरब से आयात	मी. टन	0	0	0	8,791
यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात	मी. टन	31,929	42,016	55,243	50,606
कुल मांग	मी. टन	46,769	49,798	59,243	70,552
उत्पादन क्षमता	मी. टन	22,500	22,500	22,500	22,500
बिक्री	मी. टन	14,472	6,425	4,037	11,154
उत्पादन	मी. टन	14,409	5,484	4,203	11,080
क्षमता उपयोग	%	64.04%	24.37%	18.68%	49%
बाजार हिस्सा	%	31%	13%	7%	16%

- (द) इस प्रकार, घरेलू उद्योग को यदि कोई क्षति हुई है तो वह यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यातित सामान्य बुटानॉल के आयातों के कारण है जो आयातों की 85 प्रतिशत मात्रा है और जिसका घरेलू मांग में 72 प्रतिशत हिस्सा था। इसके अतिरिक्त, 7 महीनों के लिए उत्पादन संयंत्र का बंद होना, 23 अगस्त, 2013 को आग लगना, उन दोनों घटनाओं के टिकाऊ परिणाम तथा कच्ची सामग्री की आपूर्ति में कमी जैसे कारकों से घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति हुई है।

(ध) घरेलू उद्योग पहली बार यह दावा कर रहा है कि सऊदी अरब के आयातों से जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों के आधार पर वास्तविक क्षति का खतरा हो रहा है। शुरुआत में यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग यह दावा नहीं कर सकता कि वास्तविक क्षति का कोई खतरा है। जांच का क्षेत्र जांच की शुरुआत के नोटिस द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसमें क्षति के खतरे का मूल्यांकन नहीं दिया जाता। घरेलू उद्योग ने याचिका दायर करते समय और यहां तक कि सार्वजनिक सुनवाई के दौरान वास्तविक क्षति के खतरे का आरोप कभी नहीं लगाया है। वर्तमान जांच याचिका में लगाए गए आरोप के अनुसार वास्तविक क्षति के मूल्यांकन तक सीमित है और जिसके लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि जांच की शुरुआत के नोटिस में प्रथम दृष्टया साक्ष्य था। यह निर्दिष्ट प्राधिकारी की निर्धारित परिपाटी है कि जांच की अवधि के बाद की अवधि मूल जांच में वास्तविक क्षति के मूल्यांकन के लिए नहीं मानी जाती है। चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित वायर रॉड ऑफ अलॉय अथवा नॉन अलॉय स्टील के आयातों से संबंधित हाल ही में निष्कर्ष निकाली गई पाटनरोधी जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह पाया है कि:

"हितवद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि जांच की अवधि के बाद की प्रवृत्तियों की जांच की जानी चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में जांच की अवधि के बाद की प्रवृत्तियां संगत नहीं हैं। पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के संदर्भ में शुरू की गई समीक्षाओं के मामले में जांच की अवधि के बाद की प्रवृत्तियां संगत होंगी क्योंकि प्राधिकारी को यदि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाते हैं तो पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना की जांच करनी होती है।"

मूल जांच में जांच की अवधि के आंकड़ों के आधार पर वास्तविक क्षति निर्धारित करने की निर्दिष्ट प्राधिकारी की स्थापित परिपाटी है। दूसरे शब्दों में, जांच की अवधि के बाद के आंकड़े मूल जांच में असंगत हैं।

(न) प्रश्नावली के उत्तरों में स्पष्ट किए गए अनुसार सऊदी अरब में सामान्य बुटानॉल का वाणिज्यिक उत्पादन 01 मार्च, 2016 को शुरू हुआ। परीक्षण उत्पादन के उत्पाद का कुछ निर्यात सऊदी अरब से भारत में जनवरी, 2016 और फरवरी, 2016 के दौरान हुआ। इस प्रकार, भारत में आयात केवल जांच की अवधि के अंतिम तीन माह के दौरान अर्थात् जनवरी, 2016, फरवरी, 2016 और मार्च, 2016 में किए गए थे। निम्नलिखित तालिका में इसका विवरण है:

जांच की अवधि के दौरान आयातों की मासिक मात्रा मी. टन में

विवरण	अप्रैल, 2012 से मार्च, 2015	अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015	जनवरी, 2016	फरवरी, 2016	मार्च, 2016	जांच की अवधि
सऊदी अरब	0	0	2,154	3,131	3,506	8,791

स्रोत: याचिका में लेन-देन से लेन-देन की सूची

(प) इस प्रकार, वस्तुतः निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मानी गई जांच की अवधि तीन माह की ही है। फिर भी तकनीकी रूप से इसे एक वर्ष की अवधि का नाम दिया जाता है।

पाटनरोधी जांच के मामले में जांच की अवधि कम से कम 6 माह होनी चाहिए।

(फ) घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में नोट किया गया है कि:

"आयातों और बाजार हिस्से के संबंध में सूचना संलग्न क्षति संबंधी सूचना में दी जाती है। इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि 2014-15 तक सऊदी अरब से कोई आयात नहीं थे। प्रस्तावित जांच की अवधि में सऊदी अरब से सम्पूर्ण दृष्टि से आयातों की काफी मात्रा है।" (पृष्ठ 13)

(ब) इस प्रकार, याचिका (अगोपनीय रूपांतर) विशिष्ट रूप से इस तथ्य को प्रकट नहीं करती कि सऊदी अरब से आयात जांच की अवधि के अंतिम तीन महीनों में ही हुए।

(भ) भले ही यह भी हो, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम के अवलोकन से हम समझते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने उस दावे का समर्थन करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के कई पूर्व जांच परिणामों पर विश्वास किया है कि पाटनरोधी शुल्क की वर्तमान मामले में सिफारिश की जा सकती है:

- जॉर्जिया, इंडोनेशिया और ईरान अमोनियम नाइट्रेट
- ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और सिंगापुर से फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉल्योल
- मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम से आर-डीवीडी
- इंडोनेशिया, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात से थर्मल सेंसिटिव पेपर

- (v) कुछ फॉस्फोरस आधारित सम्मिश्रण
- (vi) चीन से डाइक्लोफेनाक सोडियम
- (vii) कतर से कास्टिक सोडा
- (viii) यूरोपीय संघ, सिंगापुर और जॉर्जिया से विटामिन ए पामीटे
- (ix) चीन और संयुक्त अरब अमीरात से सत्यापित/प्रोसलीन टाइल्स

(म) रूस, इंडोनेशिया, जॉर्जिया और ईरान से अमोनियम नाइट्रेट के मामले में संबद्ध सामान 2015-16 की अवधि अर्थात् जांच की अवधि के दौरान जॉर्जिया से आयात किए गए थे। तथापि, घरेलू उद्योग का यह दावा है कि आयात जॉर्जिया से जांच की अवधि के तीन महीनों के दौरान ही अर्थात् जुलाई, अगस्त और फरवरी, 2015-16 की अवधि में किए गए। घरेलू उद्योग ने मामले के निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत नहीं किए हैं:

- (i) अंतिम जांच परिणाम में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है कि संबद्ध सामानों का आयात जांच की अवधि में तीन माह के दौरान जॉर्जिया से किया गया था। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसा कोई दावा नहीं किया गया था कि संबद्ध सामानों का आयात जॉर्जिया से तीन माह के लिए ही किया गया था और इसीलिए इस मुद्दे की जांच निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई थी। जॉर्जिया से निर्यातक को भी असहयोगी निर्धारित किया गया था।
- (ii) अन्य संबद्ध देशों अर्थात् रूस, ईरान और इंडोनेशिया से क्षति जांच की अवधि (जांच की अवधि सहित) के दौरान संबद्ध सामानों का आयात किया गया था।
- (iii) वर्तमान जांच के असमान क्षति जांच अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान और जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों के कारण जांच की अवधि प्रभावी रूप से तीन महीने की ही नहीं थी।

(य) इस प्रकार, उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर मामला का पूरा विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि जॉर्जिया, इंडोनेशिया और ईरान से अमोनियम नाइट्रेट में निर्दिष्ट प्राधिकारी के जांच परिणामों पर घरेलू उद्योग के दावे का समर्थन करने के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता।

(कक) कतर से कास्टिक सोडा के मामले में जांच की अवधि 01 जनवरी, 2001 से 30 सितंबर, 2001 निर्धारित की गई थी। जांच की अवधि के दौरान कतर से संबद्ध सामानों का आयात किया गया था। घरेलू उद्योग ने इस तथ्य पर विश्वास किया कि संबद्ध सामानों का आयात जांच की अवधि के दौरान एक भागीदार निर्यातक से नहीं किया गया था और ऐसी स्थिति में भारतीय आयातकों के साथ उसकी रिक्रि संविदा के आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। घरेलू उद्योग यह नोट करने में एक बार फिर विफल रहा कि वर्तमान मामले के असमान संबद्ध सामानों का आयात जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश कतर से किया गया था। यह तथ्य कि एक निर्यातक मैसर्स कतर विनायल कंपनी (क्यूवीसी) लि. से जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों का कोई आयात नहीं था, एक निर्यातक विशिष्ट मामला है और उस स्थिति के समान नहीं है जहां सामान्य रूप में संबद्ध देश से आयात नहीं हैं।

(खख) ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और सिंगापुर से फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलियोल के मामले में जांच की अवधि के दौरान (जनवरी, 2012 से दिसंबर, 2012) ऑस्ट्रेलिया से संबद्ध सामानों का आयात किया गया था।

(गग) वर्तमान मामले में उत्तरदाताओं ने पाटनरोधी समिति की सिफारिश पर विशेष रूप से विश्वास किया है जिसमें आंकड़ा संग्रहण की न्यूनतम 6 माह की अवधि अर्थात् जांच की अवधि के न्यूनतम 6 माह निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी का जांच परिणाम जिसमें नोट किया गया है कि संबद्ध सामान एक वर्ष की जांच की अवधि के दौरान आयात किए गए थे, किसी भी तरह उत्तरदाता के दावे के विरुद्ध नहीं है। इसी प्रकार, (i) मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम से आर-डीवीडी, (ii) इंडोनेशिया, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात से थर्मल सेंसिटिव पेपर, (iii) यूरोपीय संघ और चीन से - कुछ फॉस्फोरस आधारित सम्मिश्रण, (iv) चीन से डाइक्लोफेनाक सोडियम, (v) यूरोपीय संघ, सिंगापुर और जॉर्जिया से विटामिन ए पामीटे और (vi) चीन और संयुक्त अरब अमीरात से सत्यापित/प्रोसलीन टाइल्स में संबद्ध सामानों का आयात जांच की अवधि के दौरान किया गया था और इसीलिए वर्तमान मामले में इन मामलों के तथ्यों की कोई समानता नहीं है। इन मामलों के अंतिम जांच परिणाम में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है कि संबद्ध सामानों का आयात जांच की अवधि में तीन माह के दौरान ही किया गया था। इसके अतिरिक्त, इन मामलों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई दावा नहीं किया गया था कि संबद्ध सामानों का आयात तीन महीने के लिए ही किया गया था और इसीलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ऐसे मुद्दे की जांच नहीं की।

(घघ) संक्षेप में, घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित प्राधिकारी का कोई किसी भी विगत निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं है। इसलिए, यह दावा करना गलत है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी का विगत निर्णय घरेलू उद्योग के दावे को सिद्ध करता है कि वर्तमान

मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करना उपयुक्त है। वस्तुतः भारत में ऐसा कोई पूर्व मामला नहीं है जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने तीन माह की जांच अवधि के आधार पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की हो।

(डड) डब्ल्यूटीओ, पाटनरोधी करार और भारतीय पाटनरोधी नियमावली जांच की अवधि के लिए न्यूनतम अवधि के रूप में स्पष्ट रूप से किसी विशिष्ट अवधि का प्रावधान नहीं करते। तथापि, पाटनरोधी नियमावली में कोई विशिष्ट प्रावधान न होने का अर्थ यह नहीं है कि जांच की अवधि की उपयुक्तता के संबंध में कोई मार्गनिर्देश नहीं है और प्राधिकारी पाटनरोधी जांच के प्रयोजन के लिए यथा उपयुक्त तीन माह, दो माह अथवा एक माह की अल्पावधि पर विचार कर सकते हैं। पाटनरोधी परिपाटी संबंधी डब्ल्यूटीओ समिति द्वारा की गई सिफारिश में यह प्रावधान है कि:

"समिति सिफारिश करती है कि पाटन और परिणामस्वरूप क्षति की मौजूदगी निर्धारित करने के लिए मूल जांच के संबंध में:

1. एक सामान्य नियम के रूप में:

(क) पाटन जांच के लिए सामान्यतः आंकड़ा संग्रहण की अवधि 12 माह होनी चाहिए और किसी भी दशा में 6 माह से कम नहीं होनी चाहिए जो कि जांच की शुरुआत की तारीख की समाप्ति पर हो, जैसा कि परिपाटी रखे जाने योग्य है।" (जोर शामिल किया गया)।

(चच) डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी समिति मानती है कि आंकड़ा संग्रहण के 6 माह की न्यूनतम अवधि पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी निर्धारित करने के लिए उपयुक्त है। दिशा-निर्देश का प्रभावी रूप से यह अर्थ है कि जांच की अवधि ऐसी होनी चाहिए कि वह संबद्ध देश से आयात आंकड़ों की कम से कम 6 माह हो। फिर भी यह सिफारिश के रूप में है, प्रावधान की अनिवार्य प्रकृति के संबंध में दिशा-निर्देश में कोई द्विअर्थकता नहीं है जो इस बात पर जोर देती है कि न्यूनतम अवधि 6 माह से कम नहीं होनी चाहिए।

(छछ) इस समिति की सिफारिश के बावजूद डब्ल्यूटीओ पैनल और अपीलीय निकाय ने कई मामलों में यह पाया है कि जांच की अवधि का निर्धारण पाटनरोधी करार के तहत गैर-विनियमित नहीं है और उसमें प्रतिनिधिकारक अवधि शामिल होनी चाहिए। डब्ल्यूटीओ पैनल में मैक्सिको – स्टील पाइप ने यह माना कि जांच की अवधि के संबंध में स्पष्ट अपेक्षा के अभाव का अर्थ यह नहीं है कि उसके द्वारा चुनी जाने वाली अवधि के संबंध में जांचकर्ता प्राधिकारी का विवेक उसके क्षति विश्लेषण के लिए आधार के रूप में असीमित है। इस मामले में, जांच की अवधि जुलाई-दिसंबर, 2000 थी तथा पूर्व के दो वर्षों (1998 और 1999) में तदनुसूची 6 माह की अवधि क्षति विश्लेषण के लिए अनुपयुक्त मानी गई थी।

(जज) पैनल ने जोर दिया कि जांचकर्ता प्राधिकारी को सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर वस्तुतः जांच करना अपेक्षित है। पैनल ने यह पाया कि:

"हम मानते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थिति पर पाटन के प्रभावों के सकारात्मक साक्ष्य की वस्तुपरक जांच, जो प्राधिकारी को यह निष्कर्ष निकालने के लिए सक्षम बनाती है कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, में आयातों की मात्रा और कीमत के समय में प्रवृत्तियों एवं घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण शामिल है।"

(झझ) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर वस्तुपरक मूल्यांकन करना अपेक्षित है जिसके लिए एक निर्धारित समयावधि में आयातों के विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तीन माह की जांच अवधि से सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर वस्तुपरक मूल्यांकन नहीं हो पाएगा।

(ञञ) ईसी – ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग में यूरोपीय आयोग ने 01 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 1999 तक एक वर्ष की जांच की अवधि का प्रयोग करके अपनी जांच की। ब्राजीलियन रियल का जनवरी, 1999 में इस अवधि के अंत में 42 प्रतिशत तक अवमूल्यन किया गया था। ब्राजील ने तर्क दिया कि यूरोपीय संघ को सामान्य मूल्यों की तुलना अवमूल्यन के बाद की अवधि से पूर्णतः निर्यात कीमतों से करनी थी।

(टट) अपीलीय निकाय ने पाया कि ब्राजील के दृष्टिकोण का अभिप्राय होगा कि निर्धारण बहुत ही कम अवधि के आंकड़ों के आधार पर होगा। जांच की अवधि के भीतर एक समयावधि से आंकड़ों का चयन इस प्रकार विवेक के आधार पर करने की अनुमति से पाटन निर्धारण के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि पर जांचकर्ता प्राधिकारी के विश्वास करने के उद्देश्य बेकार होंगे। इसके अतिरिक्त, अपीलीय निकाय ने पाया कि जांच की अवधि एक निर्धारित समयावधि में संग्रहित आंकड़े प्रदान करती है जो अवधि जांचकर्ता प्राधिकारी को वह पाटन निर्धारण करने की अनुमति देती है जो कि समुचित मूल्यांकन को बिगाड़ने वाले बाजार उतार-चढ़ाव तथा अन्य स्थितियों के अध्यधीन कम होने की संभावना है। अपीलीय निकाय ने नोट किया कि जांच की अवधि पर मानकीकृत विश्वास, यद्यपि, पाटनरोधी करार द्वारा अवधि में निर्धारित नहीं है, जांचकर्ता प्राधिकारी और निर्यातकों को वर्तमान पाटन के निर्धारण के लिए सतत एवं उपयुक्त सिद्धांत का आश्वासन देती है जो पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने का इरादा है।

(ठठ) राइस के संबंध में मैक्सिको-पाटनरोधी उपायों में मैक्सिकन जांचकर्ता प्राधिकारी ने अपने पाटन निर्धारण के प्रयोजन के लिए मार्च से अगस्त, 1999 और अपने क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए मार्च से अगस्त, 1997, 1998 और 1999 को शामिल करते हुए जांच की अवधि के लिए आंकड़ों की जांच की। अपीलीय निकाय ने पाया कि मुद्दे के तथ्यों पर 1997, 1998 और 1999 की मार्च से अगस्त की अवधि से संबंधित जांच की अवधि घरेलू उद्योग की स्थिति की सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रदान नहीं करते और इस प्रकार अनुच्छेद 3.1 की अपेक्षा के अनुसार इसके परिणामस्वरूप वस्तुपरक जांच नहीं हुई।

(डड) आयुक्त अथवा सीमा शुल्क, बेंगलोर बनाम जी. एम. एक्सपोर्ट के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंतिम शुल्क की समाप्ति और अंतिम शुल्क लगाए जाने की तारीख के बीच की अंतराल अवधि के दौरान लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की वैधता निर्धारित करते समय पाया कि:

"ऐसी स्थिति में जहां भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है और उस संधि को आगे बढ़ाने में संविधि की जाती है, ऐसी संविधि के संकीर्ण निर्माण के बजाए उद्देश्यपूर्ण निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसी संविधि का निर्वचन पूर्व के घरेलू पूर्वोदाहरणों के बजाए सामान्य स्वीकृति के व्यापक सिद्धांतों पर निर्मित की जानी चाहिए जिनका आशय संविधि की अनिवार्यताओं को लेना हो न कि उनके असंगत हो।" (जोर शामिल किया गया)।

(ढढ) इस प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से माना है कि:

क. जब घरेलू संविधि (अर्थात् सीमा प्रशुल्क अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली) अस्पष्ट अथवा द्विअर्थी हो तो संधि संविधि के प्रावधानों के निर्माण में एक वैध सहायता होती है।

ख. निर्वचन का अर्थ सामान्य स्वीकार्यता के व्यापक सिद्धांतों पर लगाया जाना चाहिए जो कि संधि की अनिवार्यताओं के असंगत न हो।

(णण) यह स्पष्ट है कि यदि तीन माह की अल्पावधि जांच की अवधि के रूप में मानी जाती है तो वह कम से कम छः माह की लंबी जांच की अवधि की अपेक्षा रखने वाले सामान्य सिद्धांत के असंगत होगी तथा पाटनरोधी करार के तहत भारत द्वारा किए गए दायित्वों के लिए असंगत होगी। माननीय उच्च न्यायालय ने इस अपेक्षा का विशेष रूप से उल्लेख किया है कि पाटनरोधी नियमावली का निर्वचन एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया जाना अपेक्षित है जो संधि की अनिवार्यताओं के असंगत न हो।

(तत) भारतीय प्राधिकारी ने जांच की अवधि निर्धारित करते समय निरंतर पाटनरोधी समिति की सिफारिश को अपनाया है। विगत मामलों में डीजीएडी के अंतिम जांच परिणाम जांच की अवधि के निर्धारण के लिए पाटनरोधी परिपाटी की डब्ल्यूटीओ समिति की सिफारिश कर पूरी तरह से विश्वास किया गया। ऐसा कोई कारण नहीं है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी की इस सतत परिपाटी में विचलन हो।

(थथ) यूरोपीय संघ (ईयू) और यूनाइटेड स्टेट्स (यूएस) जैसे डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के कानून और परिपाटी यह दर्शाते हैं कि उन्होंने पाटनरोधी परिपाटी संबंधी समिति की सिफारिश का नियमित रूप से पालन किया है।

(दद) यूरोपीय संघ के आधारभूत पाटनरोधी विनियम में यह प्रावधान है कि "प्रतिनिधिकारक जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए एक जांच अवधि चुनी जाएगी जिसमें पाटन के मामले में सामान्यतः कार्यवाही शुरू होने से तत्काल पूर्व 6 माह से कम की अवधि शामिल नहीं होगी।"

(धध) यूएस पाटनरोधी विनियामवली में यह प्रावधान है कि "किसी पाटनरोधी जांच में सचिव सामान्यतः चार हाल ही में पूरे किए गए राजकोषीय तिमाहियों के दौरान व्यापारिक बिक्री (अथवा, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से आयातित सामान शामिल करते हुए किसी जांच में, दो हाल ही में पूरी की गई राजकोषीय तिमाहियां) की जांच करेंगे जो उस माह से पूर्व के माह के रूप में होंगी जिसमें याचिका दायर की गई थी अथवा सचिव ने स्वयं ही जांच शुरू की थी।"

(नन) उत्तरदाता प्राधिकारी से उपर्युक्त अनुरोधों पर विचार करने और स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करने का अनुरोध करते हैं कि इस जांच में जांच की अवधि प्रभावी रूप से तीन माह ही है और जांच की अवधि की इस छोटी सी अवधि पर पाटनरोधी करार के तहत भारत द्वारा किए गए दायित्वों के आलोक में पाटनरोधी नियमावली के ढांचे और स्कीम के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पाटनरोधी जांच में विश्वास नहीं किया जा सकता।

(पप) घरेलू उद्योग नोट करता है कि पाटन, क्षति और कीमत प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियों की पुष्टि करने का अनुरोध है तथा तदनुसार, निष्कर्ष निकालने का अनुरोध है। घरेलू उद्योग निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे अंतिम जांच परिणाम के पैरा 94 में नोट किए गए अपने अंतिम निष्कर्ष में संशोधन करें।

(टट) घरेलू उद्योग इस संबंध में अपने दावों को सिद्ध करने के लिए कोई कारण नहीं देता है। प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा नोट की गई प्राधिकारी की टिप्पणियां निर्दिष्ट प्राधिकारी का अंतिम जांच परिणाम नहीं है और इस कारण से घरेलू उद्योग द्वारा नोट किए गए निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं।

(ठठ) घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध करने के लिए कोई कानूनी अथवा वास्तविक आधार उपलब्ध नहीं कराया है कि जांच की अवधि पाटनरोधी जांच में केवल तीन महीने का हो सकता है और यह कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपने इस अंतिम जांच परिणाम में संशोधन करना चाहिए कि पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को निष्कर्ष के तौर पर स्थापित नहीं किया जा सकता है।

(डड) मैसर्स लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन जो निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने यह उल्लेख किया कि अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह निर्धारण किया है कि :

“सउदी अरब से आयातों और घरेलू उद्योगों को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को तीन महीने की निर्यात अवधि के आधार पर निष्कर्ष के रूप में स्थापित नहीं किया गया है।”

(ढढ) माननीय उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि कारणात्मक संबंध के बारे में प्राधिकारी की उपर्युक्त टिप्पणियां सही नहीं हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने पाटन और जांच के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निष्कर्ष के गलत होने के संबंध में टिप्पणी की है। माननीय उच्च न्यायालय ने नीचे दिए गए अनुसार टिप्पणी की है :

“सउदी अरब से निर्यातकों/ उत्पादकों द्वारा समान उत्पादों के पाटन से घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में जांच परिणामों को दर्ज करने से उसी नोट पर बात आगे नहीं बढ़ पाई और अजीब तरीके से इसमें एक विपरीत प्रतिक्रिया हुई जब यह अंतिम सिफारिश तक पहुंचा। ऐसा उनकी गलत धारणा के आधार पर हुआ कि पाटन की तीन महीने की अवधि किसी जांच परिणाम को रिकार्ड करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जैसा कि हमने पहले ही नोट किया है, 1995 की नियमावली ऐसा कोई अधिदेश नहीं है, दिनांक 20.11.2017 के अंतिम जांच परिणामों को अलग रख दिया गया है और यह मामला 1995 की नियमावली की योजना और ढांचा तथा इसके ऊपर की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए नए सिरे से विचार किए जाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास भेजा गया है।” (बल दिया गया है)

(णण) इस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने यह नोट किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के जांच परिणाम और सउदी अरब के निर्यातकों द्वारा पाटन के जांच परिणाम दिए हैं परंतु शुल्क की सिफारिश नहीं की है क्योंकि आयात तीन महीने की अवधि के लिए हो रहे थे। माननीय उच्च न्यायालय ने तदनुसार यह माना है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच समाप्त करने के लिए नियम 14 (ख) का सहारा नहीं ले सकते थे क्योंकि अनुच्छेद 14 (ख) में इस जांच को समाप्त करने के लिए एक आधार के रूप में पाटन अथवा साक्ष्य का अपर्याप्त साक्ष्य का प्रावधान है।

(तत) सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9ख और पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 3.5 और भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II, पैरा 5 के अनुसार, यह अवश्य दर्शाया जाना चाहिए कि यद्यपि घरेलू उद्योग को पाटन के प्रभावों के कारण क्षति हो रही है और यह कि उसी समय में पाटित आयातों को छोड़कर किसी ज्ञात कारकों से क्षति हुई है, पाटित आयातों का कारण पाटित आयात नहीं हैं। इस प्रकार से पाटन और क्षति के मौजूद होने के अलावा, इस नियमावली की संरचना और योजना में कारणात्मक संबंध को सिद्ध किया जाना अपेक्षित है। यदि पाटित आयातों और घरेलू उद्योग के बीच क्षति को कोई कारणात्मक संबंध नहीं है तब निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश नहीं कर सकते हैं।

(थथ) प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि कथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण वर्तमान मामले में पाटनरोधी करार और भारतीय पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संभव नहीं है क्योंकि (i) यह सिद्ध करना संभव नहीं है कि 4 वर्षों की क्षति की पूरी अवधि के दौरान और विशेष रूप जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हुई क्षति जनवरी से मार्च, 2016 की तीन महीनों की अवधि के दौरान हुए आयातों के कारण हुई है (ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटित आयातों को छोड़कर किसी ज्ञात कारकों के होने की जांच कर सकते हैं जो उसी समय घरेलू उद्योग को तीन महीने की अवधि के भीतर क्षति पहुंचा रहा है।

(दद) घरेलू उद्योग ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कारणात्मक संबंध के न होने के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कोई तथ्य, सूचना अथवा तर्क प्रस्तुत नहीं किया है और इस कारण से निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि वह कारणात्मक संबंध के बारे में अपने अंतिम जांच निष्कर्ष में संशोधन करें।

(धध) माननीय उच्च न्यायालय ने यह नोट किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी वास्तविक क्षति के खतरे का आकलन करने से इंकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में इसका दावा नहीं किया गया था।

(नन) प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि क्षति के खतरे का आकलन आयातों अर्थात् तीन महीने की अवधि के लिए अपर्याप्त सूचना के कारण वर्तमान मामले में संभव नहीं है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के पैरा (vii) में अपेक्षित है कि वास्तविक क्षति का खतरा तथ्यों के आधार पर होगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :

- i. भारत में आयातों में वृद्धि बहुत अधिक हुई है।
- ii. निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त रूप से तथा स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य अथवा आसन्न, वास्तविक वृद्धि हुई है।

iii. क्या आयात उन कीमतों पर हो रहा है जिसका घरेलू कीमतों पर बहुत अधिक न्यूनकारी अथवा दबावकारी प्रभाव पड़ेगा।

(पप) घरेलू उद्योग द्वारा उपर्युक्त में से किसी भी मानदंड के संबंध में कोई सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई है। क्षति के खतरे का कोई आकलन उपर्युक्त मानदंडों के संबंध में अंतिम आंकड़ों के अभाव में नहीं किया जा सकता है।

(फफ) मैसर्स लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन जो निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करते हैं निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे नए सिरे से इस बात का निर्धारण करें कि तीन महीने की जांच की अवधि की लघु अवधि के कारण तथा पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के न होने के कारण पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संबंध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ग. सउदी कयान द्वारा अनुरोध

13. अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार :

(क) सउदी एक्रिलिक एसिड कंपनी ("एस ए ए सी") और सादरा केमिकल कंपनी ("सादरा") के साथ साथ सउदी कयान ने मैसर्स सउदी बुटालोन कंपनी ("साबुको"), एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की है और इसमें प्रत्येक का एक तिहाई शेयर होल्डिंग है। सउदी कयान, सादरा और एस ए ए सी ने साबुको के साथ एक टोलिंग और प्रोसेसिंग करार (इसके पश्चात् "करार" के रूप में संदर्भित) किया है और यह इन उत्पादकों के लिए टोलिंग आधार पर ट्रोपिलीन को सामान्य बुटालोन और आइसो बुटालोन में परिवर्तित करता है।

((ख) यह स्पष्ट किया जाता है कि सउदी कयान ने जांच की अवधि (1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016) के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है। इसके साथ ही सउदी कयान सउदी अरब में किसी निर्यातक अथवा उत्पादक जिसमें जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है, से संबंधित नहीं है।

(ग) उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 22 के संबंध में, सउदी कयान ने संबद्ध जांच में प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश किए जाने की स्थिति में एक न्यू शिप्पर समीक्षा के लिए आवेदन करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है।

घ. सउदी अरब के राज दूतावास, नई दिल्ली द्वारा अनुरोध

(क) सउदी बुटालोन कंपनी ("साबुको") सामान्य बुटालोन का एक टॉल प्रोसेसर और तीन कंपनियों नामतः सादरा केमिकल कंपनी ("सादरा") सउदी कयान पेट्रो केमिकल कंपनी ("सउदी कयान") और सउदी एसिड एक्रिलिक कंपनी ("एस ए ए सी") द्वारा एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। सादरा, सउदी कयान और एस ए ए सी साबुको को कच्चे माल की आपूर्ति करता है, जहां इसे सामान्य बुटालोन में रूपांतरित किया जाता है। तब साबुको सामान्य बुटालोन को प्रत्येक कंपनी को उनमें से प्रत्येक द्वारा आपूर्ति किए गए कच्चे माल के अनुपात के अंतर्गत वापस करता है।

(ख) सामान्य बुटालोन का वाणिज्यिक उत्पादन 1 मार्च, 2016 सउदी अरब में शुरू हुआ। जांच उत्पादन का कुछ आयात सउदी अरब से भारत में जनवरी 2016 – मार्च 2016 के दौरान हुआ। तदनुसार सउदी अरब सामान्य बुटालोन का आयात भारत में जांच की अवधि के अंतिम तीन महीने के दौरान ही हुआ। सउदी अरब के उत्पादकों अर्थात् एस ए ए सी और सादरा, जिसने जांच की अवधि के दौरान भारत में सामान्य सामान्य बुटालोन का निर्यात किया था, पाटनरोधी जांच में अधिकारियों से उचित रूप में सहयोग किया है।

(ग) प्राधिकारी कृपया यह नोट करें कि सउदी अरब में सामान्य बुटालोन के लिए उत्पादन सुविधा स्थापित करने का प्राथमिक उद्देश्य बुटाइल ग्लाइकोन इथर (बी जी ई) और बुटाइल एक्रिलेट जैसे मूल्यवर्धित पब्लिक डाउनस्ट्रीम उत्पादों का आगे निर्माण करने और तब ऐसे मूल्यवर्धित/ डाउनस्ट्रीम उत्पादों का सउदी अरब से निर्यात करने के लिए सउदी अरब के भीतर सामान्य बुटालोन का खपत करना था। हालांकि, ऐसे मूल्यवर्धित/ डाउनस्ट्रीम उत्पादों का निर्माण करने के लिए संयंत्र पाटनरोधी जांच की जांच की अवधि के दौरान पूर्णरूप से चालू नहीं थी और इस कारण से सामान्य बुटालोन का निर्यात भारत सहित सउदी अरब से विभिन्न देशों में जांच की अवधि के दौरान किया गया था।

(घ) मूल्यवर्धित उत्पादों/ डाउनस्ट्रीम उत्पादों का निर्माण करने के लिए संयंत्र क्रमशः पाटनरोधी जांच की अवधि के बाद पूर्ण रूप से चालू हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप, सामान्य बुटालोन इन संयंत्रों द्वारा अधिक से अधिक खपत किया जाने लगा और सउदी अरब से सामान्य बुटालोन के निर्यातों में धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हो गई। इसे स्पष्ट रूप से नीचे उल्लिखित आयात आंकड़ों द्वारा देखा जा सकता है, जो यह दर्शाता है कि भारत में सउदी अरब से सामान्य बुटालोन के आयातों में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बहुत अधिक गिरावट आई और यह चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ण रूप से बंद हो गया है।

सउदी अरब से सामान्य बुटानोल का आयात

विवरण	मात्रा (मी. ट.) जनवरी 2016 – मार्च 2016	मात्रा (मी.ट.) अप्रैल 2016 – मार्च 2017	मात्रा (मी.ट.) अप्रैल 2017 – मार्च 2018	मात्रा (मी.ट.) अप्रैल 2018– जुलाई 2018*
सउदी अरब के साम्राज्य से भारत में आयात	8,791	27,494	18,013	शून्य

स्रोत : निर्यात आयात आंकड़ा बैंक (वाणिज्य विभाग, भारत)

*** जुलाई, 2018 तक की रिपोर्ट के अनुसार**

(इ) यह नोट किया जाता है कि भारतीय घरेलू उद्योग यह दावा करने के लिए संक्रमण काल की अवधि पर विचार कर रहा है जब सामान्य बुटानोल का निर्यात सउदी अरब में किया गया था कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा है। घरेलू उद्योग का दावा पूर्ण तथ्यों और हाल के आयात संबंधी आंकड़ों के आधार पर नहीं है और इस कारण से इसका कोई औचित्य नहीं है।

ड प्राधिकारी द्वारा जांच

14. प्राधिकारी जांच के पूर्व के राउण्ड के दौरान किए गए अनुरोधों तथा घरेलू उद्योग और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा वर्तमान मामले के दौरान किए गए अनुरोधों तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों पर विचार करते हैं। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसार और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग के क्षति की जांच की है।

15. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह विश्लेषण जांच की अवधि के पिछले तीन महीनों सहित जांच के समग्र अवधि के लिए की गई है। जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों तथा घरेलू उद्योग पर इसके प्रभाव के विश्लेषण को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के निर्देशों को ध्यान में रखकर इस जांच परिणाम में अंतिम पैराओं में नोट किए गए अनुसार क्षति के खतरे के पहलू के साथ न्यायोचित ठहराया गया है।

16. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश के लिए तीन पूर्व शर्तें अर्थात् संबद्ध देश से पाटन, घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति और क्षति एवं पाटन के बीच कारणात्मक संबंध हैं। बाद के अनुच्छेदों में, प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध के मुद्दे का विश्लेषण किया है। प्राधिकारी नियमानुसार क्षति के पहलुओं की जांच करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखकर वास्तविक क्षति के अलावा, वास्तविक क्षति के खतरे की भी जांच की है। घरेलू उद्योग के मौजूद होने और लंबे समय से विप्लवाधीन उत्पाद का उत्पादन करने के साथ उद्योग की स्थापना को विप्लव करने की प्रक्रिया यहां संगत प्रतीत नहीं होती है।

17. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह मात्रा और कीमत के प्रभाव दोनों की जांच करने के बाद क्षति की जांच करे। क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव और (ख) घरेलू उद्योग पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव दोनों की वस्तुपरक जांच शामिल है। पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस तथ्य पर विचार करे कि क्या या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह इस तथ्य पर विचार करे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों में बहुत अधिक सीमा तक मंदी आती अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाती जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक सीमा तक हुई होती।

18. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-11 के पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लेख है :

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

19. प्राधिकारी ने यह हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों में दिए गए तर्कों और तथ्यों पर वस्तुपरक रूप से विचार करते हुए क्षति संबंधी मानदंडों की जांच की है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणाम जारी करने के पूर्व प्रकटन विवरण की टिप्पणियों की उपयुक्त रूप से जांच की थी।

ज. मांग का आकलन

20. संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग का निर्धारण सभी देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के साथ घरेलू समान उत्पाद की घरेलू बिक्री को जोड़कर किया गया है। क्षति के वर्तमान विश्लेषण के उद्देश्य से प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त किए गए लेन देन वार संबंधी आयात आंकड़ों पर विचार किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

मांग	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. ट.	14,472	6,425	4,037	11,154
आयात – संबद्ध देश	मी. ट.	0	0	0	8,791
आयात – पाटनरोधी उपाय सहित देश	मी. ट.	31,929	42,015	55,243	50,606
आयात – अन्य देश	मी. ट.	205	750	0	0.32
मांग/ खपत	मी. ट.	46,606	49,190	59,280	70,551
प्रवृत्ति		100	106	127	151

*जांच की अवधि : 2015-16

झ. पाटित आयातों की मात्रा संबंधी प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव**(क) आयात मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा**

21. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से इस तथ्य पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सउदी अरब से संबद्ध वस्तुओं का आयात जांच की अवधि में जनवरी 2016 से ही शुरू हुआ। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात दिसंबर, 2015 तक नहीं हुआ था।

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	जांच की अवधि
आयात -					
संबद्ध देश	मी. ट.	0	0	0	8,791
पाटनरोधी उपायों सहित देश	मी. ट.	31,929	42,015	55,243	50,606
अन्य देश	मी. ट.	205	750	-	0.32
कुल आयात	मी. ट.	32,134	42,765	55,243	59,397
मांग	मी. ट.	46,606	49,190	59,280	70,551
उत्पादन	मी. ट.	14,409	5,484	4,203	11,080
की तुलना में संबद्ध आया -					
कुल आयात	%	संबद्ध देश से कोई आयात नहीं			15%
खपत	%				12%
उत्पादन	%				79%

22. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध-11 (ii) में निम्नानुसार निर्धारित है :

“जहां तक नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी

अधिक हास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।”

23. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण और कीमत पर दबाव, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

(क) कीमत में कटौती

24. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति, व्यापार के उसी स्तर पर सभी छूट और करों के निवल के आधार पर की है। यह तुलना दर्शाती है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश के मूल के संबद्ध वस्तुओं का आयात भारतीय बाजार में उन कीमतों पर किया गया था जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों की तुलना में कम थी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि प्राधिकारी ने कम कीमत पर बिक्री/कीमत में कटौती के धनात्मक अथवा ऋणात्मक होने के रूप में स्पष्ट नहीं किया है। प्राधिकारी यह पुष्टि करते हैं कि तालिका में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से धनात्मक कम कीमत पर बिक्री और कीमत में कटौती को संसुचित करता है।

विवरण	इकाई	जांच की अवधि
निवल बिक्री कीमत	रु./ किग्रा.	***
पहुंच कीमत	रु./ किग्रा.	39.43
कीमत में कटौती	रु./ किग्रा.	***
कीमत में कटौती	%	25-35%
कीमत में कटौती	रेंज (%)	25-35%

(ख) कम कीमत पर बिक्री

25. प्राधिकारी संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कम कीमत पर बिक्री की मात्रा को नोट करते हैं। इस मुद्दे से, घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है। हालांकि, क्या इस कम कीमत पर बिक्री का कारण स्पष्ट रूप से पाटित आयात हैं, के लिए कारणात्मक विश्लेषण की आवश्यकता है जिसका उल्लेख इस जांच परिणाम के अंतिम अनुच्छेदों में किया गया है।

विवरण	इकाई	जांच की अवधि
क्षति रहित कीमत	रु./ किग्रा.	***
पहुंच कीमत	रु./ किग्रा.	39.43
कम कीमत पर बिक्री	रु./ किग्रा.	***
कम कीमत पर बिक्री	%	55-75%
कम कीमत पर बिक्री	रेंज (%)	55-75%

(ग) कीमत न्यूनीकरण/ दबाव

26. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से की पाटित आयातों का घरेलू कीमतों पर न्यूनकारी अथवा दबावकारी प्रभाव पड़ रहा है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव बहुत अधिक हद तक कीमतों को कम करेगा अथवा कीमत में वृद्धि को रोकेगा जो अन्यथा बहुत अधिक सीमा तक हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों पर विचार किया। इस स्थिति को नीचे दी गई तालिका के अनुसार दर्शाया गया है :

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	जांच की अवधि
बिक्री कीमत	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	92	73

बिक्री की लागत	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	113	79

27. प्राधिकारी ये नोट करते हैं कि सउदी अरब से आयात भारत में केवल जांच की अवधि के दौरान हुआ। यह आयात जनवरी, 2016 से शुरू हुआ। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागतों में 2014-15 में 113 सूचकांकों से कम होकर जांच की अवधि के दौरान 79 सूचकांक हो गया। उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की कीमत 92 सूचकांकों से कम होकर 73 सूचकांक हो गया।

(ट) घरेलू उद्योग का आर्थिक मानदंड

28. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादको पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिसका उपयोग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री में वास्तविक और संभावित गिरावट, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता का उपयोग शामिल हो; वे कारक जो घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव डालते हों, पाटन के मार्जिन का आकार; नकदी के प्रभाव पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता का एक वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित क्षति संबंधी विभिन्न मानदंडों की चर्चा नीचे की गई है।

(क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

29. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता एवं क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है :

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	जांच की अवधि
क्षमता	मी. ट.	22,500	22,500	22,500	22,500
उत्पादन	मी. ट.	14,409	5,484	4,203	11,080
क्षमता उपयोग	%	64.04%	24.37%	18.68%	49.24%
घरेलू बिक्री	मी. ट.	14,472	6,425	4,037	11,154
मांग	मी. ट.	46,606	49,190	59,280	70,551

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सउदी अरब से भारत में आयात केवल जांच की अवधि के दौरान हुआ। यह आयात जनवरी 2016 से शुरू हुआ। उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन ने जांच की अवधि के दौरान विशेषकर जांच की अवधि के दो वर्ष पूर्व की तुलना में उत्पादन, बिक्री की मात्रा और क्षमता के उपयोग में सुधार दर्शाया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षमता आधार वर्ष से जांच की अवधि तक वही रही।

(ख) लाभ, लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

31. घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत, बिक्री की कीमत, लाभ/ हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय का विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है :

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	113	79
बिक्री कीमत	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	92	73
लाभ/ हानि (प्रति इकाई)	रु./ किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-155	-732	-268

लाभ/ हानि कुल	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-69	-204	-206
ब्याज से पहले लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-58	-305	-280
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-82	-308	-290
निवेश पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-67	-360	-379

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सउदी अरब से भारत में आयात जांच की अवधि के दौरान ही हुई। यह आयात जनवरी 2016 से शुरू हुआ। उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की क्षति की समग्र अवधि दौरान तथा जांच की अवधि में भी हानि हो रही थी। घाटा एवं नकद घाटा वर्ष 2014-15 के दौरान सबसे अधिक हुआ था। घाटा तथा नकद घाटा जांच की अवधि में जारी रहा लेकिन जांच की अवधि के दौरान इसमें कमी आई।

(ग) बाजार हिस्सा

33. संबद्ध देश से आयातों और घरेलू उद्योग के हिस्से नीचे दिए गए अनुसार हैं :

बाजार हिस्सा	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	31%	13%	7%	16%
संबद्ध देश	%	0%	0%	0%	12%
पाटनरोधी उपाय सहित देश	%	69%	85%	93%	72%
अन्य देश	%	0%	2%	0%	0%

34. उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच की अवधि में सुधार हुआ है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से भारत में आयात केवल जांच की अवधि के दौरान हुआ था और इसने जांच की अवधि के दौरान 12 प्रतिशत बाजार हिस्सा प्राप्त किया।

(घ) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

35. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति नीचे दी गई है :

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	जांच की अवधि
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	97	93
मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***
मजदूरी	सूचीबद्ध	100	103	112	107
उत्पादकता प्रति दिन	मी. ट. प्रति दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	38	29	77
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	39	30	82

36. कर्मचारी के स्तर में क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान मामूली गिरावट आई है। हालांकि, प्रति दिन उत्पादकता और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में जांच की अवधि के दौरान मामूली सुधार हुआ है।

(ङ) माल भंडार

37. संबद्ध वस्तुओं के माल भंडार से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई हैं :

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	जांच की अवधि
औसत माल भंडार	मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	50	11	16

38. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के औसत माल भंडार स्तर में जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक गिरावट आई है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग जो भी यह उत्पादन करता है उसकी बिक्री करने में सक्षम है।

(च) विकास

39. घरेलू उद्योग के विकास से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं :

विकास	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	जांच की अवधि
उत्पादन	मी. ट.	-	-62%	-23%	164%
घरेलू बिक्री	मी. ट.	-	-56%	-37%	176%
बिक्री की लागत	रु./ किग्रा.	-	12%	1%	-30%
बिक्री की कीमत	रु./ किग्रा.	-	10%	-16%	-21%
घाटा	रु./ किग्रा.	-	55%	373%	-63%
निवेश पर आय	%	-	1%	-6%	0%
बाजार हिस्सा	%	-	-18%	-6%	9%

40. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मात्रा संबंधी मानदंडों जैसे उत्पादन, बिक्री की मात्रा, बाजार हिस्सा आदि के संबंध में घरेलू उद्योग का विकास जांच की अवधि में सुधार को दर्शाता है। कीमत संबंधी मानदंडों जैसे लाभ, निवेश पर आय के संबंध में सूचना यह दर्शाता है कि ये मानदंड क्षति की जांच की समग्र अवधि और जांच की अवधि के दौरान ऋणात्मक रही हैं और जांच की अवधि के दौरान बिक्री की लागत में गिरावट आई। हालांकि, सउदी अरब से आयात जनवरी 2016 में ही शुरू हुआ।

(छ) पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता

41. प्राधिकारी नोट करते हैं संबद्ध देश से आयात जांच की अवधि के पिछले तीन महीनों के दौरान ही हुए हैं। घरेलू उद्योग को क्षति की जांच की अवधि और जांच की अवधि की पूरी अवधि के दौरान घाटा होता रहा है।

(ज) पाटन मार्जिन और पाटन मार्जिन का स्तर

42. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयात इस देश में पाटित कीमतों पर हो रहा है और यह कि पाटन का मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है।

(झ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

43. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति की पूरी अवधि और जांच की अवधि में घाटा होता रहा है। घरेलू उद्योग की कीमतों पर संबद्ध देश से आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के कारण 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक के दौरान दबाव बना रहा। इन तीन महीने की अवधि के दौरान भी जब संबद्ध देश से भारत में आयात हुआ, तब भी यह अन्य देशों जो भारतीय बाजार में प्रमुख भागीदार थे, द्वारा निर्धारित समय पर भी प्रचलित कीमतों पर हुआ।

(ज) क्षति संबंधी टिप्पणी

44. संबद्ध देश से आयात भारत में जांच की अवधि के पिछले तीन महीने के दौरान हुआ था। संबद्ध देश से पिछले तीन महीने तथा जांच की अवधि के पहले नौ महीनों के दौरान कोई आयात नहीं हुआ था। घरेलू उद्योग की कीमतों पर क्षति की जांच की समग्र अवधि और जांच की अवधि के दौरान दबाव बना रहा। यह स्पष्ट ही है कि घरेलू उद्योग की 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 के दौरान दबाव न्यून कीमतें संबद्ध देश से आयातों को छोड़कर अन्य कारणों से थी।

45. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में विक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्सा और माल भंडार के संबंध में जांच की अवधि के दौरान सुधार दर्शाया है।

46. घरेलू उद्योग को क्षति की पूरी अवधि और जांच की अवधि में भी घाटा उठाना पड़ता रहा है। घाटा और नकद घाटा वर्ष 2014-15 के दौरान सबसे अधिक था। घाटा और नकद घाटे में जांच की अवधि के दौरान कमी आई।

(ट) कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को क्षति इसके आपूर्तिकर्ता अर्थात् एच पी सी एल की संयंत्र के आग की घटनाओं के कारण बंद होने के कारण प्रोपिलीन के एकमात्र स्रोत पर उनकी निर्भरता, जांच की अवधि में अन्य देशों से पाटन और अन्य कारकों जैसे मांग और आपूर्ति में भारी अंतर होने के कारण आयात करने की अनिवार्यता के कारण हुई है। प्राधिकारी ने पाटन और परिणामी क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन करते समय इन पहलुओं पर विचार किया।

48. यह नोट किया गया है कि सउदी अरब से आयात जनवरी 2016 में शुरू हुआ और संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा जांच की अवधि के दौरान कुल बाजार हिस्से का 12 प्रतिशत था। जांच की अवधि के पहले 9 महीने अर्थात् अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 तक के दौरान कोई आयात नहीं हुआ था।

49. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II पैरा (v) में नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित है:

"यह अवश्य दर्शाया जाना चाहिए कि पाटित आयातों, उपर्युक्त पैरा ii और (iv) में यथा निर्धारित पाटन के प्रभावों के द्वारा घरेलू उद्योगों को क्षति उत्पन्न कर रही है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध को दर्शाना निर्विण्ट प्राधिकारी के सक्षम संगत साक्ष्य की जांच के आधार पर होगा। निर्विण्ट प्राधिकारी पाटित आयातों के अलावा किसी ज्ञात कारकों की भी जांच करेगा, जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं और इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति को अवश्य ही पाटित आयात का कारण नहीं माना जाना चाहिए। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, में अन्य बातों के साथ साथ पाटित कीमतों पर न बेची गई आयातों की कीमतों और मात्रा, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन और उत्पादकता हो सकते हैं।"

50. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान, सउदी अरब अर्थात् संबद्ध देश से आयात पिछले तीन महीनों अर्थात् जनवरी – मार्च, 2016 के दौरान हुई। जांच की अवधि के पहले 9 महीने में और पूर्ववर्ती 3 वर्षों में, आयात मुख्य रूप से मलेशिया, यूरोपीय संघ, यू एस ए, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर से हुआ था, जिस पर अप्रैल, 2016 अर्थात् जांच की अवधि के बाद पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन देशों में सभी / कुछ से आयात कीमत अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है जो घरेलू उद्योग के उसी अवधि में गिरते हुए निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) में प्रकट किया गया है।

51. प्राधिकारी ने अनेक कारकों को उपयुक्त रूप से अलग अलग करने की पुनः जांच की थी ताकि संबद्ध देश से आयातों से घरेलू उद्योगों को क्षति के खतरे के साथ साथ कारणात्मक संबंध के पहलू का मूल्यांकन किया जा सके। प्राधिकारी ने पुनः इस तथ्य की जांच की थी क्या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत नीचे सूचीबद्ध अन्य कारकों का पाटन एवं घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच के लिए घरेलू उद्योग को क्षति में कोई अंशदान हो सकता था।

(क) तृतीय देशों से आयात

52. प्राधिकारी ने मूल जांच में लेन देन वार आधार पर डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त संबद्ध वस्तुओं के आयात संबंधी आंकड़ों की जांच की थी। प्राधिकारी यह स्मरण करते हैं कि सउदी अरब से आयात भारत में केवल जांच की अवधि के दौरान हुआ। यह आयात जनवरी 2016 से शुरू हुआ। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को 2012-13, 2013-14, 2014-15 और जांच की अवधि के दौरान हानि उठानी पड़ रही थी। जांच की अवधि के पहले 9 महीने और पिछले तीन वर्षों में, आयात मुख्य रूप से मलेशिया, यूरोपीय संघ, यू एस ए, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर से हुए थे जिन पर अप्रैल 2016 अर्थात्

जांच की अवधि के पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी जांच की अवधि पिछले तीन महीनों के लिए संबद्ध देश और अन्य देशों से कीमत की प्रवृत्ति की पुनः नीचे दिए गए अनुसार की थी।

53. जांच की अवधि के पिछले तीन महीने (जनवरी से मार्च 2016) से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं, जिसका उल्लेख मूल जांच में भी किया गया था :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	जनवरी से मार्च 16
1	पहुंच कीमत – सउदी अरब	रु./ किग्रा.	39.43
2	पहुंच कीमत – वे देश जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता है		
क	यूरोपीय संघ	रु./ किग्रा.	59.19
ख	मलेशिया	रु./ किग्रा.	37.83
ग	दक्षिण अफ्रीका	रु./ किग्रा.	39.75
घ	संयुक्त राज्य अमेरिका	रु./ किग्रा.	38.38
ङ	सिंगापुर	रु./ किग्रा.	38.36
3	एन एस आर	रु./ किग्रा.	***
4	कीमत में कटौती		
क	सउदी	रु./ किग्रा.	***
ख	यूरोपीय संघ	रु./ किग्रा.	***
घ	मलेशिया	रु./ किग्रा.	***
ङ	दक्षिणी अफ्रीका	रु./ किग्रा.	***
च	संयुक्त राज्य अमेरिका	रु./ किग्रा.	***
ज	सिंगापुर	रु./ किग्रा.	***

उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि मलेशिया, यू एस ए, सिंगापुर से उन कीमतों पर हुआ जो संबद्ध देश की कीमतों की तुलना में कम थी और दक्षिण अफ्रीका से आयात लगभग उसी कीमत पर हुआ जिस पर संबद्ध देश से जनवरी 2016 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान हुआ था। इस कारण से मलेशिया, यू एस ए, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर ने घरेलू उद्योग पर कीमत का दबाव बनाये रखना जारी रखा है और घरेलू उद्योग में कीमतों का निर्धारण किया है। सउदी अरब से भारत में आयात मांग और आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए किया हुआ और यह आयात उस समय प्रचलित कीमतों पर हुआ जिन्हें मलेशिया, यू एस ए, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर जैसे प्रमुख निर्यातक देशों द्वारा तय किया गया था। प्राधिकारी ने इस वापसी जांच के दौरान आगे संबद्ध देश से यथा उपलब्ध जांच की अवधि के पश्चात् के आयात आंकड़ों के आधार पर क्षति की जांच के खतरे के अंतर्गत आयातों के व्यवहार की जांच की है।

(ख) मांग में संकुचन

54. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग ने क्षति के अवधि के दौरान बहुत अधिक सुधार दर्शाया है। मांग में संभावित संकुचन घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाया होगा।

(ग) विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई होगी।

(घ) प्रौद्योगिकी में विकास

56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी और निर्माण की प्रक्रिया की पूर्ण रूप से तुलना संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रथा से की जा सकती है।

(ङ) खपत के पैटर्न में परिवर्तन

57. घरेलू उद्योग उन संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है जिनका आयात भारत में किया गया है। खपत के पैटर्न में संभावित परिवर्तन ऐसा कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति हुई होगी।

च) निर्यात कार्य निष्पादन

58. याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति घरेलू प्रचालन के कारण ही हुई है।

झ) अन्य उत्पादों के संबद्ध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन

59. अन्य उत्पादों जिनका उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा किया जा रहा है, के कार्य निष्पादन ने घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन के संबंध में प्राधिकारी द्वारा किए गए आकलन को प्रभावित नहीं किया है। प्राधिकारी द्वारा विचार की गई सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध में है।

ज) क्षति मार्जिन

60. प्राधिकारी नोट करते हैं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 31 जुलाई, 2018 के आदेश में क्षति मार्जिन की मात्रा के संबंध में कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं की है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान कार्यवाहियों में क्षति मार्जिन के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है। इस कारण से प्राधिकारी वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में क्षति के मार्जिन की मात्रा के संबंध में अपनी जांच पर पुनः विचार नहीं कर रहे हैं।

ड) क्षति का खतरा और जांच की अवधि के बाद का विश्लेषण

61. माननीय उच्च न्यायालय के अपने दिनांक 31 जुलाई, 2018 के आदेश के विशिष्ट निदेशों को ध्यान में रखकर, प्राधिकारी ने इस तथ्य का विश्लेषण किया है कि क्या संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे की संभावना हो सकती है।

62. क्षति के खतरे के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II पैरा (vii) में नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित है :

“(vii) वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों के आधार पर और न कि केवल आरोपों, अनुमानों अथवा दूर की संभावना के आधार पर होगा। परिस्थितियों में बदलाव जिससे ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसमें पाटन से क्षति पहुंचेगी, स्पष्ट रूप से प्रत्याशित और आसन्न होनी चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे के होने के संबंध में निर्धारण करने में, निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ साथ ऐसे कारकों पर विचार करेगा जैसे :

(क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि का अधिकतम दर जो पर्याप्त रूप से बड़े हुए आयात की संभावना को दर्शाता हो;

(ख) किसी अतिरिक्त निर्यातों को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता पर विचार करते हुए भारतीय बाजारों को पर्याप्त रूप से बड़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना को दर्शाते हुए निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त रूप से स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य अथवा आसन्न, वास्तविक वृद्धि;

(ग) क्या आयात उन कीमतों पर हो रहा है जिनका घरेलू कीमतों पर पर्याप्त न्यूनकारी अथवा दबावकारी प्रभाव पड़ेगा और जिससे संभवतः आगे आयातों के लिए मांग में वृद्धि होगी;

(घ) उस वस्तु जिसकी जांच की जा रही है, का माल भंडार।”

63. वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में प्राधिकारी नीचे दिए गए अनुसार नोट करते हैं :

(क) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयात जांच की अवधि के पिछले तीन महीने अर्थात् जनवरी 2016 से मार्च 2016 के दौरान हुई। इस तथ्य की जांच करने के उद्देश्य से की संबद्ध देश से भारत में पाटित आयातों की वृद्धि बहुत अधिक दर पर हुई है, आयातों की तुलना आधार वर्ष से किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान परिदृश्य में, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान कोई आयात नहीं हुआ है। जांच की अवधि के दौरान होने वाला कोई आयात इस कारण से स्वतः वृद्धि को दर्शायेगा। अतः जांच की अवधि के पिछले तीन महीनों के दौरान हुए आयातों से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पायेगा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मूल जांच में, जो अंत में दिनांक 28 नवंबर, 2017 के अंतिम जांच परिणाम के रूप में समाप्त हुई, में घरेलू उद्योग की याचिका में, याचिकाकर्ता ने वास्तविक क्षति और न कि क्षति के खतरे का दावा किया था। दिनांक 31

जुलाई, 2018 के माननीय उच्च के आदेश को देखते हुए प्राधिकारी ने जांच की अवधि के बाद की अवधि का इस बात की जांच करने के लिए विश्लेषण किया कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का कोई खतरा है।

घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध देश से जनवरी, 2016 से मार्च 2016 तक बहुत अधिक आयात हुआ है और सउदी अरब में संबद्ध वस्तुओं की क्षमता जांच की अवधि के बाद के दौरान आयातों के लिए बहुत अधिक है। हालांकि, दूसरी ओर सउदी अरब के साम्राज्य के अनुरोधों में यह उल्लेख किया है कि 330000 क्षमता की क्षमता के उद्देश्य का उपयोग गुप्त रूप से मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे बुटाइल ग्लाइकोल इथर (बी जी ई), बुटाइल एक्रिलेट आदि का निर्माण करने के लिए किया जाना है। उपर्युक्त अनुरोधों की जांच करने के उद्देश्य से प्राधिकारी ने जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। नवीनतम जी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार, संबद्ध देश से आयात जांच की अवधि के पिछले तीन महीनों अर्थात् जनवरी, 2016 के दौरान ही शुरू हुआ। जांच की अवधि के बाद के आयातों की प्रवृत्ति नीचे दी गई है।

विवरण	मात्रा (मी. ट.) 2016 - 17	मात्रा (मी. ट.) 2017 - 18	मात्रा (मी. ट.) 2018 - 19
अप्रैल जून -	9372	5893	शून्य
जुलाई - सितंबर	8147	5567	शून्य
अक्टूबर दिसंबर -	4447	5983	-
जनवरी मार्च -	5529	570	-
कुल	27495	18013	शून्य

(ख) प्राधिकारी ने निर्यातक के सत्यापन के दौरान यह नोट किया था कि उत्पादक का वाणिज्यिक उत्पादन 1 मार्च, 2016 को ही शुरू हुआ। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि साबुको एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसे सादारा केमिकल कंपनी, सउदी एक्रिलिक एसिड कंपनी और सउदी कयान पेट्रो केमिकल कंपनी द्वारा बनाई गई है, जिसमें प्रत्येक का एक तिहाई शेयर होल्डिंग है। साबुको प्रोपिलीन को सामान्य बुटालोन और आइसो बुटालोन में तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों के लिए टॉलिंग आधार पर परिणत करता है।

(ग) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सउदी अरब से भारत में आयात केवल जांच की अवधि के दौरान हुआ है। यह आयात जनवरी 2016 से शुरू हुआ और घरेलू उद्योग को क्षति की समग्र अवधि तथा जांच की अवधि में भी घाटा उठाना पड़ रहा था। घाटे तथा नकद घाटे वर्ष 2014-15 के दौरान सबसे अधिक था। इन घाटों में जांच की अवधि के दौरान कमी आई। आगे प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागतों में 2014-15 में 113 सूचकांक जांच की अवधि के दौरान 79 सूचकांक तक गिरावट हुई। उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 92 सूचकांक से 73 सूचकांक तक गिरावट आई।

(घ) प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भाग लेने वाले उत्पादकों के पास उपलब्ध माल भंडार को सिद्ध करना वास्तविक खतरे की क्षति को सिद्ध करने के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण थी जिसके लिए संबद्ध देश से आयातों की उचित अवधि की आवश्यकता होगी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि साबुको की संबद्ध वस्तुओं की क्षमता 330000 मी. ट. है जबकि संबद्ध देश से जांच की अवधि के दौरान आयात कुल क्षमता का 2.6 प्रतिशत, 2016-17 में कुल क्षमता का 8.33 प्रतिशत, 2017-18 में कुल क्षमता का 5.45 प्रतिशत और 2018-19 में कुल क्षमता का शून्य प्रतिशत आयात है। इस कारण से प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे को निर्णायक रूप से सिद्ध करने के लिए जांच की अवधि के बाद की प्रवृत्ति पर विचार किया।

(ण) प्रकटन पश्चात् टिप्पणियां

(क) घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध :

64. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए थे :

(i) प्राधिकारी ने प्राथमिक रूप से निम्नलिखित आधारों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने से पूर्व में इन्कार किया था।

क. केवल एक महीने के लिए वाणिज्य उत्पाद भी कार्यरत उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए एक प्रतिनिधित्व से संबंधित और वास्तविक सामान्य मूल्य के निर्धारण में बाधा पैदा करता है।

ख. सउदी अरब से संबद्ध वस्तुओं की जांच की अवधि में निर्यात के पिछले तीन महीनों की अवधि घरेलू उद्योग को क्षति का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

ग. सउदी अरब से आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को निर्यात की तीन अवधि के आधार पर निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं किया गया है।

(ii) हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय ने नीचे दिए गए अनुसार फैसला दिया :

"उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी सउदी अरब से निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा समान उत्पादों के पाटन से घरेलू उद्योग को हुई क्षति के समर्थन में जांच परिणाम को रिकार्ड करने के बाद उसी नोट पर आगे बढ़ने में असफल रहे और अजीब तरीके से इसके विपरीत कार्यवाही हुई जब यह अंतिम सिफारिश की।"

"विचाराधीन मामले में जैसा कि ऊपर नोट किया गया है निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड किया गया जांच परिणाम स्पष्ट रूप से सउदी अरब के निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा तीन महीने की छोटी अवधि के भीतर पाटन के पर्याप्त साक्ष्य और उसके द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को स्पष्ट रूप से दर्शाया है। इस कारण से निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांच को समाप्त किए जाने के औचित्य को बताने के लिए इस उप नियम का सहारा नहीं ले सकते थे। वास्तव में नियम 14 जिसमें जांच को समाप्त करने संबंधी प्रावधान है, में किसी भी उप नियम की प्रयोज्यता नहीं थी जिसके द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसा कदम उठा सकते थे।"

(iii) पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एकमात्र मुद्दा तीन महीने की कथित लघु अवधि और इस कारण से कथित रूप से कारणात्मक संबंध का नहीं होना था। हालांकि, पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश से इन्कार करने के लिए प्राधिकारी का यह आधार उच्च न्यायालय द्वारा उपयुक्त/सही नहीं माना गया था। मामला ऐसा होने के कारण अब यह उपयुक्त नहीं होगा कि उन तथ्यों पर फिर से विचार किया जाए और घरेलू उद्योग को संरक्षण से इन्कार किया जाये। इस प्रकटन विवरण ने तीन महीने की अवधि का बार बार संदर्भ लेते हुए और व्यक्त यप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उक्त अवधि क्षति अथवा कारणात्मक संबंध को मानने के लिए पर्याप्त नहीं है, घरेलू उद्योग को क्षति का विश्लेषण किया है। प्रकटन विवरण में उच्च न्यायालय के आदेश की उपेक्षा की गई है जो एक बार फिर उसी आधार को मानने के समान है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा सही नहीं माना गया था।

(iv) प्रकटन विवरण निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस तथ्य पर विचार करने का संकेत देता है कि चूंकि संबद्ध पाटित आयात जांच की अवधि के 12 महीने में से जांच की अवधि के तीन महीने में ही मौजूद है और इसके अलावा, किसी भी घरेलू उद्योग को सउदी अरब से आयात के शुरू होने के पूर्व के 9 महीने में भी क्षति उठानी पड़ रही थी, इसका आशय यह है कि "अन्य कारक" हैं जो घरेलू उद्योग क्षति पहुंचा रहे हैं। याचिकाकर्ता निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वे कृपया ऐसे आवश्यक तथ्यों को प्रकट करें यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह पाया है कि कुछ अन्य कारक हैं जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

(v) निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करे जिसमें यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि जांच की अवधि में तीन महीने का आयात पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त है। प्राधिकारी ने सकारात्मक निर्धारण किया है और वास्तव में सउदी अरब से निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात के संबंध में बहुत अधिक पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस संबंध में यह भी टिप्पणी की है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड किए गए जांच परिणाम स्पष्ट रूप से पाटन के पर्याप्त साक्ष्य को दर्शाते हैं और घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। कानून के अंतर्गत कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि जांच की समग्र अवधि में पाटित आयात को मौजूद रहना चाहिए।

(vi) विचाराधीन आवश्यक तथ्यों के प्रकटन का प्रावधान वाले नियम 16 का आशय यह है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी "विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों को प्रकट करेंगे जो इसके निर्धारण का आधार होगा। प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे केवल उन तथ्यों के आधार पर निर्धारण करें जिसे अंतिम जांच परिणाम में प्रकट किया गया है। इस कारण से नियम 16 पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वह कृपया उन तथ्यों पर विचार करें जिन्हें विचाराधीन आवश्यक तथ्यों की उच्चतर सीमाओं के रूप में प्रकटन विवरण में प्रकट किया गया है। इसके अलावा, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने किसी अन्य आवश्यक तथ्य को पाया है तब याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग को इसके प्रकटन का अनुरोध करते हैं।

(vii) प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वे कृपया इस मामले में पूर्व में जारी किए गए अंतिम जांच परिणाम का संदर्भ लें। यह स्पष्ट है कि तथ्यों में बिना किसी परिवर्तन के, प्राधिकारी ने उस तरीके से बिल्कुल हटकर वर्तमान प्रकटन में क्षति का विश्लेषण किया है जिस तरीके से इसने मूल जांच परिणाम में किया था। आयात की मात्रा, संबद्ध देश का हिस्सा, कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री और जांच की अवधि के बाद विश्लेषण के संबंध में विश्लेषण अलग है और इसमें इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं होने पर विचार नहीं किया गया है।

(viii) पूर्व के जांच परिणाम में क्षति के संबंधी निष्कर्ष के संबंध में, प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के पैरा 47 से 49 में प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया है। प्राधिकारी द्वारा किए गए पैरा 77 से 79 में पूर्व जांच परिणाम में अलग अलग किया गया क्षति विश्लेषण वर्तमान प्रकटन विवरण में पूर्ण रूप से गायब है। प्राधिकारी ने बिना कोई कारण बताये उसे वर्तमान प्रकटन विवरण

से हटा दिया है। यह अनुरोध किया जाता है कि एक अन्य प्रकटन विवरण जारी किया जाए जिसमें उस विश्लेषण को शामिल किया जाए। यह नोट करना संगत नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्णय में उसकी टिप्पणी की थी।

(ix) प्राधिकारी ने बहुत ध्यानपूर्वक विश्लेषण किया है और यह उजागर किया है कि सउदी अरब से आयातों की कीमतों का निर्धारण मलेशिया, यू.एस.ए., दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर से संबद्ध वस्तु की कीमतों के आधार पर किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से पाटित आयातों के बर्ताव के प्रति भेदभाव पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है, जब निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह पाया कि किसी अन्य देशों जो उसी उत्पाद का भारत में निर्यात कर रहे थे, पर पाटन रोधी उपाय लगाया गया था और सउदी अरब के निर्यातकों/उत्पादकों को उन पर उसी पाटनरोधी उपायों को लगाते हुए ऐसा करने की अनुमति दी गई थी यद्यपि उनके क्रियाकलाप तीन महीने की एक लघु अवधि में स्पष्ट रूप से घरेलू बाजार पर उनके आक्रामक रूप से कब्जा करने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति को दर्शाया।

(x) पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए संबद्ध देशों में उस देश को चुनने का कोई अधिदेश नहीं है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 19 में यह प्रावधान है कि शुल्क को बिना किसी भेदभाव पूर्ण आधार पर लगाया जायेगा।

(xi) जबकि यदि हमने निर्दिष्ट प्राधिकारी की प्रथा को ध्यान से देखा; अन्य देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी को कभी भी भारत में उस वस्तु को पाटित करने के लिए एक बहाने के रूप में नहीं माना गया है और उसकी प्रशंसा एवं उसे प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। पूर्व के अनेक जांचों जैसे यूरोपीय संघ और मैक्सिको से पी.वी.सी. संस्पेंशन, चीन जन. गण. से पेंटासिक्लीटोल पर अंतिम निर्णायक जांच और चीन जन. गण. तथा यू.ए.ई. से हेक्सामाइन पर पाटनरोधी जांच में संदर्भ के अनुसार प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के एक समूह से पाटित वस्तु से आयातों पर शुल्क की सिफारिश की थी जबकि संबद्ध वस्तुओं के एक अन्य समूह से पर्याप्त पाटित आयात हुए थे जिन पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा था।

(xii) यह अनुरोध किया जाता है कि इतिहास में कभी भी पहले पाटनरोधी शुल्क लगने वाले अन्य संबद्ध देशों से पाटित आयात हुआ है और उस पर क्षति के कारण के रूप में विचार किया गया था जबकि नए स्रोतों से कारणात्मक संबंध की जांच की गई थी।

(xiii) अनुबंध ॥ के पैरा (v) में अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति का संदर्भ दिया गया है। ऐसे अन्य कारकों का संदर्भ लेते समय नियमावली में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी पाटित आयातों के अलावा अन्य ज्ञात कारकों की भी जांच करेंगे जो उस समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं और इन अन्य कारकों द्वारा हुई क्षति का कारण पाटित आयात नहीं होना चाहिए। वे कारक जो इस मामले में संगत हैं उनमें अन्य बातों के साथ साथ पाटन कीमतों पर न बेची गई आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल है। इसके अलावा यह नियमावली कुछ कारकों की पहचान करता है जिन्हें संगत माना जा सकता है और उस समय वे मौजूद होंगे और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे होंगे। प्रकटन विवरण में अन्य स्रोतों से पाटित आयात को छोड़कर किसी अन्य आयात की पहचान किए बिना संभावित "अन्य कारक" का बार बार संदर्भ लिया गया है। इस कारण से याचिकाकर्ता प्रकटन विवरण को समझने के आधार पर ये अनुरोध कर रहे हैं कि कोई भी अन्य सूचीबद्ध ज्ञात कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है और अन्य देशों से आयात को छोड़कर, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कोई अन्य कारक को नहीं पाया है, जिसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है।

(xiv) नियम 16 और पैरा (v), अनुबंध ॥ पर भी विचार करना संगत है। नियम 16 के साथ पठित अनुबंध ॥ के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों के संदर्भ से यह स्पष्ट है कि अनुबंध ॥ में संदर्भित अन्य कारक तथ्यों की प्रकृति में हैं। चूंकि, ये तथ्यों की प्रकृति में हैं अतः प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस बात को प्रकट करें कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति ऐसे किसी अन्य कारक के कारण हुई है।

(xv) एक प्रश्न जो वर्तमान जांच में विचार किए जाने के लिए उठता है वह यह है कि क्या अन्य स्रोतों से पाटित आयात अन्य कारक हो सकते हैं, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच रही हो। इस संबंध में निम्नलिखित संगत है :

□ प्राधिकारी द्वारा मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यू.एस.ए. से आयातों के संबंध में जारी किए गए अंतिम जांच परिणाम में निकाला गया निष्कर्ष नीचे दिया गया है :

i. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और उसे मात्रा संबंधी मानदंडों जैसे उत्पादन, बिक्री, क्षमता का उपयोग और माल भंडार में गिरावट पर विचार किए बिना कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री को सिद्ध किया गया है।

ii. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण गिरावट आई है।

iii. पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध उन तथ्यों से सिद्ध किया जा सकता है कि आयात स्वतंत्र रूप में और सापेक्ष रूप में बहुत अधिक हैं।

iv. विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण कीमत पर दबाव पड़ रहा है और यह घरेलू उद्योग को कीमत में वृद्धि करने से रोक रहा है। इसके परिणामस्वरूप लाभ, नकद प्रभाव और निवेश पर आय में गिरावट आई है।

v. संबद्ध आयातों के फलस्वरूप बाजार में कम कीमत पर बिक्री हो रही है।

vi. घरेलू उद्योग का विकास अनेक कीमत और मात्रा संबंधी आर्थिक मानदंडों के मामले में ऋणात्मक हो गया। जबकि मात्रा संबंधी मानदंडों में ऋणात्मक विकास उत्पादन को रोकने के कारण हो सकता है, कीमत संबंधी मानदंडों में ऋणात्मक विकास मुख्य रूप से देश में इस उत्पाद के पाटन के कारण हुआ है।

(xvi) इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि अन्य देश से आयातों को पाटित आयात के रूप में माना गया था और यह माना गया था कि इस के कारण घरेलू उद्योग को उस सीमा तक क्षति हुई है जिस सीमा तक प्राधिकारी इन आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करने के लिए उपयुक्त माना। चूंकि, अन्य देशों से ये आयात पाटित आयात हैं, अतः यह माना जा सकता है कि घरेलू उद्योग को वर्तमान जांच की संगत अवधि के दौरान यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यू एस ए से पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही थी।

(xvii) अन्य कारकों के अंतर्गत अनुबंध ॥ के पैरा (v) में हालांकि अन्य स्रोतों से पाटित आयात शामिल नहीं होते हैं। आयातों की मात्रा और कीमतें जिन्हें पाटन कीमतों पर नहीं बेचा गया था, मांग में संकुचन अथवा उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात कार्य निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता जैसे कारकों का सूचीयन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि इन नियमों को एक कारक के रूप में और अन्य कारकों जैसे पाटन कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग के निर्यात कार्य निष्पादन और उत्पादकता को अन्य कारकों के रूप में पाटित आयात के बीच अंतर किया गया और अलग अलग रूप में देखा गया है। इस प्रकार से प्राधिकारी से यह अपेक्षित नहीं है कि वे अन्य पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को अलग अलग करें।

(xviii) निम्नलिखित डब्ल्यू टी ओ पैनल के रिपोर्ट में इस संबंध में यह संगत है।

i. **ब्राजील से मेलियेबल कास्ट आयरन – टयूब या पाइप फिटिंग के मामले में पैनल ने नीचे दिये गये अनुसार नोट किया :**

अपने निर्धारण में यूरोपीय समुदाय ने पाटित आयातों को छोड़कर कुछ अन्य कारकों की पहचान की जो संभावित रूप से तीसरे देशों से आयातों सहित घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे थे और न कि संबद्ध वस्तुओं की जांच; उपभोग में गिरावट और प्रतिस्थापन उसमें शामिल थी। इन कारकों में प्रत्येक कारक को अलग अलग किए जाने के संबंध में यूरोपीय समुदाय ने एक अलग जांच की और यह पाया कि या तो यह 'ऐसा नहीं है जिससे समुदाय उद्योग द्वारा हुई वास्तविक क्षति को बहुत अधिक मात्रा में अंशदान किया है' (उपभोग में गिरावट); 313 यह कि इसने 'कोई महत्वपूर्ण योगदान' किया है (निर्यात कार्य निष्पादन) अथवा यह कि 'कोई महत्वपूर्ण प्रभाव' हो सकता था (संबंधित उत्पाद का अपना आयात), 314 यह कि इसने क्षति में बहुत अधिक अंशदान नहीं कर सकता है (प्रतिस्थापन), **315 अथवा (उन देशों से आयातों के मामले में जो जांच के अधीन नहीं है) 'यदि अन्य तृतीय देशों से आयात का समुदाय उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति में अंशदान भी रहा होगा तब इसके माध्यम से इसकी पुष्टि की जाती है कि यह ऐसा नहीं है जिससे पाटन और पाई गई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध टूट गया हो'।** 316 यूरोपीय समुदाय ने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई अन्य कारक जिसका घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में अंशदान रहा होगा 'ऐसा नहीं था जिससे पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध टूट गया हो'।³

7.368 यूरोपीय समुदाय के निर्धारण के ये पहलू हमें यह दर्शाते हैं कि यूरोपीय समुदायों संबंधित कारणात्मक कारकों का अलग अलग रूप में विश्लेषण किया और इन कारणात्मक कारकों में से प्रत्येक के अलग अलग प्रभावों की जांच की है। इन कारकों में से प्रत्येक कारक के संबंध में यूरोपीय समुदायों ने यह निष्कर्ष निकाला कि क्षति के अंशदान की सीमा बहुत अधिक नहीं थी और एक मामले में इसने यह उल्लेख किया कि यदि प्रभाव अधिक भी था तब यह इतना नहीं था कि 'पाटित आयातों और वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को तोड़ सके'। यूरोपीय समुदाय का समग्र निष्कर्ष यह था कि इनमें से किसी भी कारक का प्रभाव ऐसा नहीं था जिससे पाटित आयातों और वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध टूट गया हो।

(xix) उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि किसी भी मामले में अन्य स्रोतों से पाटित आयात कारणात्मक सम्पर्क के विश्लेषण के लिए क्षति का 'अन्य कारक' नहीं हो सकता है। याचिकाकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में सी डी आर, डी वी डी आर और पी वी सी सस्पेंशन मामले में विगत किए गए निर्धारण की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है।

(xx) प्राधिकारी ने खतरे के विश्लेषण के उद्देश्य से सितंबर, 2018 तक की अवधि तक किए गए आयात पर विचार किया है जो जांच की अवधि के बाद 30 महीने के आंकड़ों को दर्शाता है। याचिकाकर्ता का यह अनुरोध है कि सबसे पहले क्षति के खतरे के विश्लेषण के उद्देश्य से जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार करने के लिए नियमावली के अंतर्गत कोई अधिदेश नहीं है। हालांकि, प्रथा के अनुसार प्राधिकारी ने कभी भी जांच की अवधि के बाद के विश्लेषण के उद्देश्य से 6 महीने

से अधिक के आंकड़ों पर विचार नहीं किया है। निर्णायक समीक्षा जांचों के संदर्भ में और जहां भी प्राधिकारी ने जांच की अवधि में सतत् पाटन और क्षति नहीं पाई है, प्राधिकारी ने जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर विचार किया है। हालांकि, प्राधिकारी ने जांच की अवधि के बाद के विश्लेषण के लिए केवल 6 महीने के आंकड़ों पर ही विचार किया है। वास्तव में फिनोल और एसिटोन के संबंध में मध्य अवधि समीक्षा के मामले में घरेलू उद्योग ने ठोस तर्क दिया है कि बाजार की स्थिति बहुत अधिक अस्थायी थी और प्राधिकारी को जांच की अवधि के बाद के पिछले एक वर्ष के आंकड़ों पर विचार करना चाहिए। हालांकि, प्राधिकारी ने यह उल्लेख करते हुए 6 महीने के बाद की जांच की अवधि के बाद की अवधि पर विचार करने से इन्कार किया है कि जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों पर 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामले होने पर, सितंबर 2018 तक की अवधि के लिए आयात के आंकड़ों पर विचार करना उचित नहीं है और न ही इसका कोई औचित्य है। याचिकाकर्ता प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे वर्तमान उद्देश्य से जांच की अवधि के बाद के रूप में सितंबर, 2016 तक के ही आयात पर विचार करें। अक्टूबर 2016 के बाद की अवधि के लिए आयात संबंधी आंकड़ों को खतरे के विश्लेषण के उद्देश्य से नहीं लिया जा सकता है।

(xxi) जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों के विश्लेषण को खुला रखने से विश्लेषण किए जाने के लिए आंकड़ों में अनुमान और अनिश्चतता उत्पन्न होती है। निर्दिष्ट प्राधिकारी की एक सतत् प्रथा रही है कि इसने जांच की अवधि के बाद के विश्लेषण के उद्देश्य से 6 महीने की अवधि पर विचार किया है। उसे नीचे दिए गए मामलों की सूची से निष्कर्ष निकाल जा सकता है :

- क. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए 'फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयरिंग नकल्स जिसका निर्माण भारी और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए किया जाता है', के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।
- ख. चीन जन. गण. और इण्डोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए 'बंबू फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।
- ग. सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए 'पोली प्रोपिलीन' के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने की निर्णायक समीक्षा (एस एस आर) जांच।
- घ. यूरोपीय संघ, ईरान, इण्डोनेशिया और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए 'मेला माइन' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच (निर्णायक समीक्षा)।
- ङ. चीन जन. गण. और स्वीजरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए 'विटामिन – ए पालमिटेट' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा।
- च. वियतनाम और थाईलैण्ड के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए 'सभी प्रकार के डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क – रिकार्डबल (डी वी डी – आर)' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा (एस एस आर)।
- छ. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए 'भारी और मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए बनाये गये 'फ्रंट एक्सल बीम' और 'स्टीयरिंग नकल्स' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा (एस एस आर)।

(xxii) उपर्युक्त मामले स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि क्या यह मूल जांच है या निर्णायक समीक्षा जांच है, प्राधिकारी ने सतत् रूप 6 महीने की अवधि को ही जांच की अवधि के बाद की अवधि के रूप में संदर्भित किया है। हालांकि, जारी किए गए वर्तमान प्रकटन में जांच की अवधि के बाद की अवधि को खुला रखा है।

(xxiii) यदि अन्य प्रकार से क्षति के खतरे के संबंध में याचिकाकर्ता यह अनुरोध करता है कि प्रकटन विवरण में, प्राधिकारी ने केवल उन मानदंडों का संदर्भ लिया लेकिन सभी अनिवार्य मानदंडों की जांच नहीं की तब याचिकाकर्ता यह अनुरोध करता है कि अनुबंध II पैरा (vii) में उल्लिखित मानदंड अनिवार्य प्रकृति के हैं। हम प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे वास्तविक क्षति के खतरे के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए उसकी जांच करें।

(xxiv) प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में विभिन्न अनुच्छेदों संख्या 56.46 के अंतर्गत यह उल्लेख किया है कि सउदी अरब से आयातों की कीमतें मलेशिया, यू एस ए, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर द्वारा पेशकश की गई कीमतों से निर्देशित हुई थी क्योंकि वे कीमतों को तय करने में बाजार में दमदार भागीदार थे। याचिकाकर्ता इस संबंध में नीचे दिये गये अनुसार अनुरोध करता है :

- क. पूर्व में कभी भी प्राधिकारी ने इस पर विचार नहीं किया है कि क्या एक पाटित स्रोत से आयात कीमत अन्य स्रोत से पाटित आयातों से प्रभावित होता था।
- ख. कानून के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें प्राधिकारी द्वारा इस विश्लेषण पर विचार किया जाए।

- ग. कानून के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें यह उल्लेख हो कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उन पाटित स्रोतों को पाटनरोधी शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करे जहां पाटन अन्य देशों से पाटित आयातों के कारण हुआ था।
- घ. यह पूर्ण रूप से गलत है कि क्या सउदी उत्पादक ने अन्य पाटित स्रोतों की कीमतों का पालन किया।
- ङ. यह मानते हुए कि सउदी उत्पादक ने अन्य पाटित स्रोतों की कीमतों का पालन किया, वह अपने आप में यह सिद्ध करता है कि सउदी उत्पादक ने पाटन का सहारा लेकर एन बी ए – 1 देशों द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंचाई गई क्षति में योगदान दिया है।
- च. यह तथ्य अपने आप में पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने के लिए सउदी में निर्यातकों के लिए औचित्य नहीं हो सकता है। किसी बाजार में उत्पाद के पाटन की निंदा की जानी चाहिए। यदि यह घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाता हो।
- छ. एन बी ए – 1 मामले में यूरोपीय संघ से आयात (और अन्य देशों से भी) उच्चतर कीमतों पर हुआ था। परंतु निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वैसा ही निष्कर्ष नहीं निकला जैसा कि वर्तमान मामले में प्रस्ताव किया गया।
- ज. एन बी ए – 1 मामले में भी ऐसा नहीं है कि चार देश एक ही समय में तय कर रहे थे। यह स्पष्ट है कि कुछ देश कीमत तय कर रहे थे और अन्य उसका पालन कर रहे थे। किसी भी मामले के लिए यह सही है जहां एक से अधिक स्रोत शामिल हो। याचिकाकर्ता यह समझ पाने और यह जानने में असफल है कि वर्तमान मामले में विशिष्ट बात क्या है।

(xxv) प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के पैरा 66(क) में एक नया तथ्य लाये हैं जिस पर प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम पर पहुंचते समय विचार नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता का यह अनुरोध है कि इस पर अब विचार नहीं किया जा सकता है। सउदी उत्पादक और सरकार एक लिखित वचन दे सकती है कि सउदी में उत्पादक भारत में इस उत्पाद का निर्यात नहीं करेंगे क्योंकि इसका उत्पादन कैपिटव खपत के लिए किया गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी उस स्थिति में जांच को स्थगित करने पर विचार कर सकते हैं। याचिकाकर्ता को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी।

(ख) निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों / अन्य पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

65. मैसर्स एल के एस जो साबुको, सादरा, एस ए ए सी, पैट्रोकेम, तासनी मार्केटिंग एवं टोयोटा का प्रतिनिधित्व करता है, ने निम्नलिखित अनुरोध किया है :

(i) पाटनरोधी प्रथाओं पर डब्ल्यू टी ओ समिति में यह प्रावधान है कि पाटनरोधी जांच में आंकड़ों के संकलन की अवधि कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। वर्तमान मामले में, जांच की अवधि प्रभावी रूप से केवल तीन महीने की थी क्योंकि सउदी अरब से जांच की अवधि के पिछले तीन महीने अर्थात् जनवरी 2016 से मार्च 2016 के दौरान ही आयात हुआ। इस आधार पर ही जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(ii) प्राधिकारी ने क्षति संबंधी मानदंडों की जांच करते समय घरेलू उद्योग की जांच की अवधि के दौरान मात्रा संबंधी लगभग सभी मानदंडों जैसे उत्पादन, बिक्री की मात्रा, क्षमता का उपयोग, बाजार हिस्सा और माल भंडार में धनात्मक सुधार देखा है। मात्रा के मानदंडों पर, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान किसी क्षति का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हम प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे अंतिम जांच परिणाम में इस तथ्य की पुष्टि करें।

(iii) प्राधिकारी ने कीमत न्यूनीकरण/ उस पर दबाव का विश्लेषण करते समय यह नोट किया है कि सउदी अरब से आयात जांच की अवधि के पिछले तीन महीने अर्थात् जनवरी 2016 से मार्च 2016 के दौरान हुआ। घरेलू उद्योग की बिक्री की लागतों में 2014-15 में 113 सूचकांक से जांच की अवधि के दौरान 79 सूचकांक तक कटौती हुई (34 सूचकांक की गिरावट) जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत 2014-15 में 92 सूचकांक से गिरकर जांच की अवधि में 73 सूचकांक तक पहुंच गई (19 सूचकांक की गिरावट) यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमत पर कोई दबाव नहीं पड़ा था इस कारण से सउदी अरब से आयातों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि कीमत पर कोई दबाव हो रहा है क्योंकि सउदी अरब से आयात जांच की अवधि के पिछले तीन महीनों में ही हुआ। हम प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि अंतिम जांच परिणाम में इस तथ्य की पुष्टि करें।

(iv) प्रकटन विवरण के पैरा 34 और 35 विश्लेषण किए गए कीमत मानदंडों के संबंध में, प्राधिकारी ने यह नोट किया है सउदी अरब से भारत में आयात जांच की अवधि के पिछले तीन महीनों के दौरान ही हुई। हालांकि, घरेलू उद्योग को क्षति की जांच की अवधि सहित जांच की समग्र अवधि के लिए हानि हो रही थी। प्राधिकारी ने यह टिप्पणी की है कि घाटे और नकद घाटे 2014-15 में सबसे अधिक हुए थे और जांच की अवधि में इसमें कमी आई। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सउदी अरब के आयात क्षति के जांच की समग्र अवधि और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हुई हानि के लिए जिम्मेदार नहीं थी

और सउदी अरब से संबद्ध वस्तुओं के आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुए घाटे के बीच किसी कारणात्मक संबंध का पूर्ण अभाव है। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि कृपया अंतिम जांच परिणाम में इस तथ्य की पुष्टि करें।

(v) प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के 53 – 55 में यह नोट किया है कि सउदी अरब से भारत में आयात जांच की अवधि के पिछले तीन महीने के दौरान हुआ। हालांकि, घरेलू उद्योग को जांच की अवधि सहित क्षति की जांच की समग्र अवधि के दौरान सउदी अरब को छोड़कर अन्य देशों से हुए आयातों के कारण घाटा हो रहा था। यह अनुरोध किया जाता है कि जांच की अवधि के पिछले तीन महीने के दौरान सउदी अरब से आयात भारत में उस समय प्रचलित कीमतों और अन्य देशों द्वारा निर्धारित कीमतों पर भारतीय बाजार में हुए जो भारतीय बाजार में प्रभावी भागीदार थे। यह भी अनुरोध किया जाता है कि कुछ अन्य देशों से आयात जांच की अवधि के पिछले तीन महीनों के दौरान सउदी अरब की कीमतों की तुलना में कम कीमत पर हुए। इस कारण से सउदी अरब से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का कोई खतरा नहीं है और न ही कोई कारणात्मक संबंध है। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे अंतिम जांच परिणाम में इसकी पुष्टि करें।

(vi) प्रकटन विवरण के पैरा 66 में प्राधिकारी की टिप्पणियां स्पष्ट रूप से यह दर्शाती हैं कि सउदी अरब से संबद्ध वस्तुओं के आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का कोई खतरा नहीं है क्योंकि सउदी अरब से आयात में 2017-18 में बहुत अधिक गिरावट हुई है और यह 2018-19 के दौरान पूर्ण रूप से बंद हो गया है। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे अंतिम जांच परिणाम में इसकी पुष्टि करें।

(vii) सामान्य बुटालोन का कोई निर्यात एस ए ए सी और सादरा द्वारा न तो भारत में और न ही किसी अन्य देश में 2018-19 में किया गया है। एस ए ए सी और सादरा के लिए संयुक्त उद्यम करार करने का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य बुटालोन प्राप्त करना था जिसका उपयोग बुटील एकीलेट और बुटील ग्लाइकोइथर (बी जी ई) जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्माण करने के लिए या तो उनके द्वारा अथवा उनकी संबंधित कंपनियों द्वारा कैप्टिव उपभोग के लिए किया जाएगा।

(viii) संबद्ध देश में अतिरिक्त क्षमता का सृजन करना मात्र यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि इन वस्तुओं को भारतीय बाजार में विपथित किया जा सकता है और इससे भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन होगा। इस संबंध में प्रतिवादी भारतीय स्पिनर एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी पर भी भरोसा करते हैं जिसमें माननीय सेस्टेट ने यह पाया कि केवल अतिरिक्त क्षमताओं का मौजूद होना क्षति के किसी आसन्न खतरे का संकेत नहीं देगा।

(ix) प्रतिवादी यह अनुरोध करते हैं कि घरेलू उद्योग सउदी अरब से आयातों के तीन महीने की छोटी अवधि का अनुचित लाभ लेने की कोशिश कर रहा है और साथ ही सउदी अरब से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगवाने की कोशिश कर रहा है। प्रतिवादी ऐसा बयान दे रहे हैं क्योंकि मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि सउदी अरब से आयात जांच की अवधि के पिछले तीन महीने अर्थात् जनवरी 2016 से मार्च 2016 के दौरान हुआ और इसमें 2017-18 में बहुत अधिक गिरावट आई है और यह 2018-19 में शून्य हो गया। घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में धीरे धीरे 2015-16 से सुधार हुआ है जिसका संक्षिप्त विवरण संबंधित वर्षों की इसकी वार्षिक रिपोर्टों में नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :

विवरण	16-2015 (लाख में .रु)	17-2016 (लाख में .रु)	18-2017 (लाख में .रु)
प्रचालन से राजस्व	3758.83	37043.04	53275.25
कर पूर्व लाभ (हानि) /	(2630.43)	(1090.47)	4725.98

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में जांच की अवधि के अंत से बहुत अधिक सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग को 2015-16 में 2630.43 लाख रुपए का घाटा हुआ था जो घटकर 2016-17 में 1090.47 लाख रु. हो गया और यह 2017-18 के दौरान 4725.98 लाख रु. के अच्छे लाभ में परिणत हो गया। अतः हम प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे वर्तमान जांच को समाप्त कर दें और घरेलू उद्योग के जाल में न फंसे, जिसके द्वारा वे सउदी अरब से तीन महीनों की छोटी अवधि के दौरान जिसमें उन्हें अन्य देशों से आयातों के कारण न कि सउदी अरब से आयातों के कारण हानि हो रही थी, आयातों के आधार पर 5 वर्षों के लिए पाटनरोधी शुल्क लगवाना चाहते हैं।

त. प्राधिकारी द्वारा जांच

66. प्राधिकारी विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं जिनमें से कुछ को बार-बार दोहराया गया है और उनका समाधान प्रकटन विवरण में उस सीमा तक कर दिया गया था जिस सीमा तक नए तर्क किए गए थे और उन्हें संगत माना गया था, विशिष्ट मुद्दों का उपर्युक्त जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर निराकरण किया गया है। प्राधिकारी ने यहां

नीचे दिए गए हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच उस सीमा तक की है जिस सीमा तक उन्हें संगत माना गया है और उनका समाधान अन्य स्थान पर नहीं किया गया था । .

- (i) प्राधिकारी हितवद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों को नोट करते हैं और यह मानते हैं कि विचाराधीन सभी संगत आवश्यक तथ्यों को प्रकट किया गया है ।
- (ii) घरेलू उद्योग का यह दावा है कि प्राधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की उपेक्षा की है क्योंकि इस जांच में प्राधिकारी के समक्ष एकमात्र मुद्दा सऊदी अरब से 3 महीने की लघु अवधि के दौरान आयातों के कारण कारणात्मक संबंध का अभाव है । घरेलू उद्योग का यह भी दावा है कि वर्तमान प्रकटन विवरण में अतिरिक्त तथ्य और विश्लेषण नहीं होने चाहिए जो पूर्व के अंतिम जांच परिणामों में मौजूद नहीं थी । प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने प्राधिकारी को यह निदेश दिया है कि वे इस योजना के आधार पर तथा पाटनरोधी नियमावली की संरचना के आधार पर नए सिरे से निर्धारण जारी करें और साथ ही वास्तविक क्षति के खतरे जिसकी जांच पूर्व के जांच परिणामों में नहीं की गई थी का विश्लेषण करने का भी निदेश दिया गया था । माननीय उच्च न्यायालय ने प्राधिकारी को यह निदेश नहीं दिया है कि वे इस योजना के अंतर्गत और पाटनरोधी नियमावली की संरचना के अंतर्गत संगत तथ्यों पर विचार किए बिना पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करें । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के 9 महीने और अगले तीन महीने के क्षति संबंधी अलग-अलग किए गए क्षति संबंधी विश्लेषण को प्राधिकारी द्वारा वर्तमान जांच में हटा दिया गया है । इस संबंध में प्राधिकारी यह स्मरण करते हैं कि मूल जांच परिणाम में अलग-अलग किए गए विश्लेषण में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को कीमत न्यूनीकरण के कारण सतत क्षति के बारे में पुष्टि की थी । हालांकि प्राधिकारी ने सऊदी अरब से आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को निर्णायक रूप से सिद्ध करने का प्रयास किया था जिसे अलग-अलग किए गए विश्लेषण के आधार पर भी स्थापित नहीं किया जा सकता था । प्राधिकारी इस संबंध में दिनांक 28 नवंबर, 2017 के मूल अंतिम जांच परिणाम के पैरा 93 (ii) का स्मरण करते हैं । इस कारण से वर्तमान रिमांड जांच में, जब जांच की अवधि की बाद के आंकड़े उपलब्ध हैं, प्राधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार 2016-17, 2017-18, 2018-19 (अगस्त 2018 तक) की अवधि के लिए उसका विश्लेषण किया है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्रकटन विवरण में वे सभी आवश्यक तथ्य शामिल हैं जो इस योजना और पाटनरोधी नियमावली की संरचना के अनुसार और माननीय उच्च न्यायालय के विशिष्ट निदेशों का कठोरता से पालन करने के बाद है । इसके लिए विगत जांच की अवधि जिसे जांच की अवधि के बाद के रूप में कहा जाता है, सऊदी अरब से आयातों की प्रवृत्ति की जांच अपेक्षित है जिसका निराकरण नीचे दिए गए पैरा में किया गया है ।
- (iii) जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों के संबंध में, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों को जांच की अवधि की बाद के विश्लेषण के उद्देश्य से निर्दिष्ट प्राधिकारी की सतत प्रथा पर विचार करते हुए वास्तविक क्षति के खतरे का विश्लेषण करते समय 6 महीने तक सीमित किया जाना चाहिए । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के अनुरोधों को निम्नलिखित कारणों से नहीं माना जा सकता है। सर्वप्रथम वास्तविक क्षति के खतरे की जांच के उद्देश्यों से इस अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली में कोई विशिष्ट अवधि नहीं दी गई है । पाटनरोधी जांच की सामान्य प्रक्रिया में, प्राधिकारी सामान्य रूप से जांच की अवधि के हाल बाद के आंकड़े आम तौर पर लेते हैं जो 6 से 9 महीने से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं है । हालांकि इस वाद के वर्तमान तथ्यों में प्राधिकारी के समक्ष डी जी सी आई एंड एस के अगस्त, 2018 के नवीनतम आयात संबंधी आंकड़े हैं जो अन्य पाटनरोधी जांचों में स्थिति नहीं है । प्राधिकारी के पास उपलब्ध आंकड़ों की सुविधा और उपलब्धता के मामले के लिए, प्राधिकारी सामान्य तौर पर सबसे हाल की अवधि को लेते हैं जो सामान्यतया जांच की अवधि के बाद 6 महीने की अवधि होती है । हालांकि वर्तमान जांच में, प्राधिकारी के पास उपलब्ध 6 महीने से अधिक के आंकड़ों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है जो प्राधिकारी को एक निष्पक्ष निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति देता है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के निदेश से प्राधिकारी जांच की अवधि के बाद के 6 महीनों की अवधि अर्थात् 30 सितंबर, 2016 तक की अवधि के दौरान क्षति के खतरे की जांच करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं । हाल में उपलब्ध आंकड़ों की उपेक्षा करते हुए क्षति के खतरे की जांच के लिए इस चरण में पुराने आंकड़ों की जांच करना अनुचित होगा और निष्पक्ष नहीं होगा क्योंकि केवल हाल के आंकड़े सही वास्तविकता को दर्शाते हैं जिस पर कोई भी हितवद्ध पक्ष इस मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आपत्ति नहीं करेगा और इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के 1995 की नियमावली के योजना और संरचना के अनुसार इस मामले की कठोरता से जांच करने के लिए है । प्राधिकारी पुनः उल्लेख करते हैं कि इन पर जिम्मेदारी अभी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वस्तुपरक आकलन करना है ।
- (iv) अन्य स्रोतों से पाटित आयातों का विश्लेषण करने के संबंध में किए गए अनुरोधों के संबंध में कारणात्मक क्षति के विश्लेषण के लिए क्षति का एक अन्यकारक नहीं हो सकता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में यह तथ्य विशिष्ट प्रकृति के हैं क्योंकि संबद्ध देशों से आयात क्षति की जांच की अवधि के दौरान शून्य है और सऊदी अरब से आयात जांच की अवधि के पिछले तीन महीनों में ही हुआ है । प्राधिकारी पर इस तथ्य की जांच करने का दायित्व है कि क्या संबद्ध देश से

आयात इस कठिन स्थिति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हो सकता है अथवा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए अन्य कारक जिम्मेदार हैं। यदि अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं तब सउदी अरब से आयातों को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। जांच की अवधि के दौरान प्राधिकारी ने मात्रा संबंधी प्रायः सभी मानदंडों जैसे घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री की मात्रा, क्षमता का उपयोग, बाजार हिस्सा और माल भंडार में सकारात्मक सुधार देखा है। कीमत संबंधी मानदंड क्षति की जांच की अवधि और जांच की अवधि ऋणात्मक थी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कुछ मात्रा और कीमत संबंधी मापदंडों में सुधार पिछले वर्ष/पिछले 2 वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में हुई। हालांकि, चूंकि सउदी अरब से आयात जांच की अवधि की पूर्व वर्षों के दौरान नहीं हुई और कुछ मानदंडों के प्रदर्शन में जांच की अवधि में सुधार देखा गया। अतः जांच की अवधि में सउदी अरब से आयातों और घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन के बीच संबंधी स्थापित करने के लिए अन्य देशों की आयात कीमतों की भी निकटता से जांच की जानी अपेक्षित थी। अतः प्राधिकारी ने अन्य कारकों की जांच की है जिससे कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। इसके अलावा प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को यूरोपीय यूनियन, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए से पाटित आयातों के कारण क्षति की जांच की अवधि के दौरान क्षति हो रही थी और जांच की अवधि के दौरान सउदी अरब से जांच की अवधि के पिछले तीन महीनों में आयात कीमत मलेशिया, सिंगापुर और यूएसए की तुलना में अधिक थी। इन सभी कारकों के कारण प्राधिकारी यह दोहराते हैं कि सउदी अरब से आयात घरेलू उद्योग को हुई कीमत संबंधी मानदंडों पर क्षति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

- (v) अन्य देशों से पाटित आयातों (जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है) का वर्तमान तथा पाटनरोधी शुल्क लगाए बिना निर्यात करने के लिए सउदी अरब से निर्यातकों/उत्पादकों को अनुमति देने के बीच भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण के संबंध में, प्राधिकारी यह मानते हैं कि ऐसा कोई भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण वर्तमान जांच में नहीं अपनाया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का तर्क सही नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग नियम 19 पर भरोसा कर रहा है जिसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि शुल्क लगाने के समय किसी देश में विभिन्न उत्पादकों/निर्यातकों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वास्तव में घरेलू उद्योग के दावे के विरुद्ध, प्राधिकारी यूरोपीय समुदाय - चीन से कुछ लौह अथवा इस्पात फास्टर पर निश्चयात्मक पाटनरोधी उपाय में अपील की रिपोर्ट को नोट करते हैं जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 9.2 में नीचे दिए गए अनुसार की गई है:

“338. हम नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.2 में यह अपेक्षित है कि पाटनरोधी शुल्कों का संग्रहण ‘उन स्रोतों’ जिनसे कीमत संबंधी लिखित वचन स्वीकार्य किए गए हैं, को छोड़कर पाटित किए जाने के लिए और क्षति पहुंचाने के लिए पाए गए ‘सभी स्रोतों’ से बिना किसी भेदभावपूर्ण आधार पर किया जाना चाहिए। हम पैनल से सहमत हैं कि ‘स्रोत’ शब्दावली जो अनुच्छेद 9.2 के प्रथम वाक्य में दो बार आया है, का वही आशय है और इसका संदर्भ अलग-अलग निर्यातक अथवा उत्पादक और न कि संपूर्ण देश से है। यह इस तथ्य द्वारा दर्शाया गया है कि अनुच्छेद 9.2 के प्रथम वाक्य में उल्लिखित कीमत संबंधी लिखित वचनों को अलग-अलग निर्यातकों और न कि देशों से पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 8 के अनुसार स्वीकार किया गया है। इस कारण से, अनुच्छेद 9.2 के अंतर्गत यह अपेक्षा कि पाटनरोधी शुल्कों का संग्रहण प्रत्येक मामले में उपयुक्त राशियों में की जाए और सभी स्रोतों से इसका संग्रहण किया जाए। जांच के अध्यक्षीन अलग-अलग निर्यातकों अथवा उत्पादों से संबंधित है।”

अपीलीय निकाय ने यह व्याख्या की कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 9.2 के अंतर्गत सभी स्रोतों से बिना भेदभावपूर्ण आधार का संदर्भ अलग-अलग निर्यातकों अथवा उत्पादों से है और न कि संपूर्ण देश से। अतः, घरेलू उद्योग का तर्क सही नहीं है कि प्राधिकारी ने अन्य देशों से पाटित आयातों की विवेचना और सउदी अरब से निर्यातकों/उत्पादकों को पाटनरोधी शुल्क लगाए बिना निर्यात करने के लिए अनुमति देने के प्रति कोई भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है।

- (vi) घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि अनुबंध-2 के पैरा (v) का संदर्भ अन्य कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति से है और प्राधिकारी पैरा (v) में विशिष्ट रूप से नहीं सूचीबद्ध किसी अन्य ज्ञात कारकों की जांच नहीं करेंगे। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अनुबंध-2 के पैरा (v) में उल्लिखित कारक सांकेतिक हैं। अन्य कारकों का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने संबद्ध देश को छोड़कर अन्य देशों से आयातों की जांच की है जिससे ऊपर में उल्लिखित अनुसार, घरेलू उद्योग को क्षति हुई। इन तीन महीने की अवधि जब संबद्ध देश से भारत में आयात हुए, के दौरान वे केवल उस समय प्रचलित कीमतों पर हुए थे जिसे अन्य देशों जो भारतीय बाजार में प्रमुख भागीदार थे, द्वारा निर्धारित किया गया था। मूल अंतिम जांच परिणाम के पैरा 93 (ii) में दिए गए प्राधिकारी के दृष्टिकोण का स्मरण किया जाता है।
- (vii) घरेलू उद्योग ने पिछले जांचों का उदाहरण दिया है जिसमें संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी जांच की सिफारिश प्राधिकारी द्वारा देशों के एक समूह के लिए और बाद में देशों के अन्य समूह के लिए किया गया है। प्राधिकारी पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करते हुए और पाटन, क्षति का विश्लेषण करने के बाद गुण-दोष के आधार पर शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं। वर्तमान जांच के तथ्य और परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं और घरेलू उद्योग द्वारा उद्धृत पूर्व की जांचों पर कानून की एक स्थापित मान्यता के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है विशेषकर जब

किसी जांच में तथ्य और परिस्थितियां कीमत व्यवहार के अलग-अलग रूप में हो। प्राधिकारी द्वारा किया गया विश्लेषण उस विशेष जांच में तथ्यों और मौजूद परिस्थितियों के आधार पर है। इस कारण से उन जांचों का परिणाम और जांच परिणाम अधिक से अधिक समान स्थितियों के लिए सांकेतिक हो सकते हैं। अतः प्राधिकारी दोहराते हैं कि किसी विशेष जांच का विश्लेषण विगत में की गई अन्य जांचों से पूर्ण रूप से अलग है और यह किसी विशेष जांच की तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मामला दर मामला आधार पर किया जाता है क्योंकि प्रत्येक मामले में इसके अपने विशिष्ट तथ्य होते हैं।

- (viii) घरेलू उद्योग का आबद्ध उत्पादन के लिए और न कि भारत में निर्यात करने के लिए संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु सउदी अरब की सरकार से और सउदी अरब के उत्पादकों/निर्यातकों से लिखित आश्वासन लेने के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच में इसे पाटन, क्षति की जांच करना और क्षति एवं पाटन के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करना होता है। हालांकि कानून के अंतर्गत सउदी अरब की सरकार और सउदी अरब के उत्पादकों/निर्यातकों से आबद्ध खपत के लिए और न कि भारत में निर्यात करने के लिए संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु लिखित आश्वासन लेने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस अधिनियम और नियमावली के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो प्राधिकारी को संबद्ध देश की सरकार से इस प्रकार के लिखित आश्वासन की मांग करने की शक्ति प्रदान करता हो। प्रकटन के उत्तर में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि सउदी अरब के उत्पादक/निर्यातक अथवा सउदी सरकार भारत में निर्यात नहीं करने के लिए एक लिखित आश्वासन दे सकती है लेकिन उन्होंने प्राधिकारी द्वारा सिफारिश के पश्चात उनके आर्थिक कार्य निष्पादन के संबंध में सउदी अरब से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाने के किसी प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी घरेलू उद्योग की इसकी वैबसाइट पर उपलब्ध लेखा परीक्षित वित्तीय रिपोर्ट तथा निर्यातक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की समग्र लाभप्रदता में सउदी अरब से आयातों पर पाटनरोधी उपाय के उपलब्ध नहीं होने के बावजूद सुधार हुआ है। इसके अलावा प्राधिकारी नोट करते हैं कि 5 अन्य देशों अर्थात् यूरोपीय यूनियन, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यू.एस.ए. पर पाटनरोधी उपाय अप्रैल, 2016 में लागू हुआ और इस कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि इन देशों से अनुचित आयातों को रोकने के कारण लाभप्रदता में सुधार हुआ है और इस पर प्राधिकारी द्वारा दिनांक 28 नवंबर, 2017 के मूल जांच परिणाम के पैरा 93 (ii) में मान लिया गया था जो अब सही माना गया है।
- (ix) प्राधिकारी यह मानते हैं कि जांच की अवधि के तीन महीने में सउदी अरब से आयात यद्यपि बहुत अधिक था फिर भी प्राधिकारी सभी आवश्यक मानदंडों अर्थात् पाटन की सीमा, क्षति की सीमा और उससे भी महत्वपूर्ण पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन करने के लिए तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 के अंतर्गत पाटित (अनुचित) आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करने पर विचार करने के लिए 1995 के पाटनरोधी नियमावली की योजना और संरचना के अनुसार बाध्य थे। सउदी अरब द्वारा आक्रामक रूप से कब्जा किए जाने के बावजूद, कारणात्मक संबंध की गैर निर्णायक स्थापना ने प्राधिकारी को किसी उपाय की सिफारिश करने से रोक दिया क्योंकि कारणात्मक संबंध आवश्यक रूप से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करने के लिए एक मूलभूत शर्त है। प्राधिकारी की यह मान्यता है कि पाटनरोधी नियमावली को अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने हेतु अधिदेश तथा योजना के अनुसार लागू किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि इस नियमावली के अंतर्गत दिए गए अधिदेश के अनुसार, किसी आवश्यक शर्त को पूरा नहीं किए जाने की स्थिति में, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने हेतु पाटनरोधी उपाय की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अधिदेश की सीमाओं से बाहर नहीं जा सकते हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुसार कोई पाटनरोधी उपाय उसी सीमा तक लागू किया जाता है जिस सीमा तक क्षति अथवा पाटन उसमें से जो भी कम हो, हुआ हो ताकि क्षतिग्रस्त घरेलू निर्माता के अलावा, प्रयोक्ता घरेलू उद्योग की भी चिंताओं को दूर किया जा सके। हालांकि आयातों की अधिक मात्रा जैसी स्थिति में जहां पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सभी शर्तों को पूरा नहीं किया गया हो, क्षतिग्रस्त घरेलू निर्माता किसी अन्य उपयुक्त व्यापार निदानात्मक उपायों के अंतर्गत समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
- (x) प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश जिसमें क्षति के विश्लेषण की भी जांच करने का निदेश दिया गया है जिस पर प्राधिकारी ने पूर्व में विचार नहीं किया था, का अनुपालन सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है क्योंकि घरेलू उद्योग ने सउदी अरब से आयातों के कारण वास्तविक क्षति के खतरे का तर्क देते हुए यह आवेदन दायर नहीं किया था।
- (xi) प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 14 के अंतर्गत जांच समाप्त करने का सहारा नहीं ले सकते थे। प्राधिकारी ने विस्तृत जांच करने के बाद पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 के अंतर्गत अंतिम जांच परिणाम जारी किया जिसमें नियम 17 (iii) के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण और गैर समझौता योग्य मानदंड इस रूप में है कि “पाटित आयातों और क्षति के बीच जहां भी लागू हो, एक

कारणात्मक संबंध है”। अतः इस शर्त को पूरा नहीं कर पाने के कारण पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सकारात्मक सिफारिश करने में परिणत हो सकता था। ऐसी परिस्थितियों में, सिफारिश उस जांच को समाप्त करने के लिए थी जिसकी प्राधिकारी ने नियम 14(ख) के अंतर्गत सिफारिश की जो इस प्रकार से है “किसी जांच की प्रक्रिया में यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि पाटन का कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है अथवा तहां भी लागू हो जांच को जारी रखने के लिए कोई औचित्य नहीं है।” नियम 14 (ख) के अंतर्गत उल्लिखित लागू क्षति को पाटन के साथ एक कारणात्मक संबंध के होने से अलग करते हुए नहीं पढ़ा जा सकता है जो नियम 17 के अंतर्गत पाटनरोधी उपाय की सिफारिश करने का एक अभिन्न हिस्सा है। इस दृष्टिकोण के साथ प्राधिकारी ने नियम 14(ख) के अंतर्गत जांच को समाप्त कर दिया। यह नोट करते हुए कि नियम 14(ख) के अंतर्गत इस निष्कर्ष से प्राधिकारी के निर्धारण के संगत प्रावधान में संदिग्धता उत्पन्न होती है, प्राधिकारी एतद्वारा इसकी पुष्टि करते हैं कि जांच को समाप्त करना पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(ख) के साथ पठित नियम 17 के अंतर्गत किया गया है।

- (xii) प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के तीन महीने के दौरान सउदी अरब से आयात 8791 मी.ट. (वार्षिक रूप से लगभग 35,000 मी.ट.) थी। सउदी अरब से आयातों की जांच की अवधि के बाद की अवधि के बाद की प्रवृत्ति को 2016-17 में 27495 मी.ट. आयात, 2017-18 में 18013 मी.ट. आयात और अप्रैल, 2018 से अगस्त, 2018 तक “शून्य” के रूप में नोट किया गया है। आयातों में 2016-17 में लगभग 22 प्रतिशत और 2017-18 में 34 प्रतिशत तक गिरावट हुई और यह वर्ष 2018-19 (अगस्त, 2018 तक) शून्य हो गया। गिरावट की यह प्रवृत्ति सउदी अरब से आयातों पर बिना किसी शुल्क के लगाए जाने के कारण शून्य स्तर तक पहुंच गया है। इस कारण से उपर्युक्त प्रवृत्ति घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के किसी खतरे को स्थापित नहीं करती है और वास्तव में यह मूल जांच परिणामों में प्राधिकारी की इस सिफारिश को सही ठहराता है कि सउदी अरब से आयात पाटन और घरेलू उद्योग को हो रही परिणामी क्षति के बीच निर्णायक कारणात्मक संबंधी स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं था।
- (xiii) प्राधिकारी यह मानते हैं कि जांच की अवधि के तीन महीने में सउदी अरब से आयात यद्यपि बहुत अधिक था फिर भी प्राधिकारी सभी आवश्यक मानदंडों अर्थात् पाटन की सीमा, क्षति की सीमा और उससे भी महत्वपूर्ण पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन करने के लिए तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 के अंतर्गत पाटन (अनुचित) आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करने पर विचार करने के लिए 1995 के पाटनरोधी नियमावली की योजना और संरचना के अनुसार बाध्य थे। सउदी अरब द्वारा आक्रामक रूप से कब्जा किए जाने के बावजूद, कारणात्मक संबंध की गैर निर्णायक स्थापना प्राधिकारी को किसी उपाय की सिफारिश करने से रोक दिया क्योंकि कारणात्मक संबंध आवश्यक रूप से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करने के लिए एक मूलभूत शर्त है।
- (xiv) प्राधिकारी की यह मान्यता है कि पाटनरोधी नियमावली को अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने हेतु अधिदेश तथा योजना के अनुसार लागू किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि इस नियमावली के अंतर्गत दिए गए अधिदेश के अनुसार, किसी आवश्यक शर्त को पूरा नहीं किए जाने की स्थिति में, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने हेतु पाटनरोधी उपाय की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अधिदेश की सीमाओं से बाहर नहीं जा सकते हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुसार कोई पाटनरोधी उपाय उसी सीमा तक लागू किया जाता है जिस सीमा तक क्षति अथवा पाटन उसमें से जो भी कम हो, हुआ हो ताकि क्षतिग्रस्त घरेलू निर्माता के अलावा, प्रयोक्ता घरेलू उद्योग की चिंताओं को दूर किया जा सके। हालांकि आयातों की अधिक मात्रा जैसी स्थिति में जहां पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सभी शर्तों को पूरा नहीं किया गया हो, क्षतिग्रस्त घरेलू निर्माता किसी अन्य उपयुक्त व्यापार निदानात्मक उपायों के अंतर्गत समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

थ. निष्कर्ष तथा सिफारिशें :

67. इन मुद्दों का समाधान करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के निदेश, पाटनरोधी नियमावली और इस अधिनियम के अधिदेश, विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए संगत अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखकर प्राधिकारी का निष्कर्ष नीचे दिया गया है :
- (i) घरेलू उद्योग को तब भी जब सउदी अरब से कोई आयात नहीं हो रहा था, क्षति के विश्लेषण की समग्र अवधि के दौरान क्षति हो रही थी।
- (ii) वास्तविक क्षति के खतरे का मूल्यांकन जैसाकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निदेश दिया गया था, किए जाने के बाद प्राधिकारी यह मानते हैं कि जांच की अवधि के बाद अर्थात् अगस्त, 2018 तक के आयातों को देखते हुए, वास्तविक क्षति के खतरे को स्थापित नहीं किया गया है।

- (iii) उपर्युक्त को देखते हुए, मूल जांच परिणाम में प्राधिकारी की यह सिफारिश कि सउदी अरब से संबद्ध वस्तुओं का आयात निर्णायक रूप से पाटन और वास्तविक क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं किया, की भी पुष्टि हो गई है और इसे दोहराया जाता है।
- (iv) प्राधिकारी यह मानते हैं कि उपरोक्त (II) और (III) का विश्लेषण और व्याख्या ने यह सिद्ध किया कि सउदी अरब से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- (v) उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी इसे उपयुक्त नहीं मानते हैं कि वे सउदी अरब से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करें और एतद्वारा इस जांच को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के नियम 14 (ख), नियम 17(1)(iii), नियम 11(2) और पैरा (v) के अनुसार समाप्त करते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2018

FINAL FINDINGS

Subject : WP No. 7671 of 2018 (Andhra Petrochemicals Limited v. Union of India) High Court of Judicature at Hyderabad for the state of Telangana and the State of Andhra Pradesh, Hon'ble High Court order dated 31st July, 2018 in the final findings dated 28th November, 2017 issued in the anti-dumping investigation concerning imports of Normal Butanol or "N-Butyl Alcohol" originating in or exported from Saudi Arabia- Redetermination

No. 14/20/2016-DGAD.—Having regard to the aforesaid subject and the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules).

A. BACKGROUND

- a) The Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), under the above Rules, received a written application from The Andhra Petrochemicals Ltd. ('APL') (hereinafter referred to as the "petitioner") as domestic industry of the subject goods, alleging dumping of "Normal Butanol" or "N-Butyl Alcohol" (hereinafter also referred to as "subject goods" or "NBA") originating in or exported from Saudi Arabia (hereinafter referred to as the "subject country") and resultant injury to domestic industry and requesting recommendations for imposition of anti-dumping duty on imports of the product under consideration from the subject country.
- b) The Authority, on the basis of the aforesaid application initiated an investigation, against imports of the subject goods from the subject country on 02.09.2016.
- c) After detailed investigation and examination, the Authority recommended termination of investigation vide its final findings Notification No. 14/20/2016 - DGAD dated 28th November, 2017.
- d) Aggrieved by the recommendations of the Authority in the above referred Final Findings, M/s Andhra Petrochemicals Ltd., the domestic industry in this investigation, filed Writ Petition (Writ Petition No. 7671 of 2018) in the High Court of Judicature at Hyderabad for the state of Telangana and the state of Andhra Pradesh.
- e) The Hon'ble High Court passed final orders in Andhra Petrochemicals Limited v. Union of India (W.P. No. 7671 of 2018) on 31st July, 2018, remitting the matter back to the Designated Authority for consideration afresh taking into account the scheme and structure of the rules of 1995 of the final findings dated 28th November, 2017 and to complete the exercise expeditiously and in two months from the date of receipt of a copy of final order dated 31st July, 2018. The Authority received the certified

copy of the Final order on 31st August, 2018, although the order was available on the website of the High Court of Judicature at Hyderabad for the state of Telangana and the state of Andhra Pradesh even earlier.

- f) The Authority issued a Disclosure statement on 26th September, 2018 on the issues wherein the Hon'ble High Court had directed the Authority to revisit the final finding dated 28th November, 2017.
- g) Relevant extracts of the order dated 31st July, 2018 passed by the Hon'ble High Court are as under:
- (i) *“Rule 4 thereof, as already stated, sets out the duties of the designated authority and requires it to submit its findings, provisional or otherwise, to the Central Government not only as to the injury but also the threat of injury to an industry established in India or the material retardation to the establishment of an industry in India, consequent upon import of a like article from the specified countries. Therefore, the designated authority was wholly unjustified in holding that it had no mandate to look into the possible threat of injury to or material retardation of the domestic industry consequent upon the import of the product from Saudi Arabia. Rule 5(2) of the Rules of 1995 merely requires the application to specify the injury, where applicable, but that by itself would not circumscribe the duty of the designated authority under Rule 4(1)(c). Rule 11 also makes this clear as the designated authority is required thereunder to record a finding that import of the like article into India causes or threatens material injury to any established industry in India or materially retards the establishment of any industry in India. This Rule is captioned ‘Determination of injury’ and therefore makes it clear that the scope of the investigation is not dictated or restricted by the contents of the application made by the domestic industry under Rule 5(2).” (Refer page 20 and 21 of the Certified copy of the order referred)*
 - (ii) *“The refusal by the designated authority in the case on hand to look into any possible threat of injury or material retardation to the establishment of any industry in India therefore falls short of the statutory mandate. That apart, the specific conclusion of the designated authority was that the investigation had to be terminated in accordance with Rule 14(b) of the Rules of 1995...It is evident from the aforestated provision that it is only when the designated authority does not find sufficient evidence of dumping or, where applicable, injury to justify the continuation of the investigation that it can terminate it. In the case on hand, as already noted supra, the findings recorded by the designated authority clearly demonstrated sufficient evidence of dumping within the short span of three months by the exporters/ producers from Saudi Arabia and also the injury caused to the domestic industry thereby. Therefore, the designated authority could not have taken recourse to this clause for justifying the termination of investigation. In fact, none of the clauses in Rule 14, which deals with termination of investigation, had application whereby the designated authority could have taken such a step.” (Refer Page 21 and 22 of the certified copy of order referred)*
 - (iii) *“...the designated authority found that several other countries who were exporting the very same product to India had been subjected to anti-dumping measures, allowing exporters/producers from Saudi Arabia to do so without subjecting them to the same anti-dumping measures, even though their activities within a short span of three months clearly indicated their invasive capturing of the domestic market and the consequential injury to domestic industry, was clearly not warranted. Though the counter-affidavit stressed upon the designated authority not rendering final findings and recommendations only on the ground that the dumping took place for three months during the period of investigation, the final findings, as set out supra, clearly indicate to the contrary. It may also be noted that the Rules of 1995 specifically provide for extension of the period of investigation but despite the same, the designated authority did not deem it appropriate to seek such extension. (Page 22 and 23 of the Certified copy of order referred)*
 - (iv) *Though the learned Assistant Solicitor General for India appearing for the respondents would contend that Annexure-I to the Rules of 1995 would indicate that at least six months sales need to be taken into account, we are of the opinion that the argument is misconceived. Annexure-I relates to determination of normal value, export price and margin of dumping and in respect of all these three aspects, the designated authority had no difficulty in determining the normal value, export particulars and margin of dumping in relation to exporters/producers from Saudi Arabia. Further, Clause (2) in Annexure-I speaks of the period of six months in the context of sales made by such exporters/producers of the like product in their domestic market or to a third country for the*

purpose of determining the normal value and no more. This clause therefore does not indicate any requirement of the dumping being in excess of three months during the period of investigation, as wrongly assumed by the designated authority in its final conclusion. There is no mention of any length of duration being required in the context of the Rules of 1995 for ascertaining or evaluating the injury to the domestic industry by dumping of like products by exporters/producers from foreign countries, but all through, the designated authority linked the three months period, January to March, 2016, to justify his termination of the investigation, which is wholly unsustainable.” (Refer Page 23 of the certified copy of order referred)

h) The operative part of the order passed by Hon’ble High Court is as under:

“On the above analysis, this Court finds that the designated authority, having recorded findings in support of the injury sustained by the domestic industry by dumping of like products by exporters/producers from Saudi Arabia, failed to carry through on the same note and strangely did a volteface, when it came to the final recommendation. This was on the strength of his misconceived notion that a three month span of dumping was insufficient for recording a finding. As we have already noted that there is no such mandate in the Rules of 1995, the Final Findings dated 28.11.2017 are set aside and the matter is remitted to the designated authority for consideration afresh, taking into account the scheme and structure of the Rules of 1995 and the observations made hereinabove. This exercise shall be completed expeditiously and, in any event, not later than two months from the date of receipt of a copy of this order.” (Refer Page 24 of the certified copy of order referred)

The Authority therefore in accordance of the Hon’ble High Court’s order has addressed various issues raised in this remand investigation.

B. PROCEDURE

1. The procedure described below has been followed:

- a) In compliance with the order of Hon’ble High Court, the Authority provided an opportunity to interested parties to present their views orally in an oral hearing held on 13th August, 2018. The oral hearing was attended by the Domestic Industry and other interested parties.
- b) The interested parties who presented their views orally at the time of oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed by them orally and were allowed to file rejoinders to the submissions made by the opposing parties. The following interested parties filed submissions subsequent to the oral hearing:
 - i. M/s TPM representing M/s Andhra Petrochemicals Ltd. (Domestic Industry)
 - ii. Embassy of Kingdom of Saudi Arabia
 - iii. M/s LKS representing Saudi Butanol Company (SABUCO), Saudi Acrylic Acid Company (SAAC), Sadara Chemical Company (SADARA), Petrochem Middle East FZE (PETROCHEM), National Industrialization Petrochemical Marketing Co (TASNEE MARKETING) and Toyota Tsusho Corporation (TOYOTA)
- c) All the relevant submissions made by interested parties during the earlier round of investigation (which resulted in final findings dated 28th November, 2017) and submissions during the remand proceedings by Hon’ble High Court vide order dated 31st July, 2018 the observations made by Hon’ble High Court and submissions to the disclosure statement have been taken into account in this finding.
- d) The Authority made available non-confidential version of the submissions/evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. The public file was inspected by interested parties and who requested copies of the documents from the public file, were provided the same.
- e) Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. The Authority accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis, which was made available through public file.

- f) The Non-injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') considering the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry. This remains unaltered in this redetermination.
- g) The POI in the original Investigation was considered as 1st April 2015 to 31st March 2016 (12 months) (hereinafter referred to as the 'period of investigation' or the 'POI'). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from 2012-13, 2013-14, 2014-15 and the POI. The Authority has considered post POI period import data for the period 2016-17, 2017-18 and April, 2018 – August, 2018 as available from DGCIS to evaluate threat of material injury in accordance with the Hon'ble High Court's Order.
- h) Exchange rate for conversion of US\$ to Rs. is considered for the POI as Rs.65.91 as per customs data.
- i) *** in this Final Findings represents information furnished by the interested parties on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 2. The Hon'ble High Court has not made any specific observations with regard to scope of product under consideration and like Article in its order dated 31st July, 2018. The Authority further notes that none of the interested parties have raised any issues with regard to the product under consideration and like article in the present remand proceedings. The Authority has therefore not revisited examination with respect to product under consideration and like article in the present finding.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

- 3. The Hon'ble High Court has not made any specific observations with regard to scope of domestic industry in its order dated 31st July, 2018. The Authority further notes that none of the interested parties have raised any issues with regard to the domestic industry in the present remand proceedings. Therefore, the Authority has not revisited examination with respect to domestic industry and standing in the present finding.

E. MISCELLANEOUS ISSUES

a. Views of the Domestic Industry

- 4. The domestic industry has made the following submissions: -
 - a) There was no need for granting oral hearing in the present remand proceedings. The High Court has not directed the Designated Authority for holding the oral hearing in the present case. Had the High Court wished the Designated Authority to hear the interested parties, the same would have been specifically stated by the High Court in its order. CESTAT in the matter of Rubber Chemicals, wherein the CESTAT has remanded the case back to the Designated Authority and wherein the CESTAT had specifically directed the Designated Authority to hear the interested parties.
 - b) In a remand back proceeding, the Designated Authority is not required to undertake fresh determination. The Designated Authority is required to only address the issues raised by the interested parties before High Court and decided by High Court. The Designated Authority is required to consider the matter only to extent remanded back by the High Court. The Designated Authority is not required to examine any other aspect of the case. The petitioner requests the Designated Authority to consider the order and recommend imposition of anti-dumping duty. Therefore, the Designated Authority is required to only address the issue raised by the petitioner to reconsider the causation of injury suffered by the domestic industry due to dumped imports from Saudi Arabia and modify the final findings in the light of the observations made by High Court. The Designated Authority may, therefore not entertain any argument with regard to appropriateness or otherwise of the High Court order made by the interested parties.
 - c) The argument of interested parties at the time of oral hearing tantamount to challenging correctness or otherwise of the decision of the High Court. Firstly, the party did not participate in the Writ Petition decided by the High Court. Secondly, scope of present proceedings is not to review the correctness or otherwise of the order of High Court. The Designated Authority is not required to consider the correctness or otherwise of the order of the High Court. The Designated Authority may, therefore not entertain any

argument with regard to appropriateness or otherwise of the High Court order made by the interested parties.

b. Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

6. M/s Lakshmi Kumaran & Sridharan Attorneys representing producers/exporters from Saudi Arabia viz. Saudi Butanol Company, Saudi Acrylic Acid Company, Sadara Chemical Company, National Petrochemical Industrialization Marketing Company, Toyota Tsusho Corporation, Petrochem Middle East FZE has submitted the following:

- a) Domestic industry has claimed that no oral hearing was required in the present case since there is no specific direction by the Hon'ble High Court to conduct oral hearing. Firstly, the submission of the domestic is redundant since the oral hearing has already taken place and the domestic industry has also participated in the same. Secondly, it is incorrect to state that oral hearing is not required because Hon'ble High Court has not given any specific direction in this regard. There is no requirement of specific direction from the Hon'ble High Court to conduct oral hearing. The Hon'ble High Court has directed the Designated Authority to make afresh determination based on the scheme and structure of the Anti-dumping Rules 1995, which includes the requirement to conduct oral hearing. Rule 6 (6) of the Anti-dumping rules provides for the opportunity of oral hearing to interested parties.
- b) Moreover, Hon'ble Supreme Court in the case of Automotive Tyre Manufacturers Association vs. The Designated Authority and Ors. [(2011)2SCC258] has specifically observed that oral hearing is mandatory because principles of natural justice are required to be followed in the case of anti-dumping investigation. Hon'ble Supreme Court observed that:

"It is thus, well settled that unless a statutory provision, either specifically or by necessary implication excludes the application of principles of natural justice, because in that event the Court would not ignore the legislative mandate, the requirement of giving reasonable opportunity of being heard before an order is made, is generally read into the provisions of a statute, particularly when the order has adverse civil consequences which obviously cover infraction of property, personal rights and material deprivations for the party affected.....In light of the aforementioned legal position and the elaborate procedure prescribed in Rule 6 of 1995 Rules, which the DA is obliged to adhere to while conducting investigations, we are convinced that duty to follow the principles of natural justice is implicit in the exercise of power conferred on him under the said Rules.... Even written arguments are no substitute for an oral hearing. A personal hearing enables the authority concerned to watch the demeanour of the witnesses etc. and also clear up his doubts during the course of the arguments." (emphasis added)

Thus, there is no doubt that the law laid down by the Hon'ble Supreme Court is required to be followed and hearing is to be granted by the Designated Authority before issuing the final findings even in the case of remand proceedings.

- c) Domestic industry submitted that the order of the Hon'ble High Court is not open for review by any interested party. It is agreed that the order of the Hon'ble High Court cannot be reviewed or revised by the interested parties. However, we cannot be prevented from raising legal arguments after taking into account the observations of the Hon'ble High Court. As already stated, the Hon'ble High Court has directed the Designated Authority to make afresh determination based on the scheme and structure of the Anti-dumping Rules and after considering the observations made in its judgment. Accordingly, we have made detailed submission based on the structure and scheme of the Anti-dumping Rules and based on the observations of the Hon'ble High Court.
- d) Domestic industry claims that in the remand proceedings the Designated Authority is not required to undertake fresh determination and is not required to examine other aspects of the case. The claim of the domestic industry is in direct contravention with the observations made by the Hon'ble High Court. The Hon'ble High Court has directed the Designated Authority to make "afresh" determination based on the structure and scheme of the Anti-dumping Rules. Hon'ble High Court has observed that:

"As we have already noted that there is no such mandate in the Rules of 1995, the Final Findings dated 28.11.2017 are set aside and the matter is remitted to the designated authority for consideration a fresh, taking into account the scheme and structure of the Rules of 1995 and the observations made hereinabove." (emphasis added)

Thus, it is clear that the Hon'ble High Court has not prevented the Designated Authority from considering all the legal issues and in fact has specifically directed to issue "a fresh" determination. Hon'ble High Court has specifically granted 2 months time to the Designated Authority to issue a fresh determination.

- e) Domestic industry claimed that Respondents did not participate in the writ petition before the Hon'ble High Court and the argument of the Respondents before the Designated Authority is tantamount to challenging the correctness or otherwise of the decision of the Hon'ble High Court, which cannot be permitted. The domestic industry did not make producers/exporters from Saudi Arabia as Respondents in the Court proceedings. Consequently, no notice was served by the domestic industry or by the Hon'ble High Court on the Respondents regarding the writ petition filed by the domestic industry. Thus, non-participation of the Respondents before the Hon'ble High Court does not imply lack of co-operation of any kind from the Respondents and it cannot be held against them. The Respondents have been determined as co-operating parties by the Designated Authority in the original investigation and have duly participated in the hearing before the Designated Authority that was scheduled pursuant to the remand proceedings.
- f) It is incorrect to state that argument of the Respondents tantamount to challenging the correctness or otherwise of the decision of the Hon'ble High Court. The domestic industry has failed to identify even one submission or argument of the Respondent which questions the correctness of the decision of the Hon'ble High Court. In fact, the Respondents have made submissions in compliance with the specific directions of the Hon'ble High Court and after taking into account all the observations of the Hon'ble High Court. Thus, nothing prevents the authority from taking into account the legal issues raised by the Respondents.

c. Examination by the Authority

- 7. The Authority notes that being a Quasi-Judicial body, it is required to follow the principles of natural justice and interested parties have been provided an opportunity of being heard. The Authority followed the mandate of AD Rules to conduct an oral hearing and provide an opportunity to interested parties to make their submissions before the Authority.
- 8. The Authority further notes that Hon'ble Supreme Court in Automotive Tyre Manufacturers Association vs. The Designated Authority and Ors. has held that the Authority is required to conduct an oral hearing before issuing the final findings. The Authority notes that the Hon'ble High Court has not restrained the Authority to hold an Oral hearing. Inviting submissions from all interested parties on various facets of AD Rules and Act in no way undermines the principles of natural justice.

F. Determination of Normal Value, Export Price and Dumping Margin

- 9. The Hon'ble High Court has not made any specific observations with regard to normal value, export price and dumping margin in its order dated 31st July, 2018. The Authority further notes that none of the interested parties have raised any issues with regard to the normal value, export price and dumping margin in the present proceedings. Therefore, the Authority has not revisited its examination with respect to determination of normal value, export price and dumping margin in the present finding, and these remain the same as evaluated in the original finding dated 28.11.2017.

G. INJURY

- 10. The Authority notes that Hon'ble High Court had made certain observations on the issue of injury and causal link. Further, interested parties during the course of remand proceedings have made elaborate submissions on injury and causal link. Therefore, the Authority has reexamined the injury and causal link aspect in the present finding.

a. Submissions made by the Domestic Industry

11. The domestic industry has submitted that: -

- a) Imports from the subject country started in January 2016 and the volume of such dumped imports in just three months was significant enough to cause material injury to the domestic industry.
- b) The petitioner has segregated the entire injury information within the POI into two parts – (i) April – December 2015 – when there were no imports from the subject country, and, (ii) January – March 2016 – when the imports from the subject country started.
- c) While still examining the injury to the domestic industry during the POI, the Authority may additionally consider the period January to March 2016, in particular, to examine the extent and degree of injury caused to the domestic industry by dumped imports from the subject country.
- d) Imports in the post POI period shows that the imports during the POI were not casual exports to India from a new plant, but a market opportunity seen by the subject exporters to dump the product.
- e) The capacities with SABUCO, the production sharing by the three promoter companies and the options with them for utilization of the production further shows that the imports in the POI were not casual, but were conscious decisions of these companies to grab the Indian market.
- f) There is significant difference between the prices offered by the domestic industry and the foreign producers. Thus, the domestic industry is unable to raise the prices above the costs as a result of dumping of the product in the Country.
- g) Even when the domestic industry has been offering sub-optimal prices, it was losing sales. Thus, decline in sales volumes is a direct consequence of dumped imports from the subject country.
- h) Despite sub-optimal prices offered by the domestic industry, the imports were undercutting the prices of the domestic industry and creating price pressure on the domestic industry.
- i) Imports are depressing the prices of the domestic industry and preventing the price increases that would have occurred in the absence of dumping.
- j) Performance of the domestic industry with respect to sales, production and capacity utilization had improved as investigations for imposition of anti-dumping duty on other sources were under process in the first nine months of the POI, i.e. April-December 2015. However, the performance in respect of the above parameters has significantly deteriorated in the last three months of the POI, i.e. January-March 2016 as fresh dumping from the subject country started. Further, the Authority had notified positive findings recommending imposition of anti-dumping duty on imports from these sources on 19th February 2016.
- k) Performance of the domestic industry was adverse in terms of profits, return on investments and cash profit throughout the injury period. Situation has worsened with the commencement of dumped imports from the subject country in Jan-Mar 2016 period of the POI.
- l) Dumping margin is significant.
- m) The most important factor affecting the prices of the domestic industry is import price from subject country. Thus, the price depression is due to dumping of the product in the market.
- n) Growth of the domestic industry is adverse in terms of both, volume and price parameters.
- o) The domestic industry has suffered material injury as a result of dumping from the subject country.
- p) The injury margin is significant.
- q) Definitive anti-dumping duty is required to be imposed in accordance with the dumping margin and injury margin.
- r) The form of measure is required to be kept as fixed quantum in US\$.
- s) The purpose of segregation of POI in two parts is to show the effect of dumping of the subject goods on the performance of domestic industry and its causal link with injury.

- t) The impact of dumping of subject goods in just 3 months is so significantly felt, that, material injury has been caused to the domestic industry.
- u) Imports upto Dec., 2015 were from other sources dumping the product under consideration and where ADD was imposed after March, 2016. Imports from Saudi started in last quarter of the POI and were significant in no time. Shifting of dumping from one source to other source does not imply that causal link is broken.
- v) The issue concerning shut down because of fire in the plant of propylene supplier of petitioner in the previous period has already been examined by the Designated Authority.
- w) The cause of plant shut down in the present POI was suspension of production in view of un-remunerative prices in the market because of the presence of low priced dumped imports from the subject country.
- x) Domestic industry is not required to cater to 100% of the demand before seeking protection under the law. Further, there is no restriction on imports of the product in the country at fair prices.
- y) In the light of the order of the Hon'ble High Court, Andhra Pradesh and information earlier provided, the petitioner requests the Authority to kindly:
- Consider the determination made wherein the Authority has already concluded the following:
 - Imports from Saudi Arabia entered India in significant volume in the last three months of the period of investigation, both in absolute terms and in relation to production and consumption in India.
 - There was significant price undercutting of 25% to 35% by the Saudi Arabian exporters/producers during these three months.
 - There was price underselling to the extent of 55% to 75%.
 - Performance in respect of the parameters of sales, production and capacity utilization deteriorated in the last quarter of the period of investigation i.e. January to March 2016 as fresh dumped imports from Saudi Arabia started.
 - The injury margins determined by the Authority in respect of exporters from Saudi Arabia were also high, ranging from 70% to 90%.
 - Modify the final findings in so far as the following observations of the Authority are concerned:
 - Period of last 3 months of POI of exports of subject goods from Saudi Arabia is not sufficient to evaluate injury to the domestic industry as material injury determination would require data on imports and domestic industry's sales for a longer duration.
 - Causal link between imports from Saudi Arabia and injury to the domestic industry is not conclusively established on the basis of 3 months of export period.
 - The Authority in view of the above does not consider it appropriate to recommend levy of an Anti-Dumping Duty on the subject goods from Saudi Arabia and hereby terminates the investigation in accordance with Rule 14 (b) of AD Rules.
- z) The argument that the Designated Authority had not made any final conclusion regarding the inappropriateness of the POI *per se* in the present anti-dumping investigation made during the last three months of the POI is to say that the Final Finding is incomplete and deficient, and that the Designated Authority issued final findings even without first establishing appropriateness of the POI is incorrect as the Designated Authority concluded its finding in para 94 (vii) of final finding. Moreover, Hon'ble High in its judgment categorically held that 3 months imports in the POI are sufficient to determine dumping and consequent injury to domestic industry. Any such argument however at this stage is not tenable. The issue is not open for consideration at this stage and has already attained finality.

The Authority has determined positive and, in fact, significant dumping margin and injury margin in respect of exports made by the exporter. The Hon'ble High Court has also observed in this regard that the findings recorded by the designated authority clearly demonstrated sufficient evidence of dumping

and the domestic industry suffered injury. There is no legal requirement under the law that the dumped imports should exist in the entire period of investigation.

- aa) As regards the submissions that the petition did not specifically disclose the fact that imports from Saudi Arabia took place only in the last three months of the POI, the interested parties have no locus standi to challenge the final finding on this aspect now, before the Designated Authority. The interested party is trying to mislead the Authority, by advancing highly misleading and factually incorrect statement. The petitioner provided complete listing of imports for the entire injury period in the petition. It is evident from the information provided that the imports occurred in the POI only.

Another meaning of the argument of the exporter is that the Authority carelessly initiated the investigation.

There is no requirement in the AD law to require the continuity of the imports over the entirety injury period or in entirety of the POI. The requirement for imposing the antidumping duties is that the imports from the subject country should be more than 3% and the prices are dumped prices.

- bb) The issue of POI being of at least 6 months is not open for consideration at this stage and has already attained finality. The Designated Authority may therefore not entertain any argument with regard to appropriateness or otherwise of the High Court order.

Another interpretation of the argument is that the Designated Authority should have different yardstick for one country and more than one country case. If dumping is occurring only from one country, such dumping should have been uniformly spread through the investigation period. But, if dumping is happening from more than one country, it is OK if dumping is sporadic from different countries within the investigation period! The argument of the exporter implies that in some combination of countries, the Designated Authority would accept petition. In some combination, the Designated Authority would reject the petition.

The Hon'ble High Court has observed in the present matter as follows:

"...Clause (2) in Annexure-I speaks of the period of six months in the context of sales made by such exporters/producers of the like product in their domestic market or to a third country for the purpose of determining the normal value and no more. This clause therefore does not indicate any requirement of the dumping being in excess of three months during the period of investigation, as wrongly assumed by the designated authority in its final conclusion.....There is no mention of any length of duration being required in the context of the Rules of 1995 for ascertaining or evaluating the injury to the domestic industry by dumping of like products by exporters/producers from foreign countries, but all through, the designated authority linked the three months period, January to March, 2016, to justify his termination of the investigation, which is wholly unsustainable."

- cc) The Hon'ble High Court in its judgment categorically held that 3 months imports in the POI are sufficient to establish causal link between dumped imports and consequent injury to domestic industry. Any such argument however at this stage is untenable and attained finality. Now it is not open for the interested parties to raise such contentions.
- dd) The final findings has incorrectly analysed causal link between dumping and injury suffered by the domestic industry due to dumped imports from Saudi Arabia as observed by the Hon'ble High Court. Since the High Court has already decided the issue of whether dumping caused injury, the issue cannot be argued by the interested parties. The Designated Authority may therefore not entertain any argument with regard to appropriateness or otherwise of the High Court order.

*".....it is only when the designated authority does not find sufficient evidence of dumping or, where applicable, injury to justify the continuation of the investigation that it can terminate it.....In the case on hand, as already noted supra, the findings recorded by the designated authority clearly demonstrated sufficient evidence of dumping within the short span of three months by the exporters/ producers from Saudi Arabia and also **the injury caused to the domestic industry thereby**. Therefore, the designated authority could not have taken recourse to this clause for justifying the termination of investigation. In fact, none of the clauses in Rule 14, which deals*

with termination of investigation, had application whereby the designated authority could have taken such a step.”

- ee) As regards domestic industry not having presented any facts, information or argument against the decision of the DA regarding absence of causal link before the Hon’ble High Court tantamount to challenging correctness or otherwise of the decision of the High Court. The argument also tantamount to stating that the High Court has passed the order without application of mind. Firstly, the party did not participate in the Writ Petition decided by the High Court. Secondly, scope of the present proceedings is not to review the correctness or otherwise of the order of High Court. The Designated Authority is not required to consider the correctness or otherwise of the order of the High Court. The Designated Authority may therefore not entertain any argument with regard to appropriateness or otherwise of the High Court order.

The decision of the Hon’ble High Court is based on the submissions made by the domestic industry and the Designated Authority. The Designated Authority may, therefore, not entertain any argument with regard to appropriateness or otherwise of the High Court order made by the interested parties.

- ff) The argument that the DA has inadvertently summarized in paragraph 74 of the Final Findings that dumped imports from subject country as well as other non-subject countries have adversely impacted the performance of the domestic industry. The Designated Authority is only required to remove paragraph 74 of the Final Findings to conclude that there is no need for imposition of anti-dumping duty on imports from the subject country tantamounts to review of not only the order of the Designated Authority but also of the High Court. Petitioner submits that the interested parties are not entitled to review the order of either the Designated Authority or the High Court. On facts, the observation of the Authority in paragraph 74 is correct.
- gg) The domestic industry had provided the relevant information in the written submissions dated 27th October 2017 with regard to threat of material injury. However, the Authority had not considered this information as has been observed by the Hon’ble High Court as follows:

“...the designated authority was wholly unjustified in holding that it had no mandate to look into the possible threat of injury to or material retardation of the domestic industry consequent upon the import of the product from Saudi Arabia....The refusal by the designated authority in the case on hand to look into any possible threat of injury or material retardation to the establishment of any industry in India therefore falls short of the statutory mandate....”

b. Views of Exporters, Importers, Consumers and other Interested Parties

12. The other interested parties have submitted as follows: -

- a) The application neither fulfills the preconditions for initiation nor qualifies the test of adequacy and accuracy under Rule 5 as sufficient evidence establishing dumping, injury and causal link was not supplied.
- b) Confidentiality - Some of the information provided in the non-confidential version of the Petition is either misleading or insufficient to allow the interested parties to comment meaningfully thereupon. The domestic industry must be directed to disclose the data at least in ranges to allow a meaningful understanding of that table.
- c) Price undercutting margins alleged in the petition should not be considered. Exports are made by Saudi Arabian producers to Indian traders, who incur expenses of storage and warehousing. These costs increase the landed value by 25 – 30%. Price undercutting should be based on comparison of domestic selling price with the resale price of traders in India.
- d) There is absence of causal link between the imports from Saudi Arabia and injury suffered by the domestic industry. Imports from Saudi Arabia increased from NIL in 2014-15 to 8,791 MT in the POI. The sales of domestic industry also increased by 7,117 MT over the same period.
- e) Imports from the other countries were coming into India at dumped prices and free of anti-dumping duty in the POI, which was imposed after the completion of POI. Imports from Saudi Arabia entered Indian market only for the last 3 months of the POI (Apr 15 to Mar 16) and the entire injury period.

- f) The injury suffered is self-inflicted by the domestic industry. The Annual Report of the petitioner shows that they have only one source of raw material supply and had to shut down plant because of fire accident in the plant of the supplier.
- g) Imposition of anti-dumping duties on imports from Saudi Arabia would go against the public interest. There is a demand supply gap. The domestic industry would be able to supply only 32% of demand in India even when producing at full capacity.
- h) There is absence of non-confidential versions of costing data.
- i) Price undercutting margins alleged in the petition should not be considered. Exports are made by Saudi Arabian producers to Indian traders, who incur expenses of storage and warehousing. These costs increase the landed value by 25 – 30%. Price undercutting should be based on comparison of domestic selling price with the resale price of traders in India.
- j) Imports from the other countries were coming into India at dumped prices and free of anti-dumping duty in the POI, which was imposed after the completion of POI. Imports from Saudi Arabia entered Indian market only for the last 3 months of the POI (Apr 15 to Mar 16) and the entire injury period.
- k) The injury suffered is self-inflicted by the domestic industry. The Annual Report of the petitioner shows that they have only one source of raw material supply and had to shut down plant because of fire accident in the plant of the supplier.
- l) Imposition of anti-dumping duties on imports from Saudi Arabia would go against the public interest. There is a demand supply gap. The domestic industry would be able to supply only 32% of demand in India even when producing at full capacity.
- m) Domestic industry has segregated POI in two periods (i) April to December 2015 and (ii) January to March 2016. Domestic industry does not dispute that there were no imports from the subject country in the first period i.e. for first 9 months of the POI. Domestic industry also admits that period of data collection in the present investigation is effectively of three months and not one year as identified by the Designated Authority. Domestic industry does not deny that the period of data collection for dumping investigations normally should be twelve months and in any case not less than six months. However, Domestic industry relies on the observation made by the Committee of Anti-dumping practices that investigating authority can take into account particular circumstances of a given investigation in setting the periods of data collection for both dumping and injury to ensure that they are appropriate in each case. Domestic industry claims that dumping, injury and causal link is to be determined based on the import data of three months.
- n) The claim of the domestic industry cannot be accepted; Firstly, Domestic industry fails to provide for 'particular circumstance' that would necessitate shorter period of investigation; Secondly, the Designated Authority as a matter of practice has followed the recommendation of Committee on Anti-dumping practice in all investigations in past. Domestic industry has failed to provide even one instance in India or in any other jurisdiction where assessment of dumping, injury and causal link is based on the data of three month period only; Thirdly, if the 'particular circumstance' in the present case would have required a shorter period of investigation for data collection, the Designated Authority would not have formally selected one year as the period of investigation in the notice of initiation. In other words, the Designated Authority has already decided that there is no 'particular circumstance' that would necessitate shorter period of investigation; Fourthly, the reliance by the Domestic industry on the observations made by the Panel in *Guatemala – Cement II* is incorrect. Observation of Panel is regarding duration of injury investigation period and not POI. In fact, Panel in *Guatemala – Cement II* allowed a shorter period of one year and not three months for determination of injury due to existence of particular circumstance.
- o) Merely because the Anti-dumping Agreement does not expressly mandate specific duration for POI does not mean that selection of a shorter time duration of one month, two months or three months as POI is permitted. Appellate Body in *EC-Tube or Pipe Fittings* clearly noted that a POI provides data collected over a sustained period of time, which period can allow the investigating authority to make a dumping determination that is less likely to be subject to market fluctuations or other vagaries that may distort a proper evaluation.

- p) If the Designated Authority will base its determination regarding dumping, injury and causal link based on a three month time period, it will set a wrong precedent. There would be no minimum duration for which import data has to be analyzed and determination will be based even in cases where imports are occurring for one month or two months. Moreover, it cannot be disputed that three month data cannot reasonably reflect the export behavior of the producers and exporters in Saudi Arabia. Anti-dumping duty recommendation is prospective in nature, which is applicable for next five years. It is required that assessment of dumping, injury and causal link is based on the import data which is reflective of the export behavior of the producer and exporter in the exporting country. Thus, it is incorrect to contend that shorter period of three months is consistent with the provisions of WTO Anti-dumping Agreement and the Anti-dumping Rules. Consequently, entire claim of dumping, injury and causal link that is based on three months data is incorrect and unreliable.
- q) If the Designated Authority decides to continue the investigation despite the fact that there is import data of only three months, it is submitted that there can be no bifurcation of the period of investigation into nine months and three months for assessment of injury and causal link. Domestic industry cannot continue to sub-divide the period of investigation once the same is fixed by the Designated Authority. Considering the period of investigation as a whole, there is complete absence of causal link between the imports originating in Saudi Arabia and the alleged injury. The production & domestic sales of the domestic industry increased in the same period when the imports from Saudi Arabia entered India, therefore signifying that imports from Saudi Arabia had no impact on the performance of the domestic industry. Similarly, production capacity remained stable and production, capacity utilization and market share increased. Below table is illustrative:

Production capacity of the domestic industry and total demand in India in MT

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Imports from Saudi Arabia	MT	0	0	0	8,791
Imports from EU, Malaysia, Singapore, South Africa & the USA	MT	31,929	42,016	55,243	50,606
Total Demand	MT	46,769	49,798	59,243	70,552
Production capacity	MT	22,500	22,500	22,500	22,500
Sales	MT	14,472	6,425	4,037	11,154
Production	MT	14,409	5,484	4,203	11,080
Capacity utilization	%	64.04%	24.37%	18.68%	49%
Market share	%	31%	13%	7%	16%

- r) Thus, the injury suffered by the domestic industry, if any, is attributable to imports of normal butanol exported from the EU, Malaysia, Singapore, South Africa and the USA which constituted 85% of the volume of imports and had a 72% share in the domestic demand. Further, the factors such as the shutdown of the production plant for 7 months, the fire accident of 23 August 2013, the lasting consequences of those two events and the shortage in the supply of raw materials have caused the alleged injury suffered by the domestic industry.
- s) Domestic industry is for the first time claiming that imports Saudi Arabia are causing threat of material injury based on post POI data. At the onset, it is submitted that Domestic industry cannot now claim that there is threat of material injury. Scope of investigation is determined by the initiation notice which did not provide for assessment of threat of Injury. The Domestic industry has never alleged threat of material injury at the time of filing of the petition or even during the public hearing. Present investigation is limited to the assessment of material injury as alleged in the petition and for which the Designated Authority determined that there was prima facie evidence in the notice of initiation. It is settled practice of the Designated Authority that post POI period is not considered for assessment of material injury in the original investigation. In the recently concluded Anti-dumping investigation concerning imports of Wire Rod of Alloy or Non-Alloy Steel originating in or exported from China PR, the Designated Authority observed that:

“With regard to the contention of the interested parties that post POI trends should be examined, the Authority notes that in an original investigation, post POI trends are not relevant. In case of reviews initiated in terms of Rule 23 of the AD Rules, would post POI trends become relevant because the Authority has to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury if anti-dumping duty is withdrawn”

It is an established practice of the Designated Authority to determine material injury based on the data of the POI in the original investigation. In other words, post POI data is irrelevant in the original investigation.

- t) As explained in the questionnaire responses, the commercial production of normal butanol in Saudi Arabia started on 1st March 2016. Some exports of trial production product took place from Saudi Arabia to India during January 2016 and February 2016. Thus, imports into India were only made during the last three months of the POI, namely in January 2016, February 2016 and March 2016. Below table is illustrative:

Monthly volume of imports in MT during the POI

Particulars	April 2012 to March 2015	April 2015 to Dec 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mar 2016	POI
Saudi Arabia	0	0	2,154	3,131	3,506	8,791

Source: Transaction-by transaction listing in the Petition

- u) Thus, in fact POI considered by the Designated Authority is of 3 months only even though technically it is named as one-year period.

Period of investigation in case of anti-dumping investigation should be of at-least six months

- v) Petition filed by the domestic industry noted that:

"Information regarding imports and market share is provided in the injury information enclosed. It would thus be seen that there were no imports from Saudi Arabia up to 2014-15. There is significant volume of imports in absolute terms from Saudi Arabia in the proposed POI" (pg. 13)

- w) Thus, the petition (non-confidential version) did not specifically disclose the fact that imports from Saudi Arabia took place only in the last three months of the POI.
- x) Be that as it may, from a perusal of the final findings issued by the Designated Authority, we understand that Domestic industry has relied on the several previous findings of the Designated Authority to support its claim that anti-dumping duty can be recommended in the present case:

- (i) Ammonium Nitrate from Georgia, Indonesia & Iran
- (ii) Flexible Slabstock Polyol from Australia, EU & Singapore
- (iii) R-DVD from Malaysia, Thailand & Vietnam
- (iv) Thermal Sensitive Paper from Indonesia, Malaysia & UAE
- (v) Certain Phosphorous based compounds
- (vi) Diclofenac Sodium from China
- (vii) Caustic Soda from Qatar
- (viii) Vitamin A Palmitate from EU, Singapore and Georgia
- (ix) Vitrified/ Procelain Tiles from China and UAE.

- y) In the case of *Ammonium Nitrate from Russia, Indonesia, Georgia & Iran*, the subject goods were imported from Georgia during the 2015-16 period i.e. POI. However, the domestic industry claims that imports occurred during only during three months of the POI from Georgia i.e. during July, Aug & Feb in 2015-16 period. The domestic industry has not presented following facts of the case:

- (i) There is no observation in the final findings that subjects goods were imported from Georgia during three months in the POI. Moreover, no claim was made by the interested parties that the

subject goods were imported from Georgia only for three months and therefore such an issue was not examined by the Designated Authority. The exporter from Georgia was also determined to be non-cooperative.

- (ii) Subject goods were imported during the injury investigation period (including the POI) from other subject countries namely Russia, Iran and Indonesia.
 - (iii) Unlike the present investigation, due to imports from subject countries during the first three years of injury investigation period and during the period of investigation, the POI was not effectively of 3 months only.
- z) Thus, complete analysis of the case based on the aforementioned facts makes it clear that the finding of the Designated Authority in Ammonium Nitrate from Georgia, Indonesia & Iran cannot be relied upon to support the claim of the domestic industry.
- aa) In the case of Caustic Soda from Qatar, POI was determined to be 1 January 2001 to 30 September 2001. Subject goods were imported from Qatar during the POI. The domestic industry relied on the fact that subject goods were not imported from one of the participating exporter during the POI and in such a case, anti-dumping duty was imposed based on his sales contract with Indian importers. The domestic industry has once again failed to note that unlike the present case, subject goods were imported from subject country Qatar during the POI. The fact that there were no imports of subject goods during the POI from one exporter M/s Qatar Vinyl Company (QVC) Ltd. is an exporter specific concern and is not equivalent to a situation where there is absence of imports from subject country in general.
- bb) In the case of Flexible Slabstock Polyol from Australia, EU & Singapore, subject goods were imported from Australia during the POI (January 2012 to December 2012)
- cc) In the present case, Respondents have specifically relied on the recommendation of the Anti-dumping Committee which prescribes minimum six months period of data collection i.e. minimum six of months of POI. Thus, a finding of the Authority which notes that subject goods were imported during the POI of one year, does not in any way contrast the claim of the Respondent. Similarly, in (i) R-DVD from Malaysia, Thailand & Vietnam (ii) Thermal Sensitive Paper from Indonesia, Malaysia & UAE (iii) Certain Phosphorous based compounds – POCl_3 from EU and China (iv) Diclofenac Sodium from China (v) Vitamin A Palmitate from EU, Singapore and Georgia & (vi) Vitrified/ Procelain Tiles from China and UAE, the subject goods were imported during the POI and therefore there is no similarity of facts of these cases with the present case. There is no observation in the final findings of these cases that subject goods were imported only during three months in the POI. Moreover, no claim was made by the interested parties in these cases that the subject goods were imported only for three months and therefore such an issue was not examined by the Designated Authority.
- dd) In sum, none of the past decisions of the Authority referred by the domestic industry are applicable in the present case. Therefore, it is incorrect to claim that past decision of the Designated Authority substantiates the claim of the domestic industry that it is appropriate to recommend the imposition of anti-dumping in the present case. In fact, there is no previous case in India in which the Designated Authority has recommended anti-dumping duty based on the period of investigation of 3 months.
- ee) WTO Anti-dumping Agreement & Indian Anti-dumping Rules do not expressly provide any specific period as the minimum duration for period of investigation. However, absence of a specific provision in the Anti-dumping Rules does not mean that there is no guidance regarding the appropriateness of the POI and the authority can consider a short period of three months, two months or one month as appropriate for the purpose of anti-dumping investigation. Recommendation by the WTO Committee on Anti-dumping Practices provides that:

“The Committee recommends that with respect to original investigations to determine the existence of dumping and consequent injury -

1. as a general rule:

(a) the period of data collection for dumping investigations normally should be twelve months, and in any case no less than six months, ending as close to the date of initiation as is practicable.”
(emphasis added)

- ff) The WTO Anti-dumping Committee considers that minimum period of six months of data collection is appropriate to determine existence of dumping, injury and causal link. The guideline effectively means that the period of investigation should be such that it shall have at-least 6 months of import data from the subject country. Even though it is in the form of a recommendation, there is no ambiguity in the guideline regarding the obligatory nature of the provision which stresses that the minimum period should be 'no less than six months'.
- gg) Notwithstanding this committee recommendation, the WTO Panel and Appellate Body have observed in several cases that the fixation of POI is not un-regulated under the Anti-dumping Agreement and should cover a representative period. WTO Panel in the *Mexico – Steel Pipes* recognised that lack of express requirement in Anti-dumping Agreement regarding the period of investigation does not mean that an investigating authority's discretion in respect of period it selects as the basis for its injury analysis is unlimited. In this case, the period of investigation was July-December 2000 and a corresponding six months period in previous two years (1998 & 1999) was considered as inappropriate for injury analysis.
- hh) The Panel stressed that investigating authority is required to make an objective examination based on positive evidence. Panel observed that:
- "We consider that an objective examination of positive evidence of the effects of dumping on the state of the domestic industry which enables the authority to conclude that dumped imports are causing injury to the domestic industry involves an analysis of trends over time of the volume and price of imports and of the state of the domestic industry". (emphasis added)*
- ii) Thus, it is clear that the Designated Authority is required to make an objective assessment based on positive evidence which requires analysis of imports over a sustained period of time. Period of investigation of three months will not allow objective assessment based on positive evidence.
- jj) In *EC – Tube or Pipe Fittings*, the European Commission conducted its examination using a POI of one year from 1 April 1998 to 31 March 1999. The Brazilian Real was devalued by 42 percent towards the end of this period in January 1999. Brazil argued that the European Commission was obligated to compare normal values with export prices solely from the post-devaluation period.
- kk) Appellate Body observed that Brazil's approach would imply that determination will be based on the data of a very short period. Permitting such discretionary selection of data from a period of time within the POI would defeat the objectives underlying investigating authorities' reliance on a POI for the purposes of a dumping determination. Moreover, the Appellate Body observed that a POI provides data collected over a sustained period of time, which period can allow the investigating authority to make a dumping determination that is less likely to be subject to market fluctuations or other vagaries that may distort a proper evaluation. Appellate Body noted that the standardized reliance on a POI, although not fixed in duration by the Anti-Dumping Agreement, assures the investigating authority and exporters of a consistent and reasonable methodology for determining present dumping, which anti-dumping duties are intended to offset.
- ll) In *Mexico - Anti-Dumping Measures on Rice*, the Mexican investigating authority examined data for a period of investigation covering March to August 1999 for purposes of its dumping determination, and March to August 1997, 1998, and 1999 for purposes of its injury analysis. Appellate Body observed that period of investigation relating to the March to August period of 1997, 1998, and 1999, on the facts at issue, did not provide an accurate and unbiased picture of the state of the domestic industry and, thus, did not result in an objective examination as required by Article 3.1.
- mm) In the case of *Commissioner or Customs, Bangalore Vs. G.M. Exports*, the Hon'ble Supreme Court while determining the legality of anti-dumping duty imposed during the gap period between the end of provisional duty and the date of imposition of final duty, observed that:
- "In a situation where India is a signatory nation to an international treaty, and a statute is made in furtherance of such treaty, a purposive rather than a narrow literal construction of such statute is preferred. The interpretation of such statute should be construed on broad principles of general acceptance rather than earlier domestic precedents, being intended to carry out treaty obligations, and not to be inconsistent with them." (emphasis added)*
- nn) Thus, Hon'ble Supreme Court has specifically held that:

- a. *when domestic statute (i.e. Customs Tariff Act & Anti-dumping rules) is vague or ambiguous, treaty is the legitimate aid to the construction of the provisions of the statute; &*
 - b. *Interpretation should be construed on broad principles of general acceptance that is not inconsistent with treaty obligations.*
- oo) It is clear that if short period of 3 months is considered as POI, it will be inconsistent with the general principle requiring a lengthy POI of at-least 6 months and with the obligations incurred by India under the Anti-dumping Agreement. Hon'ble Supreme Court has specifically laid down the requirement that interpretation of Anti-dumping Rules is required to be carried out in a purposive manner that will not be inconsistent with treaty obligations.
- pp) Indian authority has consistently followed the recommendation of the Anti-dumping committee while determining the period of investigation. The final findings of the DGAD in past cases expressly relied on the recommendation of WTO Committee of Anti-dumping practice for fixation of the POI. There is no reason to deviate from this consistent practice of the Designated Authority.
- qq) Law and practice of WTO member countries like European Union (EU) & the United States (US) indicate that they have regularly followed the recommendation of Committee on Anti-dumping practices.
- rr) The EU Basic Anti-dumping Regulation provides that “for the purpose of representative finding, an investigation period shall be selected which, in the case of dumping shall, normally, cover a period of not less than six months immediately prior to the initiation of the proceeding.”
- ss) The US Anti-dumping Regulations provide that “In an antidumping investigation, the Secretary normally will examine merchandise sold during the four most recently completed fiscal quarters (or, in an investigation involving merchandise imported from a nonmarket economy country, the two most recently completed fiscal quarters) as of the month preceding the month in which the petition was filed or in which the Secretary self-initiated an investigation...”
- tt) Respondent requests the authority to consider the aforementioned submissions and clearly determine that the POI in this investigation is effectively of 3 months only and such short duration of the POI cannot be relied upon in an anti-dumping investigation for reaching any conclusion regarding dumping, injury and causal link in accordance with the structure and scheme of the Anti-dumping Rules in light of the obligations incurred by India under the Anti-dumping Agreement.
- uu) The domestic industry notes that the observations made by the Designated Authority in relation to dumping, injury and price effect and requests them to confirm the same and conclude accordingly. Domestic industry requests the Designated Authority to modify its final conclusion noted in paragraph 94 of the final findings.
- vv) Domestic industry does not provide for any reason to substantiate its claim in this regard. Respondents submit that the observations of the Authority noted by Domestic Industry are not final conclusions of the Designated Authority and therefore cannot replace the final conclusions of the Designated Authority noted by the domestic industry.
- ww) The domestic industry has not provided any legal or factual basis to substantiate that the POI can be of only three months in an anti-dumping investigation and that the Designated Authority should revise its final conclusion that causal link between dumped imports and injury cannot be conclusively established.
- xx) M/s Lakshmikumaran & Sridharan representing exporters stated that in the final findings, the Designated Authority determined that:

"Causal link between imports from Saudi Arabia and injury to the domestic industry is not conclusively established on the basis of 3 months of export period"
- yy) Hon'ble High Court has not observed that the aforementioned findings of the authority regarding causal link is incorrect. Hon'ble High Court has observed regarding the incorrectness of the conclusion of the Designated Authority in relation to dumping and injury. Hon'ble High Court has observed as below:

"Having recorded findings in support of the injury sustained by the domestic industry by dumping of like products by exporters/producers from Saudi Arabia, failed to carry through on the same note and

stragely did a volte-face, when it came to the final recommendation. This was on the strength of his misconceived notion that a three months span of dumping was insufficient for recording a finding. As we have already noted there is no such mandate in the Rules of 1995, the final findings dated 28.11.2017 are set aside and the matter is remitted to the designated authority for consideration afresh, taking into account the scheme and structure of the Rules of 1995 and the observations made hereinabove." (emphasis added)

- zz) Thus, Hon'ble High Court has noted that the Designated Authority has given a finding of material injury to the domestic industry and a finding of dumping by the exporters from Saudi Arabia but has not recommended duty because imports were occurring for a three months period. Hon'ble High Court has accordingly held that the Designated Authority could not have taken recourse to Rule 14(b) to terminate the investigation since Article 14(b) provides for insufficient evidence of dumping or injury as a ground to terminate the investigation.
- aaa) In accordance with Section 9B of the Customs Tariff Act & Article 3.5 of the Anti-dumping Agreement and Annexure II, para. 5 of Indian Anti-dumping Rules, it must be demonstrated that dumped imports are, through the effects of dumping causing injury to the domestic industry and that injury caused by any known factors other than the dumped imports at the same time is not attributed to the dumped imports. Thus, apart from existence of dumping and injury, the structure and scheme of the Rules require establishment of causal link. If there is no causal link between dumped imports and injury to the domestic industry, the Designated Authority cannot recommend imposition of anti-dumping duty.
- bbb) Respondents submits that determination of causal link between alleged dumped imports and injury to the domestic industry is not possible in the present case in accordance with provisions of Anti-dumping Agreement and Indian Anti-dumping Rules because (i) it is not possible to establish that injury caused to the domestic industry throughout the injury investigation period of 4 years and particularly during the POI is due to imports during three months of January to March 2016 (ii) the Designated Authority cannot examine existence of any known factors other than dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry in a span of 3 months period.
- ccc) Domestic industry had not presented any fact, information or argument against the decision of the Designated Authority regarding absence of causal link before the Hon'ble High Court and therefore there is no need for the Designated Authority to revise its final conclusion regarding causal link.
- ddd) The Hon'ble High Court has noted that the Designated Authority cannot refuse to conduct assessment of threat of material injury because it was not claimed by the domestic industry in its petition.
- eee) Respondents submit that assessment of threat of injury is not possible in the present case due to insufficient information regarding imports i.e. for 3 months period. Para (vii) of Annexure II of the Anti-dumping Rules require that threat of material injury shall be based on facts. Designated Authority shall consider:
 - i. Significant rate of increase in imports into India
 - ii. Sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter
 - iii. Whether imports are entering at prices that will have significant depressing or suppressing effect on domestic prices
- fff) No information is provided by the domestic industry regarding any of the above parameters. No assessment of threat of injury can be made in absence of conclusive data regarding the aforementioned parameters.
- ggg) M/s Lakshmikumaran & Sridharan representing exporters requests the Designated Authority to make afresh determination that there is no requirement to recommend imposition of anti-dumping duty on the subject imports as per the Anti-dumping rules due to short duration of the POI of 3 months and due to absence of causal link between dumped imports and injury.

c. Submissions by Saudi Kayan

13. The submissions are as follows:

- a) Saudi kayan along with Saudi Acrylic Acid Co (“SAAC”) and Sadara Chemical Co (“Sadara”) have setup a joint venture company, M/s Saudi Butanol Company (“SABUCO”), each with one third shareholding. Saudi kayan, Sadara, and SAAC have entered into a Tolling and Processing Agreement (hereinafter referred as “Agreement”) with SABUCO and it converts propylene into Normal Butanol and iso Butanol on tolling basis for three producers.
- b) It is clarified that Saudi Kayan has not exported the subject goods to India during the POI (1st April 2015 to 31st march 2016). Also, Saudi Kayan is not related to any of the exporters or producers in Saudi Arabia who have exported the subject goods to India during the POI.
- c) Considering the above facts and in terms of Rule 22 of the AD Rules, 1995, Saudi Kayan reserved its right to apply for a New Shipper Review in case the authority recommends for imposition of AD duty in the subject investigation.

d. Submissions by Royal Embassy of Saudi Arabia, New Delhi

- a) Saudi Butanol Company (“SABUCO”) is a toll processor of normal butanol and a joint venture set up by 3 companies, namely Sadara Chemical Company (“SADARA”), Saudi Kayan Petrochemical Company (“Saudi Kayan”) and Saudi Acid Acrylic Company (“SAAC”). SADARA, Saudi Kayan and SAAC supply the raw materials to SABUCO where it is transformed into normal butanol. SABUCO then returns the normal butanol to each company within the proportion of the raw materials supplied by each of them.
- b) The commercial production of normal butanol started in Saudi Arabia on 1 March 2016. Some exports of trial production took place from Saudi Arabia to India during January 2016 – March 2016. Accordingly, imports of normal butanol from Saudi Arabia came into India only during the last three months of the POI. Producers from Saudi Arabia i.e. SAAC and SADARA who had exported normal butanol to India during the POI duly cooperated with the Authority in the anti-dumping investigation.
- c) The Authority may kindly note that the primary objective of setting up production facility for normal butanol in Saudi Arabia was to consume normal butanol within Saudi Arabia for further manufacture of value added/downstream products like Butyl Glycol Ether (BGE) and Butyl Acrylate and then to export such value added/downstream products from Saudi Arabia. However, the plants for manufacturing such value added/downstream products were not fully operational during the POI of the anti-dumping investigation and therefore normal butanol was exported to different countries from Saudi Arabia including India during the POI.
- d) The plants for manufacturing value added products/ downstream products gradually became fully operational after the POI of the anti-dumping investigation. Consequently, normal butanol started getting more and more consumed by these plants and the exports of normal butanol from Saudi Arabia gradually started declining. This is clearly evidenced by the below mentioned import data, which shows that imports of normal butanol from Saudi Arabia into India declined considerably during the financial year 2017-18 and have completely stopped during the current financial year.

Import of Normal Butanol from Saudi Arabia

Particulars	Qty (MT) January 2016 - March 2016	Qty (MT) April 2016 – March 2017	Qty (MT) April 2017 – March 2018	Qty (MT) April 2018 – July 2018*
Imports into India from Kingdom of Saudi Arabia	8,791	27,494	18,013	Nil

Source: Export-Import Data Bank (Department of Commerce, India)

*** As Reported till July, 2018**

- e) It is submitted that Indian domestic industry is relying on a transitional time period when normal butanol was exported from Saudi Arabia to India to claim that there is a threat of material injury to the

domestic industry. The claim of the domestic industry is not based on complete facts and recent import statistics and is therefore devoid of merit.

e. Examination by the Authority

14. The Authority takes note of the Hon'ble high Court's directions and submissions made both during the earlier round of investigation and submissions made during the present remand case by Domestic Industry and various interested parties. The Authority has examined injury to the domestic industry in accordance with the Anti-dumping Rules and considering the submissions made by the interested parties.
15. The Authority notes that analysis has been done for the entire period of investigation including the last three months of POI. The analysis of imports from the subject country during POI and its impact on DI has been validated with the aspect of threat of injury as noted in the later paras in this finding keeping in view the directions of the Hon'ble High Court Order.
16. The Authority notes that for recommendation of Anti-Dumping Duty there are three pre-requisites i.e. dumping from the subject country, material injury being suffered by the domestic industry and causal link between injury and dumping. In the succeeding paragraphs, the Authority has analyzed the issue of injury and causal link. The Authority in view of the Hon'ble High Court's directions to examine the facets of injury as per rules has examined in addition to the material injury, the threat of material injury also. The retardation to establishment of industry does not seem relevant here with the DI being in existence and producing PUC since long.
17. The Authority also notes that AD Rules require the Authority to examine injury by examining both volume and price effect. A determination of injury involves an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic industry. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.
18. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure-II of Anti-dumping Rules states as under:
"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."
19. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments made by the parties in their submissions. The Authority had examined comments to the disclosure statement appropriately before issuing the present finding.

H. Assessment of Demand

20. The demand for subject goods has been determined by adding domestic sales of domestic like product with imports of subject goods from all countries. For the purpose of present injury analysis, the Authority has relied on the transaction-wise import data procured from DGCI&S. The Authority notes that demand of subject goods increased significantly over the injury period as depicted in the table below.

Demand	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Sales of Domestic Industry	MT	14,472	6,425	4,037	11,154

Imports – Subject Country	MT	0	0	0	8,791
Imports – Countries with AD Measures	MT	31,929	42,015	55,243	50,606
Imports – Other Countries	MT	205	750	0	0.32
Demand/consumption	MT	46,606	49,190	59,280	70,551
<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>106</i>	<i>127</i>	<i>151</i>

**POI: 2015-16*

I. Volume Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry

a) Import Volumes and Share of Subject Country

21. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The imports of the subject goods from Saudi Arabia started only from January 2016 in the POI. There were no imports of the subject goods from the subject country till December 2015.

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Imports -					
Subject Country	MT	0	0	0	8,791
Countries with AD Measures	MT	31,929	42,015	55,243	50,606
Other Countries	MT	205	750	-	0.32
Total Imports	MT	32,134	42,765	55,243	59,397
Demand	MT	46,606	49,190	59,280	70,551
Production	MT	14,409	5,484	4,203	11,080
Subject imports in relation to -					
Total Imports	%	No imports from Subject country			15%
Consumption	%				12%
Production	%				79%

J. Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

22. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

“With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.”

23. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

a) Price Undercutting

24. The Authority has compared landed price of imports from the subject country with net sales realization of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. This comparison shows that during the period of investigation, the subject goods originating in the subject country were imported into the Indian market at prices which were lower than the selling

prices of the domestic industry. The Authority notes that DI has stated that the Authority has not clarified Price underselling/ Price undercutting as being positive or negative. The Authority confirms that the data in table clearly implies a positive Price underselling and Price Undercutting.

Particulars	Unit	POI
Net Selling Price	Rs/Kg	***
Landed Price	Rs/Kg	39.43
Price undercutting	Rs/Kg	***
Price undercutting	%	25-35%
Price undercutting	Range (%)	25-35%

b) Price Underselling

25. The Authority notes the price underselling quantum of the domestic industry on account of dumped imports from the subject country. For this purpose, the NIP determined for the domestic industry has been compared with the landed price of imports from the subject country. However whether this price underselling is attributable unambiguously to the dumped imports requires a causal analysis which is stated in the later paras of this finding.

Particulars	Unit	POI
Non-injurious Price	Rs/Kg	***
Landed Price	Rs/Kg	39.43
Price underselling	Rs/Kg	***
Price underselling	%	55-75%
Price underselling	Range (%)	55-75%

c) Price Suppression/Depression

26. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	110	92	73
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	112	113	79

27. The Authority notes that the imports from Saudi Arabia came into India only during the POI. The imports started from January 2016. It is seen that the costs of sales of domestic industry reduced from 113 indexed points in 2014-15 to 79 indexed points during the POI. During the same period, selling price of the domestic industry reduced from 92 indexed points to 73 indexed points.

K. Economic parameters of the domestic industry

28. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like

product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

a) Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

29. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization is as follows:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Capacity	MT	22,500	22,500	22,500	22,500
Production	MT	14,409	5,484	4,203	11,080
Capacity Utilization	%	64.04%	24.37%	18.68%	49.24%
Domestic Sales	MT	14,472	6,425	4,037	11,154
Demand	MT	46,606	49,190	59,280	70,551

30. The Authority notes that the imports from Saudi Arabia came into India only during the POI. The imports started from January 2016. It is seen from the above table that the performance of the domestic industry had shown improvement in terms of production, sales volume and capacity utilization during the POI especially compared to two years prior to POI. The Authority notes that the capacity of the domestic industry remained same from base year to POI.

b) Profits, profitability, return on investment and cash profits

31. The cost of sales, selling price, profit/loss, cash profits and return on investment of the domestic industry has been analyzed as follows:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>112</i>	<i>113</i>	<i>79</i>
Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>110</i>	<i>92</i>	<i>73</i>
Profit/Loss (per unit)	Rs/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>-155</i>	<i>-732</i>	<i>-268</i>
Profit/loss total	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>-69</i>	<i>-204</i>	<i>-206</i>
Profit before interest	Rs. Lacs	***	***	***	***

<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>-58</i>	<i>-305</i>	<i>-280</i>
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>-82</i>	<i>-308</i>	<i>-290</i>
Return on Investments	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>-67</i>	<i>-360</i>	<i>-379</i>

32. The Authority notes that the imports from Saudi Arabia came into India only during the POI. The imports started from January 2016. It is seen from the above table that the domestic industry was suffering losses throughout the injury period and also in POI. The loss as well as cash loss was at its peak during the year 2014-15. The loss as well as cash loss continued in POI but reduced during the POI.

c) Market Share

33. The share of imports from Subject Country and the domestic industry is as below:

Market Share	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Domestic Industry	%	31%	13%	7%	16%
Subject country	%	0%	0%	0%	12%
Countries with AD Measures	%	69%	85%	93%	72%
Other Countries	%	0%	2%	0%	0%

34. It is seen from the above table that the market share of the domestic industry has improved in the POI. The Authority notes that imports from subject country came into India only during POI, and attained a market share of 12% during POI.

d) Employment, Productivity and Wages

35. The position with regard to employment, wages and productivity is as follows:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Employment	Nos.	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>98</i>	<i>97</i>	<i>93</i>
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Wages</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>112</i>	<i>107</i>
Productivity per day	MT per day	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>38</i>	<i>29</i>	<i>77</i>
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>39</i>	<i>30</i>	<i>82</i>

36. The level of employment has slightly declined over the injury period and POI. However, productivity per day and productivity per employee has slightly improved during the POI.

e) Inventories

37. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Average Inventory	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>50</i>	<i>11</i>	<i>16</i>

38. It is seen that the average inventory level of domestic industry has come down significantly during the POI which shows that the domestic industry is able to sell whatever it produces.

f) Growth

39. The data relating to growth of the domestic industry is shown in the following table:

Growth	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Production	MT	-	-62%	-23%	164%
Domestic Sales	MT	-	-56%	-37%	176%
Cost of sales	Rs./Kg	-	12%	1%	-30%
Selling price	Rs./Kg	-	10%	-16%	-21%
Loss	Rs./Kg	-	55%	373%	-63%
ROI	%	-	1%	-6%	0%
Market Share	%	-	-18%	-6%	9%

40. The Authority notes that the growth of the domestic industry in terms of the volume parameters such as, production, sales volume, market share etc. shows improvement in the POI. Information in terms of price parameters, such as profits, ROI shows that these parameters have remained negative throughout the injury investigation period and POI cost of sales declined during POI. However, imports from Saudi Arabia started only in January, 2016.

g) Ability to raise capital investments

41. The Authority notes that the imports from the subject country have happened only during the last three months of the POI. The domestic industry has been suffering losses throughout the injury investigation period and the POI.

h) Level of dumping & dumping margin

42. It is noted that imports from the subject country are entering the country at dumped prices and that the margin of dumping is above de-minimis limits.

i) Factors Affecting Domestic Prices

43. The authority notes that the domestic industry has been making losses throughout the injury period and POI. Prices of domestic industry remained suppressed during 2012-13, 2013-14, 2014-15 and 1st April 2015 to 31st December 2015 due to factors other than the imports from subject country. Even during the three months period when imports from subject country came into India, they only came at the prices prevailing at that point of time as set by other countries which were the dominant player in the Indian market.

L. Observations on Injury

44. Imports from the subject country had entered India during the last 3 months of POI. There were no imports from the subject country during the previous 3 years as well as first 9 months of POI. Prices of domestic industry remained suppressed throughout the injury investigation period and the POI. It is but obvious that the suppressed prices of the domestic industry during 2012-13, 2013-14, 2014-15 and 1st April 2015 to 31st December 2015 were due to factors other than the

imports from subject country.

45. Performance of the domestic industry has shown improvement during the POI with respect to sales, production, capacity utilization, market share and inventory.
46. The domestic industry has been suffering losses throughout the injury period and also in POI. The loss as well as cash loss was at its peak during the year 2014-15. The loss as well as cash loss reduced during the POI.

M. Evaluation of Causal Link

47. The Authority notes that the interested parties have argued that injury to the domestic industry is due to their dependence on one source of propylene, plant shutdown of its supplier i.e. HPCL due to fire accidents, dumping from other countries in the POI and other factors like inevitability to import due to huge demand supply gap. The Authority considered these aspects while undertaking evaluation of causal link between Dumping and consequential Injury.
48. It is noted that the imports from Saudi Arabia started in January, 2016 and the share of the imports from subject country constituted 12% of the total market share during POI. There were no imports during first nine months of the period of investigation i.e. April 2015 to December, 2015.
49. Annexure II para (v) of the AD Rules lays down as follows:

“It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs (ii) and (iv) above, causing injury to the domestic industry. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of relevant evidence before the designated authority. The designated authority shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry.”
50. The Authority notes that during the POI, the imports from Saudi Arabia i.e. Subject Country occurred during last 3 months i.e. January-March 2016. In the first 9 months of POI and the preceding 3 years, imports were mainly from Malaysia, European Union, USA, South Africa and Singapore which were subjected to Anti-dumping levy in April 2016 i.e. Post POI. The Authority notes that import price from all/some of these countries shows declining trend during April 2015 to March 2016 which is also manifested in the corresponding declining Net Sales Realization (NSR) of the Domestic Industry.
51. The Authority had reexamined appropriate segregation of various factors so as to evaluate the causal link aspect along with the threat of injury to DI from the imports from subject country. The Authority had reexamined whether other factors listed below under the Antidumping Rules could have contributed to injury to the domestic industry for examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry.

a) Imports from third countries

52. The Authority had examined the import data of the subject goods obtained from DGCI&S on transaction-wise basis in the original investigation. The Authority recalls that the imports from Saudi Arabia came into India only during the POI. The imports started from January 2016. It is also noted that the domestic industry was suffering losses during 2012-13, 2013-14, 2014-15 and during the period of investigation. In the first 9 months of POI and the preceding 3 years, imports were mainly from Malaysia, European Union, USA, South Africa and Singapore which were subjected to Anti-dumping levy in April 2016 i.e. Post POI. The Authority had reexamined price trend from the subject country and other countries for last 3 months of POI as under.

53. Data pertaining to last 3 Months of POI (January to March 2016) is as follows as also stated in original investigation:

S.N.	Particulars	Unit	Jan to Mar 16
1	Landed Price- Saudi Arabia	Rs/Kg	39.43
2	Landed Price- Countries attracting ANTI-DUMPING DUTY		
A	EU	Rs/Kg	59.19
B	Malaysia	Rs/Kg	37.83
C	South Africa	Rs/Kg	39.75
D	USA	Rs/Kg	38.38
E	Singapore	Rs/Kg	38.36
3	NSR	Rs/Kg	***
4	Price undercutting		
A	Saudi Arab	Rs/Kg	***
B	EU	Rs/Kg	***
D	Malaysia	Rs/Kg	***
E	South Africa	Rs/Kg	***
F	USA	Rs/Kg	***
G	Singapore	Rs/Kg	***

It is seen from the above table that imports from Malaysia, USA and Singapore came at prices lower than the prices of the subject country and the imports from South Africa came at almost the same price as that of the subject country during the period of January 2016 to March 2016. Therefore Malaysia, USA, South Africa and Singapore have continued to exert price pressure on the domestic industry and set the prices in the domestic market. Imports from Saudi Arabia came into India to bridge the demand-supply gap and came at prices prevailing at that point of time which were set by the major exporting countries like Malaysia, USA, South Africa and Singapore. The Authority during this remand investigation examined the behavior of imports from the subject country further under the threat of injury examination based on post POI import data as available.

b) Contraction in demand

54. The Authority notes that the demand for the subject goods has shown significant improvement during the injury period. Possible contraction in demand could not have caused injury to the domestic industry.

c) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

55. The Authority notes that there is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

d) Developments in technology

56. The Authority notes that the technology adopted and manufacturing process adopted by the domestic industry is quite comparable with that adopted by producers in the subject country.

e) Changes in pattern of consumption

57. The domestic industry is producing the subject goods that have been imported into India. Possible changes in the pattern of consumption are not a factor that could have caused claimed injury to the domestic industry.

f) Export performance

58. Petitioner has not exported the product under consideration. Thus, the claimed injury to the domestic industry is on account of domestic operations only.

g) Performance of the domestic industry with respect to other products

59. The performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

(h) Injury Margin

60. The Authority notes that Hon'ble High Court has not made any specific observations with regard to quantum of injury margin in its order dated 31st July, 2018. The Authority further notes that none of the interested parties have raised any issues with regard to the injury margin in the present proceedings. Therefore, the Authority is not revisiting its examination with respect to injury margin quantum in the present final finding.

N. Threat of Injury and Post POI Analysis

61. In view of the specific directions of Hon'ble High Court vide its order dated 31st July, 2018, the Authority analysed whether there could be a possibility of threat of material injury to domestic industry because of imports from the subject country.

62. With regard to the threat of injury, Annexure II para (vii) of the AD Rules lays down as follows:

“(vii) A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the dumping would cause injury must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the designated authority shall consider, inter alia, such factors as:

(a) a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;

(b) sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;

(c) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and

(d) inventories of the article being investigated.”

63. With regard to the threat of material injury, the Authority notes as follows:

(a) The Authority notes that imports from subject country entered only during last three months of the period of investigation i.e. from January, 2016 to March, 2016. In order to examine whether there has been a significant rate of increase of dumped imports into India from the subject country, the imports need to be compared with a base period. In the present scenario, there are no imports during 2012-13, 2013-14 and 2014-15, any import occurring during POI would therefore automatically show an increase. Therefore, imports during last 3 months of the period of investigation will not lead to conclusion. The Authority notes that in the petition of the domestic industry in the original investigation which culminated into final findings dated 28th November, 2017, the petitioner had claimed material injury and not threat of injury. In view of the Hon'ble High Court order dated 31st July, 2018, the Authority analysed the post POI period data to examine whether there is a threat of material injury to the domestic industry.

The Domestic Industry submitted that there are significant imports from subject country in January 2016 – March 2016 and the capacity of subject goods in Saudi Arabia is significant enough for imports during post POI. However, on the other hand, the submissions of Kingdom of Saudi Arabia states that the purpose of the setting up of 3,30,000 capacity is to be used captively to manufacture value added products like Butyl Glycol Ether (BGE), Butyl Acrylate etc. In order to examine above submissions, the Authority analysed post POI data. As per latest DGCI&S data, imports from subject country started only during last three months of the period of investigation i.e. from January, 2016. The trend of post POI imports is as under:

Particulars	Qty (MT) 2016 - 17	Qty (MT) 2017 - 18	Qty (MT) 2018 - 19
April – June	9372	5893	Nil
July – September	8147	5567	Nil
October – December	4447	5983	-
January – March	5529	570	-
Total	27495	18013	Nil

- (b) The Authority during exporter verification had noted that the commercial production of producer started only on 1st March, 2016. The Authority further notes that SABUCO is a joint venture company formed by Sadara Chemical Company, Saudi Acrylic Acid Co., and Saudi Kayan Petrochemical Co. each with one-third shareholding. SABUCO converts propylene into Normal Butanol and Iso Butanol on tolling basis for the three joint venture companies.
- (c) The Authority notes that the imports from Saudi Arabia came into India only during the POI. The imports started from January 2016 and the domestic industry was suffering losses throughout the injury period and also in POI. The loss as well as cash loss was at its peak during the year 2014-15. The losses reduced during the POI. The Authority further notes that the costs of sales of domestic industry reduced from 113 indexed points in 2014-15 to 79 indexed points during the POI. During the same period, selling price of the domestic industry reduced from 92 indexed points to 73 indexed points.
- (d) The Authority also notes that to establish the inventory available with the participating producers was indeed significant to establish threat of material injury would require a reasonable duration of imports from the subject country. The Authority notes that the capacity of subject goods of SABUCO is 3,30,000 MT with imports from the subject country during period of investigation being 2.6% of the total capacity, 8.33% in 2016-17 of the total capacity, 5.45% in 2017-18 of the total capacity and Nil imports in 2018-19 of the total capacity. The Authority therefore considered the post POI trend for conclusively establishing the threat of injury to domestic industry.

O. Post Disclosure Comments

(a) Submissions made by the domestic industry:

64. The domestic industry had made the following submissions:

- (i) The authority had earlier declined to recommend anti-dumping duty primarily on the following grounds.
- Commercial production of just one month also constrains determination of a representative and realistic normal value for operating producers/exporters.
 - Period of last 3 months of exports in the POI of subject goods from Saudi Arabia is not sufficient to evaluate injury to the domestic industry.
 - Causal Link between imports from Saudi Arabia and injury to the domestic industry is not conclusively established on the basis of 3 months of export period.
- (ii) The Hon'ble High Court however held as follows:

“On the above analysis, this Court finds that the designated authority, having recorded findings in support of the injury sustained by the domestic industry by dumping of like products by exporters/ producers from Saudi Arabia, failed to carry through on the same note and strangely did a volteface, when it came to the final recommendation.”

“....In the case on hand, as already noted supra, the findings recorded by the designated authority clearly demonstrated sufficient evidence of dumping within the short span of three months by the exporters/ producers from Saudi Arabia and also the injury caused to the domestic industry thereby. Therefore, the designated authority could not have taken recourse to this clause for justifying the termination of investigation. In fact, none of the clauses in Rule 14, which deals with termination of investigation, had application whereby the designated authority could have taken such a step.”

- (iii) The sole issue before the DA for not recommending ADD was the alleged short period of three months and allegedly absence of causal link for this reason. However, this very basis of the authority for declining to recommend ADD was held inappropriate/incorrect by High Court. Such being the case, it would not be appropriate now to once again consider the very same facts and decline the protection to the domestic industry. The disclosure statement has analysed injury to the domestic industry by repeatedly referring to three months period and ostensibly considering that the said period is insufficient to hold injury or causal link. The disclosure statement ignores the order of High Court and tantamount to once again considering the very same basis which was held to be incorrect by the High Court.
- (iv) The disclosure statement is indicative of a consideration by the DA that since subject dumped imports were present only in three months of the POI out of twelve months POI and further since the domestic industry was suffering injury even in nine months prior to commencement of imports from Saudi Arabia, it implies that there are “other factors” which are causing injury to the domestic industry. The petitioner requests the Designated Authority to kindly disclose such essential fact to the petitioner in case the Designated Authority has found that there is some other factor which has caused injury to the domestic industry.
- (v) The Designated Authority may kindly follow the Hon’ble High Court judgment wherein, it was categorically held that 3 months imports in the POI are sufficient to determine dumping and consequent injury to domestic industry. The Authority has determined positive and, in fact, significant dumping margin and injury margin in respect of exports made by the exporters from Saudi Arabia. The Hon’ble High Court has also observed in this regard that the findings recorded by the designated authority clearly demonstrates sufficient evidence of dumping and the domestic industry suffered injury. There is no legal requirement under the law that the dumped imports should exist in the entire period of investigation.
- (vi) Rule 16 dealing with disclosure of essential facts under consideration implies that the Designated Authority will disclose “all essential facts under consideration” of the authority which shall form the basis of its determination. The authority is required to make determination based on only those facts which have been disclosed in the final findings. Considering the Rule 16, therefore, the petitioner requests the authority to kindly consider the facts as disclosed in the disclosure statement as the upper limit of essential facts under consideration. Further, in case the Designated Authority has found any other essential fact, the petitioner requests its disclosure to the domestic industry.
- (vii) The Authority is requested to kindly refer to the final finding earlier issued in the case. It is evident that without any change in facts, the Authority has done injury analysis in the current disclosure differently from the way it had conducted in the original finding. The analysis with regard to import volumes, share of subject country, price undercutting, price underselling and post POI analysis is different irrespective of no change in facts and circumstances of the case.
- (viii) With regard to conclusion on injury in the previous Final finding, the Authority in the disclosure statement has taken contrary view in para 47 to 49 of the disclosure statement. The segregated injury analysis in the previous finding in para 77 to 79 done by the Authority is completely missing in the present disclosure statement. The Authority without any reason deleted the same in the present disclosure statement. It is requested that another disclosure statement be issued, incorporating the same analysis. It is relevant to note that even Hon’ble High Court observed the same in the judgment.

- (ix) The Authority has very carefully analyzed and highlighted that the prices of imports from Saudi Arabia was determined on the basis of prices of the subject good from Malaysia, USA, South Africa and Singapore. The Authority for the purpose of current investigation has taken such an discriminatory approach towards treatment of dumped imports when the designated authority found that several other countries who were exporting the very same product to India had been subjected to anti-dumping measures, allowing exporters/producers from Saudi Arabia to do so without subjecting them to the same anti-dumping measures, even though their activities within a short span of three months clearly indicated their invasive capturing of the domestic market and the consequential injury to domestic industry.
- (x) Under the Anti-dumping Rules, there is no mandate to pick and choose the country among subject countries for imposition of anti-dumping duty. Rule 19 of anti-dumping Rules provides that imposition of duty shall be on non-discriminatory basis.
- (xi) Whereas if we look into the practice of the Designated Authority; the presence of dumped imports from other countries have never been treated as an excuse for another country to dump a good in India and the same being appreciated and acknowledged by the Authority. Reference in many previous investigations viz. PVC suspension from EU and Mexico, Sunset Review Investigation on Pentaerythritol from China PR and Anti-Dumping investigation on Hexamine from China PR and UAE, the Authority had recommended duty on imports from dumped good from one set of subject countries while there were significant dumped imports from another set of subject countries who were attracting Anti-Dumping Duty.
- (xii) It is submitted that never before in the history has dumped imports from other subject countries attracting Anti-Dumping Duty were considered as a cause of injury while examining causal link from the new sources.
- (xiii) Para (v) of the annexure II refers to injury to the domestic industry due to other factors. While referring to such other factors, the rule provides that the authority shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. The rule further identifies certain factors which could be considered relevant and would be existing at the same time and causing injury to the domestic industry. The disclosure statement repeatedly refers to the possible “other factors” without identifying any, except dumped import from other sources. The petitioner is therefore making these submissions on the basis of its understanding of the disclosure statement that none of the other listed known factors have caused injury to the domestic industry and barring imports from other countries, the Designated Authority has not found any other factor which could be responsible for causing injury to the domestic industry.
- (xiv) It is also relevant to consider Rule 16 and Para (v), Annexure II. Reference to other factors listed under Annexure II when read with Rule 16 makes it very evident that the other factors referred in Annexure II are in the nature of facts. Since this is in the nature of facts, the authority is required to disclose that whether injury to the domestic industry has been caused by any other such factor.
- (xv) A question that may arise for consideration in the present case is whether dumped import from other sources can constitute other factor causing injury to the domestic industry. Following are relevant in this regard.
- The final findings issued by the authority in respect of imports from Malaysia, Singapore, South Africa and USA concluded as follows:
- i. The domestic industry has suffered material injury and the same is established on price undercutting and underselling without considering decline in volume parameters such as production, sales, capacity utilization, and inventories.

- ii. The performance of the domestic industry has deteriorated due to dumped imports from subject country.
 - iii. The causal link between dumped imports and injury can be established from the facts that imports are significant in terms of absolute terms and relative terms.
 - iv. The imports of the product under consideration are causing price suppression and are preventing the domestic industry from raising the prices. Consequently, profits, cash flow and ROI has declined.
 - v. The subject imports are resulting in price underselling in the market.
 - vi. The growth of the domestic industry became negative in terms of a number of price and volume related economic parameters. While negative growth in volume parameters could be due production suspension, negative growth in the price parameters is primarily due to dumping of the product in the country.
- (xvi) It is thus evident that the imports from other country were found as dumped imports and were found to have caused injury to the domestic industry to such an extent that the authority considered it appropriate to recommend ADD on these imports. Since these imports from other countries are dumped imports, it could be considered that the domestic industry was suffering injury from dumped imports from EU, Malaysia, Singapore, South Africa and USA during the relevant period of the present case.
- (xvii) The scope of Para (v) of Annexure II under other factors does not however include dumped imports from other sources. The listing of factors such as the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry clearly shows the rules have distinguished and differentiated between dumped import as one factor and other factors such as the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry as other factors. Thus, the authority is not required to segregate injury caused to the domestic industry due to other dumped imports.
- (xviii) Following WTO panel report is relevant in this regard.

i. WTO Panel Report in the matter of Malleable Cast Iron- Tube or pipe fittings from Brazil., wherein the Panel noted as follows

In its determination, the European Communities identified certain factors, other than dumped imports, that were potentially causing injury to the domestic industry including imports from third countries not subject the investigation; decline in consumption and substitution. With respect to each of these factors individually, the European Communities conducted a separate examination and found either that it "is not such as to have contributed in any significant way to the material injury suffered by the Community industry"(decline in consumption);³¹³ that it made "no significant contribution" (export performance) or that "no significant influence" could have resulted (own imports of the product concerned),³¹⁴ that it cannot have significantly contributed to injury (substitution),³¹⁵ or (in the case of imports from the countries not subject to the investigation) "even if imports from other third countries may have contributed to the material injury suffered by the Community industry, it is hereby confirmed that they are not such to have broken the causal link between the dumping and the injury found".³¹⁶ The European Communities concluded that any other factors that may have contributed to the injury to the domestic industry were "not such as to have broken the casual link" between dumped imports and injury.³

7.368 These aspects of the EC determination indicate to us that the European Communities analysed individually the causal factors concerned and identified the individual effects of each of these causal factors. With respect to each of the factors, the European Communities concluded that the extent of the contribution to injury was not significant, or, in one case,

extrapolated that, even if the effect were significant, it would not be such as to “break the causal link” between dumped imports and material injury. The European Communities’ overall conclusion was that none of these factors had an effect that was such to have broken the causal link between dumped imports and material injury.

- (xix) It is evident from the above that dumped imports from other sources in any case cannot be an “other factor” of injury for causal link analysis. The petitioner also brings kind attention to past determinations made by the authority in the CDR, DVDR and PVC suspension case in this regard.
- (xx) The authority has considered import up to the period, September, 2018 for the purpose of threat analysis, which implies consideration of 30 months data after the POI. Petitioner submits that firstly, there is no mandate under the Rules to consider post POI data for the purpose of threat of injury analysis. However, in practice, the Authority has never considered data beyond 6 months for the purpose of post POI analysis. In the context of sunset review investigations and wherever authority has not found continued dumping and injury in the POI, the authority has considered post POI data. However, the authority has invariably considered only 6 months data for post POI analysis. In fact, in the matter of mid-term review concerning Phenol and Acetone, the DI heavily contended that the market situation was extremely temporary and the authority should consider last one year data after the post POI. The authority however declined to consider post POI beyond 6 months stating that post POI data cannot be considered for more than 6 months period. Such being the case, consideration of import data for the period up to September, 2018 is inappropriate and unjustified. The petitioner requests the authority to kindly consider imports only up to September 2016 as the post POI for the present purpose. Import data for the period after October 2016 cannot be adopted for the purpose of threat analysis.
- (xxi) Keeping the analysis of post POI data open-ended brings speculation and unsurety in the data to be analyzed. It has been a constant practice of the Designated Authority to have taken a period of 6 months for the purpose of the post POI analysis. The same can be concluded from the list of cases detailed below:
- a. Anti-Dumping Investigations on imports of ‘Front Axle Beam and Steering Knuckles meant for heavy and medium commercial vehicles’ originating in or exported from China PR
 - b. Anti-dumping investigation on imports of ‘Viscose Staple Fibre excluding Bamboo fibre’ originating in or exported from China PR and Indonesia
 - c. Sunset Review (SSR) investigation of Anti-Dumping duty on imports of ‘Polypropylene originating in or exported from Singapore.
 - d. Anti-dumping investigation (Sunset Review) concerning imports of “Melamine” originating in or exported from European Union, Iran, Indonesia and Japan.
 - e. Sunset Review of Anti-dumping investigation concerning imports of Vitamin-A Palmitate originating in or exported from China PR and Switzerland.
 - f. Sunset Review (SSR) anti-dumping investigation concerning imports of ‘Digital Versatile Discs-Recordable of all kinds (DVD-R)’ originating in or exported from Vietnam and Thailand.
 - g. Sunset Review (SSR) Anti-dumping investigation concerning imports of ‘Front Axle Beam’ and ‘Steering Knuckles’ meant for heavy and medium commercial vehicles originating in or exported from China PR.
- (xxii) The abovementioned cases clearly shows that whether it is original investigation or sunset review investigations, the Authority has constantly referred to period of 6 months only as the post POI. However the current disclosure issued has kept the post POI period open –ended.
- (xxiii) Even otherwise with regard to threat of injury, petitioner submits that in the disclosure statement, Authority merely referred the parameters but did not examined all the mandatory parameters, petitioner submits that the parameters mentioned in the Annexure-II, paragraph- (vii) are mandatory in nature. We request the authority to examine the same to conclude on threat of material injury.
- (xxiv) The Authority in the disclosure statement has stated under various paragraphs no. 56, 46 that the prices of imports from Saudi Arabia was guided by the prices offered by Malaysia, USA, South

Africa and Singapore as they were the dominant players in the market setting the prices. Petitioner submits as follows in this regard:

- a. Never before, the Authority has considered whether import price from one dumped sources were influenced by dumped imports from other sources.
- b. There is no provision under the law which requires the Authority to consider this analysis
- c. There is no provision under the law which states that the Designated Authority shall exonerate those dumped sources from payment of ADD where the dumping was triggered due to dumped from other countries.
- d. It is entirely immaterial whether Saudi producer followed the prices of other dumped sources.
- e. Assuming that Saudi producer followed the prices of other dumped sources, the same per se establishes that the Saudi producer joined injury to the domestic industry caused by the NBA-1 countries by resorting to dumping.
- f. this fact itself cannot be a justification for the exporters in Saudi to export the subject goods at dumped prices. Dumping a product in a market should be condemned if it causes injury to the domestic industry.
- g. Imports from EU (and even other countries) in NBA-1 case were at a higher prices. But, the Designated Authority did not conclude similar to what is proposed in the present case.
- h. Even in NBA-1 case, it is not that 4 countries were at the same time setting the prices. It is obvious that some country was setting the prices and others were following. This is true for any case where more than one source is involved. Petitioner fails to understand and appreciate what is special in the present case.

(xxv) The Authority in para 66(a) of the disclosure statement brings a new fact which was not considered by the Authority while concluding the Final findings. Petitioner submits that this cannot be considered now. The Saudi producer or Govt. can give an undertaking that the producer in Saudi shall not export the product to India, as its production is meant for captive consumption. The Designated Authority can consider suspension of investigations in that situation. Petitioner shall have no reservation or objection in this regard.

(b) Submissions made by the exporters, importers and Other Interested Parties/ other Parties

65. M/s LKS representing SABUCO, SADARA, SAAC, PETROCHEM, TASNEE MARKETING and TOYOTA submitted the following:

- (i) WTO Committee on Anti-dumping Practices provides that period of data collection in an anti-dumping investigation should be of at least six months. In the present case, the POI was effectively of three months only as the imports happened from Saudi Arabia only during the last three months of POI i.e. January, 2016 to March, 2016. On this ground itself, the investigation should be terminated.
- (ii) While examining the injury parameters, the Authority has observed positive improvements in almost all the volume parameters such as production, sales volume, capacity utilization, market share and inventory of the Domestic Industry during the period of investigation. On volume parameters, the Domestic Industry is not facing any injury during POI. We request the Authority to kindly confirm this fact in the final findings.
- (iii) The Authority while analyzing price suppression/depression has noted that the imports from Saudi Arabia took place during the last three months of the POI i.e. January, 2016 to March, 2016. The costs of sales of domestic industry reduced from 113 indexed points in 2014-15 to 79 indexed points during the POI (decline of 34 indexed points) whereas the selling price of the domestic industry reduced from 92 indexed points in 2014-15 to 73 indexed points in POI (decline of 19 indexed points). This clearly shows that there is no price suppression suffered by the domestic industry during the POI. Therefore, imports from Saudi Arabia cannot be said to be causing any price suppression as imports

from Saudi Arabia took place only in last three months of the POI. We request the Authority to kindly confirm this fact in the final findings.

- (iv) With regard to price parameters analysed in para 34 and 35 of the disclosure statement, the Designated Authority has noted that the imports from Saudi Arabia came into India only during the last 3 months of POI. However, the domestic industry was suffering losses for the entire period of investigation including injury investigation period. The Authority has observed that losses and cash losses were at their peak during 2014-15 and reduced in POI. This clearly shows that the imports from Saudi Arabia were not responsible for the losses suffered by the Domestic Industry during the entire injury investigation period and the POI and there is complete absence of any causal link between the imports of subject goods from Saudi Arabia and the losses suffered by the domestic industry. We request the Authority to kindly confirm this fact in the final findings.
- (v) The Authority in para 53 – 55 of the disclosure statement has noted that the imports from Saudi Arabia came into India only during the last 3 months of POI. However, the Domestic Industry was suffering losses due to imports from countries other than Saudi Arabia during the entire injury investigation period including the POI. It is submitted that imports from Saudi Arabia during last 3 months of POI entered into the Indian market at the prices prevailing in India at that point of time and fixed by other countries who were the dominant players in the Indian market. It is also submitted that imports from some of the other countries came at prices even lower than the prices of Saudi Arabia during the last 3 months of the POI. Therefore, there is neither any causal link nor any threat of material injury to the domestic industry due to the imports of subject goods from Saudi Arabia. We request the Authority to kindly confirm the same in the final findings.
- (vi) The observations of the Authority in para 66 of the disclosure statement clearly demonstrate that there is no threat of material injury to the domestic industry due to the imports of subject goods from Saudi Arabia as the imports from Saudi Arabia have significantly declined in 2017 – 18 and have completely stopped during 2018-19. We request the Authority kindly confirm these observations in the final findings.
- (vii) No exports of Normal Butanol have been made by SAAC and SADARA to either India or to any other country in 2018-19. The primary objective of entering into the joint venture agreement for SAAC and SADARA was to get Normal Butanol which would be used for captive consumption either by them or by their related companies to manufacture value added products like Butyl Acrylate and Butyl Glycol Ether (BGE).
- (viii) Mere creation of additional capacity in subject country is not sufficient for presuming that there may be diversion of goods to the Indian market or would lead to dumping of the subject goods into India. In this regard, the Respondents also rely on Indian Spinners Association v. Designated Authority wherein the Hon'ble CESTAT found that mere existence of surplus capacities would not be indicative of an imminent threat of injury.
- (ix) Respondents submit that the Domestic Industry is trying to take undue advantage of a small window of three months of imports from Saudi Arabia and trying to get Anti-Dumping Duty imposed on imports of subject goods from Saudi Arabia. The respondents are making this statement because the facts of the case clearly demonstrate that imports from Saudi Arabia took place during the last three months of the POI i.e. January, 2016 to March, 2016 and have significantly declined in 2017-18 and become nil in 2018-19. The performance of the Domestic Industry has gradually improved since 2015-16 as outlined in its Annual Reports of respective years is tabulated below:

Particulars	2015-16 (Rs. in lakhs)	2016-17 (Rs. in lakhs)	2017-18 (Rs. in lakhs)
Revenue from operations	37580.83	37043.04	53275.25
Profit/(loss) before tax	(2630.43)	(1090.47)	4725.98

As can be seen from the above table, the performance of the Domestic Industry has drastically improved since the end of the POI. The Domestic Industry incurred losses of Rs. 2630.43 Lakhs in 2015-16 which

reduced to Rs. 1090.47 Lakhs in 2016-17 and turned into good profits of Rs. 4725.98 Lakhs during 2017-18. We, therefore, request the Authority to terminate the present investigation and not to fall into the trap of the Domestic Industry whereby they want to get Anti-Dumping Duty imposed for five years based on imports during a small window of three months from Saudi Arabia wherein they were suffering losses due to imports from other countries and not due to imports from Saudi Arabia.

P. Examination by the Authority

66. The Authority notes the submissions by various parties some of which are repetitive in nature and were addressed in the disclosure statement. To the extent fresh arguments have been made and considered relevant, the specific issues have been dealt at appropriate places in the findings above. The Authority has examined submissions of interested parties herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere.

- (i) The Authority notes various submissions of interested parties and holds that all relevant essential facts under consideration have been disclosed.
- (ii) The domestic industry claims that the Authority has ignored the decision of the Hon'ble High Court because the sole issue before the Authority in this investigation is the absence of causal link due to short period of 3 months of imports from Saudi Arabia. Domestic industry also claims that the present disclosure statement should not contain additional facts and analysis that were not present in the previous final findings. The Authority notes that the Hon'ble High Court directed the Authority to issue afresh determination based on the scheme and structure of the Anti-dumping Rules and also directed to analyze threat of material injury which was not examined in the previous findings. The Hon'ble High Court has not directed the Authority to recommend imposition of the anti-dumping duty without considering relevant facts under the scheme and structure of the Anti-dumping Rules. The Authority notes that the DI has submitted that the segregated injury analysis of 9 months and next 3 months of POI has been deleted in present disclosure by the Authority. The Authority in this regard recalls that in a segregated analysis in original finding, the Authority had confirmed about continued injury due to price depression to DI. However the Authority had attempted to conclusively establish a causal link between imports from Saudi Arabia and injury to DI which could not be established even on the basis of a segregated analysis. The Authority in this regard recalls Para 93(ii) of the original final finding dated 28th November, 2017. Therefore in the present remand investigation, when the post POI data is available, the authority as per the directions of the Hon'ble High Court has analyzed the same over a period of 2016-17, 2017-18, 2018-19 (till August, 2018) for the purpose of threat of material injury to DI as per the directions of the Hon'ble High Court. The Authority therefore holds that the disclosure statement contains essential facts which are in accordance with the scheme and structure of the AD Rules and after strictly complying with the specific directions of the Hon'ble High Court. This requires examining the trend of imports from Saudi Arabia in period past POI termed as Post POI which has been dealt in Para below.
- (iii) With regard to post POI data, the domestic industry has contended that the post POI data should be restricted to 6 months while analyzing the threat of material injury considering the consistent practice of the Designated Authority for the purpose of post POI analysis. The Authority notes that the submissions of the domestic industry are not tenable on account of the following reasons. Firstly, no specific period is provided in the Act and AD Rules for the purposes of examination of threat of material injury. In a normal course of anti-dumping investigation, the Authority generally takes the recent post POI data which is available for not more than 6 to 9 months period. However, in the present facts of the case, the Authority has before it DGCIS import data as latest as August, 2018 which is not the case in other anti-dumping investigations. For the matter of convenience and availability of data with the Authority, the Authority generally takes most recent period which is usually 6 months post POI period. However, in the present investigation, data of more than 6 months available with the Authority cannot be ignored which allows the Authority to arrive at a fair conclusion. The Authority notes that the Hon'ble High Court's direction do not constrains the authority to examine threat of injury limited only to 6 months Post POI period till 30th September, 2016. Examining old data at this stage for threat of injury examination ignoring the recently available data will be unjust and unfair as only recent data would capture the true reality which no interested party should object keeping in view the circumstances of the case and also the directions

of the Hon'ble High Court to strictly examine the case in accordance with the scheme and structure of the Rules of 1995. The Authority reiterates that obligation on it is to make objective assessment based on all facts available.

- (iv) With regard to the submissions regarding analyzing dumped imports from other sources cannot be another factor of injury for causal link analysis, the Authority notes that in the present investigation, the facts are unique in nature as the imports from the subject country are nil during the injury investigation period and imports from Saudi Arabia have occurred only in the last three months of the period of investigation. There is an obligation on the Authority to examine whether the imports from the subject country can be primarily/mainly responsible for this penurious situation or other factors are responsible for causing injury to domestic industry. If other factors are primarily/mainly responsible for causing injury to the domestic industry then imports from Saudi Arabia cannot be held responsible for causing injury to the domestic industry. During period of investigation, the Authority has observed positive improvements in almost all the volume parameters such as production, sales volume, capacity utilization, market share and inventory of the Domestic Industry. The price parameters were negative during injury investigation period and the period of investigation. The Authority notes that improvement in certain volume and price parameters happened in POI as compared to previous year/ previous 2 years. However since imports from Saudi Arabia did not occur during years prior to POI, and with performance on certain parameters showing improvement in POI, establishing nexus between imports from Saudi Arabia in POI and domestic industry's performance required close examination of import prices of other countries as well. Therefore, the Authority has examined other factors which are causing injury to the domestic industry. The Authority further notes that the Domestic Industry was suffering injury during injury investigation period due to dumped imports from EU, Malaysia, Singapore, South Africa and the USA and during period of investigation the import price from Saudi Arabia in last three months of POI was higher than Malaysia, Singapore and USA. All these factors led the Authority to reiterate that imports from Saudi Arabia cannot be primarily/mainly held responsible for the injury on the price parameters suffered by the domestic industry.
- (v) With regard to discriminatory approach between treatment of dumped imports from other countries (on whom AD duty has been imposed) and allowing exporters/producers from Saudi Arabia to do exports without imposition of anti-dumping duty, the Authority holds that there is no discriminatory approach that has been adopted in the present investigation. The Authority notes that the contention of domestic industry is not correct as the DI is relying on Rule 19 which clearly states that there should be no discrimination between various producers/exporters in a country while imposing duties. In fact, contrary to the claim of the domestic industry, the Authority notes the Appellate Body Report in *European Communities – Definitive Anti-dumping Measures on certain Iron or Steel Fasteners from China* which interpreted Article 9.2 as under:

“338. We note that Article 9.2 of the Anti-Dumping Agreement requires that anti-dumping duties be collected on a non-discriminatory basis from "all sources" found to be dumped and causing injury, except from "those sources" from which price undertakings have been accepted. We agree with the Panel that the term "sources", which appears twice in the first sentence of Article 9.2, has the same meaning and refers to individual exporters or producers and not to the country as a whole. This is indicated by the fact that price undertakings mentioned in the first sentence of Article 9.2 are accepted, according to Article 8 of the Anti-Dumping Agreement, from individual exporters and not from countries. Therefore, the requirement under Article 9.2 that anti-dumping duties be collected in appropriate amounts in each case and from all sources relates to the individual exporters or producers subject to the investigation”.

The Appellate Body interpreted that the non-discriminatory basis from all sources under Article 9.2 of Anti-Dumping Agreement refers to individual exporters or producers and not to the country as a whole. Therefore, the contention of the domestic industry is not correct that the Authority has taken a discriminatory approach towards treatment of dumped imports from other countries and allowing exporters/producers from Saudi Arabia to do exports without imposition of anti-dumping duty.
- (vi) Domestic industry submits that para (v) of Annexure II refers to injury to the domestic industry due to other factors and the Authority shall not examine any other known factors not specifically listed in para (v). The Authority notes that the factors mentioned in Para (v) of Annexure II are

indicative. The Authority while determining other factors has examined the imports from countries other than subject country which caused injury to the Domestic Industry as stated above. During these three months period when imports from subject country came into India, they came only at the prices prevailing at that point of time as set by other countries who were the major players in the Indian market. The Authority's view held in Para 93(ii) of the Original final finding is recalled.

- (vii) Domestic Industry has cited past investigations wherein anti-dumping duty on subject goods has been recommended by the Authority on one set of countries and later on the other set of countries. The Authority recommends levy of duty on merits after analyzing dumping, injury and establishing causal link between dumping and injury. The facts and circumstances of the present investigation are quite different and the previous investigations cited by the domestic industry cannot be considered as a settled proposition of law especially when facts and circumstances in any investigation are in a distinct setting of price behaviors. The analysis done by the Authority is based on the facts and circumstances prevailing in that particular investigation. Therefore, the findings and outcome of those investigations can at best be indicative for similar situations. The Authority therefore reiterates that analysis of a particular investigation is totally different from other investigations done in the past and it is done on a case to case basis based on the facts and circumstances of a particular investigation as each case has its own unique facts.
- (viii) With regard to contention of domestic industry for taking undertaking from Government of Saudi Arabia and producers/exporters from Saudi Arabia to produce subject goods for captive consumption and not to export to India, the Authority notes that in an Anti-Dumping investigation it has to examine dumping, injury and to establish causal link between injury and dumping. However, it is not permissible under the law to take undertaking from the Government of Saudi Arabia and producers/exporters from Saudi Arabia to produce subject goods for captive consumption and not to export to India. Therefore, the Authority holds that there is no provision under the Act and rules which enables the Authority to ask for such an undertaking from the Government of the subject country. In response to the disclosure, the Authority notes that DI has stated that Producers/exporters of Saudi Arabia or Saudi Government may give an under taking for non-exporting to India but have not mentioned any adverse impact of non-levy of AD duty on imports from Saudi Arabia on their economic performance post recommendation by the Authority. The Authority further notes from the Domestic Industry's audited financial reports available on its website and also submitted by the exporter that domestic industry's overall profitability improved despite non availability of AD measure on imports from Saudi Arabia. The Authority further notes that AD measure on 5 other countries i.e. EU, Malaysia, Singapore, South Africa and USA came in force in April, 2016 and it therefore appears that arresting the unfair imports from these countries improved the profitability, a consideration which the authority had acknowledged in para 93(ii) of the Original finding dated 28th November, 2017 which gets vindicated now.
- (ix) The Authority holds that though imports from Saudi Arabia in 3 months of POI were significant, the Authority was bound as per the scheme and structure of the AD rules of 1995 to evaluate all essential parameters i.e. extent of dumping, extent of injury and most important the causal linkage between the dumping and injury to consider recommending levy of AD on dumped (unfair) imports under rule 17 of AD rules. Despite invasive capturing by Saudi Arabia, the non-conclusive establishment of causal link restrained the Authority to recommend a measure as Causal Link is essentially a fundamental condition to recommend an AD levy. The Authority recognizes that AD rules need to be applied as per the scheme and mandate to protect the domestic industry from unfair trade practices. However, in event of non-fulfilment of any essential condition mandated under the rules, the Authority cannot traverse beyond the boundary of the mandate of AD rules to recommend an AD measure to protect the domestic industry. An AD measure as per AD rules is applied to the extent of injury or dumping whichever is lower so as to address the concerns of the user domestic industry also besides the injured domestic manufacturer. However in a situation like high quantity of imports where all conditions under AD rules are not met, an injured domestic manufacture can seek redressal under any other appropriate trade remedial measures.
- (x) The Authority also holds that it needs to ensure compliance with the Hon'ble High Court's order wherein directions have been given to also examine threat of injury which the Authority did not

consider earlier as the DI had not filed the application contending threat of material injury due to Imports from Saudi Arabia.

- (xi) The Authority notes that the Hon'ble High Court has held that the Authority could not have taken recourse to terminate the investigation under Rule 14 of the AD Rules. The Authority after undertaking the detailed investigation issued the final findings under Rule 17 of the AD Rules, wherein a vital and non-negotiable parameter under Rule 17 (iii) reads as "to a causal link, where applicable, between the dumped imports and injury;" Therefore, failure to meet this condition could not have culminated into a positive recommendation of levy of an AD duty. Under such circumstances, the recommendation was to terminate the investigation which the Authority recommended under Rule 14 (b) which reads as "it is satisfied in the course of an investigation, that there is not sufficient evidence of dumping or, where applicable, injury to justify the continuation of the investigation". The applicable injury mentioned under Rule 14 (b) cannot be read delinked from existence of a causal link with dumping which is an integral part of recommending an AD measure under Rule 17. The Authority with this view terminated the investigation under Rule 14 (b). Noting that this conclusion under Rule 14 (b) created ambiguity of relevant provision of Authority's determination, the Authority hereby confirms that the termination of the investigation is under Rule 17 read with Rule 14 (b) of AD Rules.
- (xii) The Authority notes that imports from Saudi Arabia during 3 months of POI were 8791 MT (annualized about 35000 MT). The post POI trend of imports from Saudi Arabia are noted as 27495 MT imports in 2016-17, 18013 MT imports in 2017-18 and 'Nil' from April 18 to August 18. The imports declined by almost 22% in 2016-17 and by 34% in 2017-18 and becoming Nil in the year 2018-19 (till August, 2018). With the declining trend reaching to a nil level has been without any measure imposed on imports from Saudi Arabia. The above trend therefore does not establish any threat of material injury to the Domestic Industry and in fact vindicates the recommendation of the Authority in the original findings that the imports from Saudi Arabia was insufficient to establish a conclusive causal link between dumping and consequential injury being suffered by the Domestic Industry.
- (xiii) The Authority holds that though imports from Saudi Arabia in 3 months of POI were significant, the Authority was bound as per the scheme and structure of the AD rules of 1995 to evaluate all essential parameters i.e. extent of dumping, extent of injury and most important the causal linkage between the dumping and injury to consider recommending levy of AD on dumped (unfair) imports under rule 17 of AD rules. Despite invasive capturing by Saudi Arabia, the non-conclusive establishment of causal link restrained the Authority to recommend a measure as Causal Link is essentially a fundamental condition to recommend an AD levy.
- (xiv) The Authority recognizes that AD rules need to be applied as per the scheme and mandate to protect the domestic industry from unfair trade practices. However, in event of non-fulfilment of any essential condition mandated under the rules, the Authority cannot traverse beyond the boundary of the mandate of AD rules to recommend an AD measure to protect the domestic industry. An AD measure as per AD rules is applied to the extent of injury or dumping whichever is lower to address the concerns of the user domestic industry besides the injured domestic manufacturer. However in a situation like high quantity of imports where all conditions under AD rules are not met, an injured domestic manufacture can seek redressal under other appropriate trade remedial measures.

Q. Conclusions and Recommendations:

67. Keeping in view the direction of the Hon'ble High Court, the mandate of AD rules and the Act, relevant submissions by various interested parties and facts available before the Authority to address the issues; the authority concludes as under:

- (i) The Domestic Industry was suffering injury during the entire injury analysis period even when no imports were coming from Saudi Arabia.
- (ii) Having evaluated the threat to Material Injury as directed by the Hon'ble High Court the Authority holds that in view of Post POI imports till August, 2018 the threat of material injury is not established.

- (iii) In view of the above, the recommendation of the authority in original finding that imports of Subject goods from Saudi Arabia did not conclusively establish a causal link between dumping and material injury also stands vindicated and is reiterated.
- (iv) The Authority holds that analysis and interpretation of both (ii) and (iii) above established that no injury to Domestic Industry due to imports from Saudi Arabia has been caused.
- (v) The Authority in view of the above does not consider it appropriate to recommend levy of an Anti-Dumping Duty on the subject goods from Saudi Arabia and hereby terminates this investigation in accordance with Rule 14 (b), Rule 17(1) (iii), Rule 11(2) and para (v) of Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority